चिंतन

वैश्विक व्यापार राजनीति में भारत की बड़ी आर्थिक जीत

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संपन्न होना भारत की आर्थिक कूटनीति की बड़ी सफलता है। यह समझौता करीब 18 वर्षों की लंबी, जटिल और कई बार की ठहरी हुई बातचीत के बाद हुआ है। यह केवल आयात-निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक भरोसेमंद, दीर्घकालिक साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह समझौता ऐसे समय में सामने आया है, जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था अस्थिरता, टैरिफ युद्ध और संरक्षणवादी नीतियों से जूझ रही है। अमेरिका सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे शुल्कों के बीच भारत और ईयू का यह करार खुले, नियम-आधारित और भरोसेमंद वैश्विक व्यापार का मजबूत संदेश देता है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि यूरोपीय संघ दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। दोनों मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 25 प्रतिशत, विश्व व्यापार का एक-तिहाई और दुनिया की करीब 30 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यह एफटीए स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में गिना जा रहा है। इससे भारत के श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर यूरोपीय संघ में लगने वाली ड्यूटी कम या समाप्त होने से भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन को गति मिलेगी और देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। साथ ही, आईटी और सेवा क्षेत्र को भी यूरोप में बेहतर बाजार पहुंच मिलने से भारत की सेवा अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इससे 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत 2047' जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को ठोस आधार मिलेगा और भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में उभरेगा। इसका गहरा रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व भी है। यूरोपीय संघ को भारत जैसा विशाल, युवा और तेजी से बढ़ता बाजार चाहिए, वहीं भारत को एक नियम-आधारित, तकनीकी रूप से उन्नत और राजनीतिक रूप से स्थिर साझेदार की आवश्यकता है। भारत ने डेयरी, अनाज, कृषि, फार्मिंग और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों को इससे बाहर रखकर अपने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा भी की है। वहीं, ईयू की लग्जरी कारों पर टैरिफ 110 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत और प्रीमियम शराब पर 150 प्रतिशत से 20 प्रतिशत होना भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगा, हालांकि इससे घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ेगा। इस एफटीए के 2027 में लागू होने की संभावना है, लेकिन असली चुनौती इसके प्रभावी और संतुलित क्रियान्वयन की होगी। गैर-शुल्क बाधाएं, यूरोपीय मानकों की कठोरता और छोटे व मध्यम उद्योगों की सीमित क्षमता जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस समझौते का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि एमएसएमई, स्टार्टअप्स और श्रमिक वर्ग भी इससे समान रूप से लाभान्वित हों। यदि इसे दूरदर्शिता, संतुलन और समावेशी नीतियों के साथ लागू किया गया, तो यह निस्संदेह भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की कवायद

भारत-ईयू एफटीए
विवेक शुक्ला

> भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जिसे कई बार रोक-टोक और बहस के बाद आज निर्णायक रूप से अंतिम रूप दिया गया है। आने वाले वर्षों में यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यदि इसे संतुलित और दूरदर्शी तरीके से लागू किया गया, तो यह न केवल दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक मॉडल प्रस्तुत करेगा। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मंगलवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसे दोनों पक्षों ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (सबसे बड़ी डील) के रूप में वर्णित किया है। यह समझौता लगभग 18 वर्षों से चली आ रही बातचीत का परिणाम है और इसे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जिसे कई बार रोक-टोक और बहस के बाद आज निर्णायक रूप से अंतिम रूप दिया गया है। इसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने की कवायद कहना अधिक तर्कसंगत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया है, जो आर्थिक समृद्धि, निवेश और साझेदारी की नई दिशा देगा। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने ज्यादातर वस्तुओं पर शुल्कों को कम या समाप्त करने का निर्णय लिया है, लगभग 96.6% उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा। भारतीय बाजार में यूरोपीय कारों पर शुल्क 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा।

शराब पर शुल्क में भारी कटौती होगी, जिससे ये वस्तुएं भारत में सस्ती होंगी। भारत को अपनी टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन और इंजीनियरिंग सामान को यूरोपीय बाजार में अधिक आसानी से निर्यात करने का मौका मिलेगा। इस समझौते में केवल व्यापारिक पहलू ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी को भी स्थान दिया गया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक सहयोग शामिल हैं। इससे यूरोपीय कंपनियों को भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते हुए बाजार में प्रत्यक्ष और आसान पहुंच होगी। वाहन, मशीनरी, वाइन और मोटर गाड़ियों जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में विस्तृत अवसर मिलेगा। यूरोप को वैश्विक व्यापार में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का लाभ। यह समझौता वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा, खासकर तब, जब अमेरिका और चीन जैसे बड़े आर्थिक संरचनाएं भी वैश्विक व्यापार नियमों और साझेदारियों में बदलाव ला रहे हैं। विशेष रूप से, अमेरिका द्वारा टैरिफ में वृद्धि और व्यापारिक दबाव के बीच, यह भारत और यूरोप के लिए एक विकल्प और समाधान के रूप में उभर रहा है। इससे विश्वव्यापी व्यापारिक जोखिमों से निपटने में मदद मिलेगी। यद्यपि समझौता आज घोषित हुआ है, इसे लागू होने के लिए अभी कुछ क़ानूनी प्रक्रियाएं और संसद/सम्मेलन की मंजूरी लेनी होगी। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे कृषि, पर अभी भी बहस जारी रहने की संभावनाएं हैं। विभिन्न उद्योगों को अनुकूल बनाने के लिए समय और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होगी। यह समझौता केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच गहरे, रणनीतिक, आर्थिक और साझेदारी के नए अध्याय का उद्घाटन है। यह न केवल दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, निवेश, तकनीकी सहयोग और बहुपक्षीय व्यापार ढांचे को भी मजबूती देगा। भविष्य में, इसके लाभ भारतीय उद्योगों, उपभोक्ताओं और निवेशकों को मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत को वैश्विक व्यापार का एक मजबूत

नेतृत्वकर्ता देश बनने का अवसर मिलेगा। यह समझौता केवल व्यापारिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और वैश्विक साझेदारी के नए आयामों को भी परिभाषित करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जब विश्व अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, भारत-यूरोप समझौता स्थिरता, विकास और सहयोग का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच सहयोग का इतिहास कई दशकों पुराना है। यूरोपीय संघ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार रहा है। हालांकि, व्यापक स्तर पर एक औपचारिक और संतुलित समझौते को अंतिम रूप देने में काफी समय लगा। इसके पीछे दोनों पक्षों के अपने-अपने आर्थिक हित, नीतिगत प्राथमिकताएं और संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं। यह समझौता लंबी बातचीत, आपसी विश्वास और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप सोच का परिणाम है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को सरल, पारदर्शी और अधिक लाभकारी बनाना है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीकी सहयोग को सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना शामिल है। साथ ही, यह समझौता दोनों क्षेत्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक-दूसरे का भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। समझौते के अंतर्गत दोनों पक्षों ने कई उत्पादों पर आयात-निर्यात शुल्क कम करने या समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, कृषि-आधारित उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान को इसका लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, यूरोपीय देशों के उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक उत्पाद, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, तकनीकी उपकरण और पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं भारतीय बाजार में अधिक सहजता से उपलब्ध होंगी। यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाक्षेत्र को भी समान महत्व देता है। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाओं में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय आईटी और सेवा कंपनियों को यूरोप में नए अवसर प्राप्त होंगे, जबकि यूरोपीय निवेशकों को भारत के तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र में निवेश का आकर्षक वातावरण मिलेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने पर भी बल दिया गया है। इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर लाभ होने की उम्मीद है।

सबसे पहले, निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी। दूसरा, घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा। तीसरा, नए निवेश और परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत जैसे युवा आबादी वाले देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह समझौता अनेक अवसर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगी। कुछ क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रारंभिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यदि इसे संतुलित और दूरदर्शी तरीके से लागू किया गया, तो यह न केवल दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक मॉडल प्रस्तुत करेगा। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

यूजीसी बिल

डॉ. घनश्याम बादल

सामाजिक न्याय या संवैधानिक असंतुलन

हाल में लागू किए गए यूजीसी के नए इक्विटी और शिकायत निवारण संबंधी प्रावधानों ने विश्वविद्यालय परिसरों से निकलकर सड़कों, दफ्तरों और सामाजिक चेतना तक को झकझोर दिया है। एक ओर दलित और पिछड़े वर्ग इन नियमों को लंबे समय से चली आ रही संस्थागत उपेक्षा के विरुद्ध सुरक्षा-कवच मान रहे हैं, तो दूसरी ओर सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें समानता के सिद्धांत के विरुद्ध और "उल्टे भेदभाव" की ओर ले जाने वाला मान रहा है। इस टकराव ने तब और तीखा रूप ले लिया, जब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री द्वारा सार्वजनिक असहमति और इस्तीफे और बाद में शासन द्वारा उन्हें निलंबित करके उनकी आवाज को दबाने के प्रयास ने इसे राष्ट्रीय बहस का रूप दे दिया। हालांकि, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि क्या एक सरकार के अधीन कार्य कर रहे उच्च अधिकारी को सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए? नियम अनुसार तो यह सरकारी कर्मचारियों के कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध ही जाता है और उन्हें निलंबित करने के पीछे सरकार की मंशा भी साफ है कि वह ऐसी हर आवाज को दबा देना चाहती है जो उसके अपने ही अधिकारी द्वारा उठाई जाए। यह विवाद केवल यूजीसी के किसी एक नियम का नहीं है, बल्कि उस संवैधानिक संतुलन का है, जिस पर भारत की सामाजिक संरचना टिकी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव, बहिष्कार, सूक्ष्म अपमान और अवसरों की असमानता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। छात्रावास, शोध निर्देशन, मूल्यांकन और यहां तक कि अनौपचारिक अकादमिक नेटवर्क हर जगह असमान शक्ति-संतुलन मौजूद है।

इस पृष्ठभूमि में इक्विटी सेल, विशेष शिकायत समितियां और संरक्षित प्रक्रिया दलित-पिछड़े वर्गों को राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन प्रतीत होती हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए विशेष प्रावधान करे। इस वर्ग का तर्क है कि समानता तब तक खोखली है, जब तक असमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को बराबर करने के लिए अतिरिक्त सहारा न दिया जाए। उनके लिए यह बहस "समान अवसर" बनाम "विशेष अवसर" की नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की है। वहीं इस संदर्भ में सवर्ण समाज की चिंता को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस यूजीसी बिल के आने से उसके मन में आशंका और असुरक्षा की भावना घर कर रही लगती है, लेकिन इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही वास्तविक है। सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि नए यूजीसी नियमों में शिकायत तंत्र की संरचना ऐसी है, जिसमें पूर्वाग्रह की आशंका निहित है। अस्पष्ट परिभाषाएं, एकतरफा प्रतिनिधित्व और प्रारंभिक जांच के बिना कार्रवाई की संभावना, ये सभी घटक भय का वातावरण पैदा करते हैं। अब यहां जानना होगा कि आखिर इस प्रतिवाद के पीछे असली प्रश्न क्या है? न्याय या असंतुलन? इस पूरे विवाद का प्रश्न यह नहीं है कि सामाजिक न्याय चाहिए या नहीं, इस पर लगभग सर्वसम्मति है। असली प्रश्न यह है कि सामाजिक न्याय को लागू करते समय संवैधानिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह बात हम सबको ध्यान में रखनी होगी कि संविधान न तो प्रतिशोध का दस्तावेज है और न ही किसी वर्ग विशेष की स्थायी ढाल। वह सुधारात्मक न्याय की अनुमति तो देता है, लेकिन बदले में नैसर्गिक न्याय, निष्पक्ष प्रक्रिया और समान गरिमा की भी मांग करता है। यह भी जानना श्रेयस्कर होगा कि इस संघर्ष और ऊहापोह के बीच आगे का रास्ता क्या हो। यूजीसी और सरकार के लिए यह समय आत्ममंथन का है, इसलिए आवश्यक है कि शिकायत तंत्र सभी वर्गों के लिए समान रूप से सुलभ और संतुलित हो।

प्रारंभिक जांच, समयबद्ध प्रक्रिया और अपील की स्पष्ट व्यवस्था हो, अकादमिक स्वतंत्रता और वैचारिक बहस को संरक्षित किया जाए, तथा राज्यों, शिक्षकों और छात्रों से व्यापक परामर्श हो। दूसरी कड़वी सच्चाई यह भी है कि राजनीति लगभग हर क्षेत्र में अपना हित ढूंढने लगती हैं। यूजीसी के नए नियमों पर छिड़ी बहस रेखांकित करती है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो संतुलन, विवेक और संवाद से चलता है। सवर्ण, दलित और पिछड़े तीनों की चिंताएं वास्तविक हैं और तीनों की उपेक्षा लोकतंत्र को कमजोर करेगी। आवश्यकता है कि नीति भावना नहीं, बल्कि संवैधानिक विवेक से चलें, क्योंकि अंततः विश्वविद्यालय किसी एक वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शांति से सभी दुखों को खत्म किया जा सकता है

संकलित
दर्शन

हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान शांति दे सकता है, यह एक काल्पनिक विचार है। हम स्वयं शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक रख सकते हैं। शांति एक मानवीय गुण तो है ही, लेकिन यह आत्मिक शक्ति है। शांति सभी सुखों की मूल है। इससे सभी वैभव एवं ऐश्वर्य की पूर्ति संभव है। शांति द्वारा सभी दुखों का शमन किया जा सकता है। इससे हर रोग का निदान होता है। शांति का माध्यम सभी समस्याओं का समाधान तैयार करता है। शांति ही देश का निर्माण करती है, वहीं अशांति से देश का पतन आरंभ होता है। शांति और अशांति के बीच समाज, समुदाय, वर्ग, कौम, जाति और संस्थाएं गतिहीन हो जाती हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य है। शांति एक शब्द मात्र नहीं है। शांति को मन मंदिर में बसाने वाले लोग देव तुल्य होते हैं। इसलिए स्वयं भी शांति के प्रहरी बनिए और दूसरों को भी शांति दूत बनाइए। यही संसार के मंगल का भेद है। शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। परिवार में शांति एक वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में आनंद की अनुभूति पाई जा सकती है। अशांति कालांतर में अग्नि के समान जीवन के हर अंग को भस्म कर देती है। मानवता का मूल इसी शांति के गर्भ में स्थिर है। यदि जीवन को सुख और वैभव से संपन्न करना हो तो निश्चित ही शांति की पूजा करनी होगी। देश में जन सामान्य को शांति के सूत्र अपनाने चाहिए।

ब्रह्माजी को दंड देने के लिए प्रकट हुए थे कालभैरव

संकलित
प्रेरणा

शिवजी के 19 अवतारों में से एक है कालभैरव। भैरव अवतार से जुड़ी कई अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं में ब्रह्माजी को दंड देने के लिए शिवजी के क्रोध से कालभैरव प्रकट हुए थे। कालभैरव की उत्पत्ति से जुड़ी सृष्टि की शुरुआत के समय की बहुत प्रचलित कथा है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बन गई। उस समय शिवलिंग प्रकट हुआ और शिव जी ने इन दोनों का विवाद शांत किया। उसी समय वहां एक विशाल पुरुष की आकृति प्रकट हुई। ये आकृति शिवजी का ही एक रूप थी। शिव जी ने उससे कहा कि तुम काल के समान हो और भीषण हो। इसी वजह से तुम्हारा नाम कालभैरव होगा। पंचमुखी ब्रह्मा जी बार-बार खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कालभैरव ने ब्रह्माजी का एक सिर काट दिया था। इस घटना के बाद से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। शिव जी ने कालभैरव को काशी का नगरपाल बना दिया। कालभैरव की पत्नी भैरवी देवी पार्वती की अवतार हैं। कालभैरव की पूजा में शराब (मदिरा), तामसिक खाना खासतौर पर चढ़ाया जाता है। दरअसल, कालभैरव हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले देवता हैं। इनकी पूजा करते समय भक्त नशे की चीजें चढ़ाकर अपनी बुराइयां छोड़ने का संकल्प लेता है। जो लोग इस संकल्प को निभाते हैं, उन्हें भैरव की विशेष कृपा मिलती है।

अंतर्मन

आज की पाती

गणतंत्र के 77 वर्ष

भारत का गणतंत्र 77 वर्ष का हो चुका है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने एक नए भारत की नींव रखी, जो स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों से प्रेरित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की- साहित्य, खेल, कृषि, विज्ञान-प्रौद्योगिकी से लेकर आर्थिक-सैन्य क्षमता तक। विविध संस्कृति को मजबूत करते हुए राष्ट्र ने वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाई। चंद्रयान मिशनों से अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बने, यूपीआई जैसी डिजिटल क्रांति ने भुगतान व्यवस्था बदल दी, जबकि ओलंपिक-एशियाड में पदकों की बौछार ने खेलक्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुईं। आज विश्व भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है, जहां विकास दर ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया।

- दीपक वर्मा, सरायपाली

ट्रेंड

सीखने के अवसर

किसी भी शोध संगठन की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग होते हैं। आपके वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन ही आपकी वास्तविक शक्ति हैं। उन्हें सीखने के अवसर देने होंगे, नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके विचारों को सुना जाएगा।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

मुक्त व्यापार समझौता

आज भारत ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न किया है। आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन, यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है।

- पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग मंत्री

पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति

सिर्फ राष्ट्रपति भवन में ही नहीं, जब राहुल गांधी असम आए, तब भी उन्होंने गमोछा पहनने से इनकार किया। गांधी परिवार के लिए असम और पूर्वी उत्तर भारत की संस्कृति कोई मायने नही रखती।

-हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

स्वास्थ्य सर्वोपरि

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि है। अक्सर बच्चे तनाव और अवसाद के साथ-साथ ऑटिज्म जैसी स्थितियों से भी जूझ रहे होते हैं, जिसे सामान्यतः माता-पिता और शिक्षक भी समय पर पहचान नही पाते।

-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

सिंगापुर में भारत सहित 8 विदेशी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता

सिंगापुर में डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्र अब भारत के 'मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन' सहित आठ और विदेशी संस्थानों में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। सिंगापुर ने उम्रदराज होती आबादी के कारण डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंगापुर चिकित्सा परिषद ने संयुक्त बयान में कहा कि नयी मंजूरी प्राप्त ये संस्थान सिंगापुर को उम्रदराज़ होती जनसंख्या के बीच डॉक्टरों की बढ़ती जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेंगे। इन आठ विश्वविद्यालयों को शामिल किए जाने के साथ ही एक फरवरी 2026 तक सिंगापुर में मान्यता प्राप्त विदेशी मेडिकल स्कूलों की संख्या 112 से बढ़कर 120 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि उसने चिकित्सा पंजीकरण अधिनियम, 1997 की दूसरी अनुसूची में आठ मेडिकल स्कूलों को जोड़ने संबंधी एसएमसी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मणिपाल के अलावा जिन विश्वविद्यालयों को सूची में शामिल किया गया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड विश्वविद्यालय, आयरलैंड का यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, मलेशिया का यूनिवर्सिटी सैन्स मलेशिया, पाकिस्तान का आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, चीन का त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय, ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और ब्रिटेन का ही सिटी सेंट जॉर्ज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शामिल हैं।

ऑफ बीट

समुद्र में कहां से आते हैं सीप कई जीव भी बनाते हैं कंकाल

सीप बस जीवों के कंकाल ही हैं। लेकिन इंसानों और अधिकतर दूसरे पशुओं से अलग, इन घोंघों, क्लैम, ऑयस्टर और मसेल्स में एक एक्सोस्केलेटन होता है, जिसका मतलब है कि यह उनके शरीर के बाहर होता है। जब सीपियों की बात होती है, तो उनका मतलब आमतौर पर घोंघों जैसे जीवों के बाहरी खोल यानी शेल से होता है। कई दूसरे समुद्री जीव भी कंकाल बनाते हैं, जिनमें सैंड डॉलर जैसे इकाइनोइड्स शामिल हैं जो अंदरूनी कंकाल बनाते हैं। ये समुद्री जीव अपने नरम शरीर को बाहरी खतरों, जैसे शिकारियों या उनके रहने की जगह में होने वाले बदलावों से बचाने के लिए अपने शेल खुद बनाते हैं। शेल इन समुद्री जीवों को समुद्र तल पर स्थिर रहने, बड़ा होने या ज़्यादा अच्छे से घूमने में भी मदद कर सकते हैं। इस बाहरी आवरण या शेल बनाने की प्रक्रिया को 'बायोमिनरलाइजेशन' कहते हैं। समुद्री जानवर शेल कैसे बनाते हैं, यह अलग-अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन इन सभी जानवरों के शेल बनाने के लिए खास ऊतक होते हैं। अधिकतर समुद्री जीव अपने शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं, जो एक मजबूत मिनरल है और लाइमस्टोन में भी पाया जाता है। कुछ स्पंज और सूक्ष्मजीव एक और पदार्थ सिलिका का इस्तेमाल करते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

ऊर्जा का अपव्यय ही अवनति की ओर ले जाता है

आर्थिक सहयोग का नया युग

अंततः भारत और यूरोपीय संघ के बीच सभी समझौतों की जननी कहा जाने वाला मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हो गया। इस समझौते का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह दुनिया की एक चौथाई आबादी वाले भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। इसका महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इसने अपना आर्थिक दबदबा कायम करने की कोशिश करने वाले अमेरिका और चीन को यह संदेश दिया है कि उनका विकल्प उपलब्ध है। इस संदेश की पुष्टि अमेरिकी नेताओं के उन बयानों से होती है, जिनसे यह ध्वनित हो रहा है कि उन्हें यह समझौता रास नहीं आया। आश्चर्य नहीं कि अमेरिका इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करे। वास्तव में टैरिफ के मामले में अमेरिका के मनमाने रवैये ने ही इस समझौते की राह आसान की। इस समझौते का एक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यूरोपीय संघ और भारत दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 25 प्रतिशत के बराबर हैं और जो वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा हैं। स्पष्ट है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग दोनों पक्षों को व्यापार और निवेश के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा। यह अवसर आर्थिक समृद्धि को बल प्रदान करने के साथ रोजगार की समस्या को भी दूर करेगा। इस समझौते से जहां यूरोपीय कारों, वाइन, मशीनरी, रसायन, स्टील आदि पर भारतीय आयात शुल्क में भारी कटौती होगी, वहीं भारतीय वस्त्र, रत्न, औषधि आदि के लिए यूरोपीय बाजार में पहुंच आसान होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों को यूरोप में नए अवसर मिलेंगे।

चूंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच का एफटीए दोनों के लिए लाभकारी है, इसीलिए उत्साह का माहौल है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इस समझौते का यूरोपीय संसद और परिषद से अनुमोदन चाहिए होगा। इसमें जो समय लगेगा, उसका सदुपयोग इस एफटीए का अधिकतम लाभ उठाने की तैयारी में खपाना चाहिए। यह तैयारी भारतीय उद्यमियों को विशेष रूप से करनी होगी। उन्हें अपने को साबित करने का जो अवसर मिलने जा रहा है, उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें गुणवत्ता और उत्पादकता का स्तर उन्नत करते हुए ऐसे मूल्यवान विश्वस्तरीय उत्पाद तैयार करने होंगे, जिनकी विशिष्ट पहचान बने और इसके चलते उनकी मांग बढ़े। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय उत्पाद अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए कम ही जाने जाते हैं। भारतीय उद्यमियों को अपने उत्पादों का निर्माण विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप करने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इससे ही आपसी व्यापार का पलड़ा भारत के पक्ष में बना रह सकता है।

इच्छाशक्ति जरूरी

यमुना में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नालों की सफाई का काम किया जाना स्वागतयोग्य है। दिल्ली सरकार ने इन 22 में से 21 नालों से गाद निकालकर इन्हें साफ करने के लिए इस साल के अंत तक का लक्ष्य रखा है। वहीं आकार बड़ा होने के कारण नजफगढ़ नाले की सफाई में कुछ अधिक समय लगने की संभावना है। यमुना में जाने वाली कुल गंदगी का 70 प्रतिशत इसी ड्रेन से जाता है और निराशाजनक यह है कि इस ड्रेन की विगत 30 वर्षों से सफाई नहीं हुई है। इसकी सफाई का कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ और अब तक करीब नौ लाख टन गाद निकाली जा चुकी है।

> यमुना को निर्मल बनाने के लिए दिल्ली सरकार को नए सिरे से योजनाएं बनाकर कार्य करना चाहिए

राजधानी में यमुना को प्रदूषणमुक्त करने को लेकर तीन दशक से अधिक समय से काम हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि करोड़ों रुपये पानी में बह जाने के बावजूद अब तक यमुना साफ नहीं हो सकी है। पिछले साल दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद इसे लेकर नए सिरे से काम शुरू हुआ है। लेकिन यह आवश्यक है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए पूर्व में बनाई गई योजनाओं और अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा कर नए सिरे से योजना बनाकर कार्य किया जाए। ये सही है कि यमुना रातोंरात साफ नहीं हो सकती, लेकिन सही दिशा में पूरी इच्छाशक्ति के साथ काम किया जाए तो इस जीवनदायिनी नदी को निश्चित तौर पर स्वच्छ किया जा सकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विश्व कप से पहले सैंजू सैमसन की खराब फार्म भारत के लिए चिंता का विषय है?

आज का सवाल

क्या यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहायक होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुधारों की गति बढ़ाए बजट

तरुण गुप्त

सतही या क्रमिक सुधारों का समय बीत चुका है। अब निर्णायक और मूलभूत परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे

हर साल फरवरी में आने वाले बजट को एक ऐसे राष्ट्रीय पथप्रदर्शक के रूप में देखा जाता है, जिसके माध्यम से देश की ढांचागत समस्याओं के समाधान की आस जुड़ी होती है। हालांकि वास्तविकता यह है कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन चुनौतियां विकराल। केंद्रीय वित्त मंत्री के हाथों में जहां करीब 50 लाख करोड़ रुपये के खर्च का बहीखाता होता है, वहीं केंद्र और राज्यों का सम्मिलित सालाना व्यय करीब 100 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाता है। यह भारी-भरकम राशि भी हमारी जीडीपी के 30 प्रतिशत से भी कम है। जबकि विकसित देशों में यह सालाना खर्च उनकी जीडीपी का 40 से 50 प्रतिशत तक होता है। हमारी विशालकाय जनसंख्या को देखते हुए प्रति व्यक्ति पैमाने के संदर्भ में विकसित देशों और हमारे बीच अंतर की यह खाई और चौड़ी हो जाती है।

खर्च की राशि और मात्रा से इतर उसकी गुणवत्ता को समझना भी महत्वपूर्ण है। हमारे कुल व्यय का करीब 25 प्रतिशत ब्याज भुगतान में खर्च हो जाता है, जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह स्तर 10 प्रतिशत से कम है। हमारे संदर्भ में ब्याज पर भारी भुगतान का कारण जीडीपी अनुपात में कर्ज के ऊंचे स्तर से अधिक अपेक्षाकृत कमजोर क्रेडिट रेटिंग के चलते मिलने वाला महंगा कर्ज अधिक जिम्मेदार है। ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसे खर्च की प्रतिबद्ध मद ही हमारे 60 प्रतिशत संसाधनों को सोख लेती हैं और ऐसी स्थिति में बुनियादी ढांचे से जुड़े परिसंपत्ति निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक संकेतकों और रक्षा पर खर्च करने के लिए मात्र 40 प्रतिशत संसाधन शेष रह जाते हैं।

बजट की प्रक्रिया में अपर्याप्त व्यय आवंटन के जरिये एक खराब शुरुआत होती है। कम प्रति व्यक्ति खर्च स्थिति को और बिगाड़ देता है। तिस पर कमजोर क्रियान्वयन हमारी परेशानियों और कई गुना बढ़ा देता है। परिणामस्वरूप विकास के मोर्चे पर कई विसंगतियां सामने आती हैं, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दूर करने में असमर्थ रहे हैं। चूंकि केंद्र सरकार ही सर्वाधिक राजस्व जुटाती है और खर्च करती है तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाओं का बोझ भी उसे ही उठाना पड़ता है। अधिक खर्च करने के लिए वित्त मंत्री को ज्यादा आय की व्यवस्था करनी होगी। पिछले वर्ष प्रत्यक्ष करों के स्तर पर रियायत, वित्तीय वर्ष के मध्य में ही जीएसटी दरों में कटौती और विभिन्न व्यापार समझौतों के अस्तित्व में आने से सीमा शुल्क में संकुचन के बाद अब राजस्व बढ़ाने के लिए नई राह की ओर देखना होगा।

हमारा टैक्स-जीडीपी अनुपात लगभग 12 प्रतिशत है, जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह 35 से 45 प्रतिशत के दायरे में होता है। भारत में आयकर चुकाने वाली आबादी दो से तीन प्रतिशत के बीच है, जो विकसित देशों में 45 से 55 प्रतिशत तक होती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण कृषि आय को कर से छूट दिया जाना है। कृषि से जुड़े हमारे लगभग 40 प्रतिशत अंशधारी कर देनदारी के दायरे से बाहर हैं। इसलिए समृद्ध कृषकों को आयकर के दायरे में लाना होगा। इसके लिए या तो एक निश्चित स्तर से ऊपर की आय अथवा कृषि भूमि आकार को आधार बना सकते हैं। यह राजनीतिक रूप से आज भले ही आत्मघाती प्रतीत हो, परंतु यह वह विचार है, जिसे आकार देने का समय अब आ चुका है।

विनिवेश को लेकर भी हम क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। दिग्गज सार्वजनिक उपक्रमों का समग्र बाजार पूंजीकरण लगभग 40 लाख करोड़ रुपये है। निजीकरण की बात न भी करें तो सरकार बहुलांश हिस्सेदारी अपने पास रखते हुए भी कुछ हिस्सेदारी बेचकर काफी राजस्व जुटाने में सक्षम हो सकती है। भूमि का मुद्रीकरण भी अपार संभावनाओं से भरा अवसर है। चूंकि सरकार के हिस्से में ही सबसे अधिक जमीन है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगी पड़ा है, तो उसका प्रभावी उपयोग भी व्यापक राजस्व की राह खोल सकता है।

अवधेश राजपूत

प्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाना सदैव प्राथमिकता में होना चाहिए। लाभांश पर प्राप्तकर्ता के हाथों सीमांत दरों पर कर लगाना दोहरे कराधान का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसे सुधार की सख्त आवश्यकता है। वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती बढ़ाना और आवासीय ऋण के ब्याज पर कटौती की सीमा में वृद्धि करना उपयुक्त होगा। ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन हमारी नीतियों के केंद्र में होना चाहिए। कतिपय दबावों में अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण एवं छापेमारी के माध्यम से उत्पीड़न समाजवादी दौर की एक अवशेष प्रवृत्ति ही है। इसे समाप्त किया जाए। विवादों, मुकदमों और रिफंड के त्वरित निपटान की एक प्रभावी प्रणाली आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो चली है। हमारी मंशा एक सीमित वर्ग से कर वसूली के बजाय करों के दायरे का विस्तार करने की होनी चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कोई समाज तभी कर अनुपालन के प्रति अधिक उन्मुख होता है, जब उसे यह विश्वास हो कि राज्य के संसाधनों का उपयोग जनसेवा में हो रहा है, न कि राजनीतिक-प्रशासनिक अभिजात वर्ग की विलासिता पर।

हमें यह भी समझना होगा कि केंद्रीय बजट एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है और केंद्र सरकार केवल राह दिखा सकती है, लेकिन राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता के बिना कोई आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं है। जीवन की सुगमता और मानव विकास सूचकांक, कारोबारी सुगमता के लिए अनिवार्य शर्तें होती हैं। वैसे भी केंद्रीय बजट की अपनी सीमा है और वह अकेले ही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। एक ऐसे दौर में जब सत्तारूढ़ व्यवस्था देश के लगभग दो-तिहाई हिस्से में प्रभावी है, तब 'डबल-इंजन' को चुनावी नारे से आगे बढ़कर शासन की वास्तविकता में बदलना होगा। मानव विकास सूचकांकों और जीवन की सुगमता से मापे जाने वाले अपेक्षित आमूलचूल परिवर्तन के लिए राज्यों को केंद्र की राजकोषीय मंशा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।

हमें अनुपयोगी भूमि के सार्थक उपयोग, समृद्ध कृषकों को आयकर के दायरे में लाने, सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी संभावनाओं को भुनाने, पारस्परिक लाभकारी व्यापार समझौतों को मूर्त रूप देने और एक सुविचारित एवं संतुलित व्यापार नीति लागू करने के बीच संतुलन साधना होगा। तभी हम अपने विकास-घाटे को पाटने की आशा कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत की कार्यान्वयन क्षमता उसकी आकांक्षाओं जितनी ही तीव्र एवं प्रभावी होनी चाहिए। सतही या क्रमिक सुधारों का समय बीत चुका है। अब निर्णायक और मूलभूत परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।

(लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं)

response@jagran.com

सबसे बड़ा और प्रभावी व्यापार समझौता

जयंतीलाल भंडारी

ईयू के साथ एफटीए निर्यात बढ़ाने के साथ मेक इन इंडिया अभियान को भी गति देने वाला साबित होगा

आखिरकार नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन की उपस्थिति में भारत-ईयू के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का एलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। उर्सुला ने भी इस समझौते को सभी 'मदर आफ आल डील्स' कहते हुए यह रेखांकित किया कि दुनिया के वर्तमान 'ग्रोथ सेंटर' और इस सदी के आर्थिक पावर हाउस भारत के साथ यह एफटीए यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में पहली बढ़त दिलाएगा। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा और यह संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। इस एफटीए ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बीच भारत और ईयू को नई रणनीतिक गोलबंदी के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दी है।

भारत-ईयू एफटीए के लिए बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह वार्ता थम गई। जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू की गई, जो अब अंजाम तक पहुंची है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों वैल्यू चेन के अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। भारत प्रमुखतः श्रम-प्रधान और प्रसंस्करण आधारित वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि यूरोपीय संघ मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं, उन्नत प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति करता है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और 27 देशों के संगठन ईयू के बीच वस्तुओं और सेवाओं में कुल व्यापार 190 अरब डालर से अधिक का रहा। इसी वित्त वर्ष में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डालर रहा। इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डालर और आयात 60.68 अरब डालर था। यूरोपीय संघ भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक

बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते ने खोली नई राहें ● फाइल

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) करीब 117.4 अरब डालर रहा। इस एफटीए से भारत और यूरोपीय संघ के छात्रों, कामगारों, शोधकर्ताओं और उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक गतिशील ढांचे को आकार मिला है। यह एफटीए भारत-ईयू व्यापार के लिए महज एक व्यापार का रणनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आर्थिक पुनर्व्यवस्था के रूप में भारत और ईयू के लिए बदलते वैश्विक व्यापार वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देने वाला पड़ाव है।

इस एफटीए के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क शुरुआत से ही कम या समाप्त कर देंगे, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह एफटीए व्यापार, निवेश, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रक्षा, डिजिटल पहलों, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों में आपसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और नियमों पर केंद्रित है, लेकिन निवेश संरक्षण जैसे मुद्दे अलग से सुलझाए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक मुख्य स्तंभ है, जिसे संस्थागत ढांचे का समर्थन प्राप्त है और इससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अंतरिक्ष सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक और महत्वपूर्ण आयाम है, जो दशकों के तकनीकी सहयोग पर आधारित है। जहां यह एफटीए क्लीन टेक्नोलाजी, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे खास सेक्टर में जरूरी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, वहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी, आतंकवाद से निपटने और साइबर-डिफेंस में सहयोग भी बढ़ाएगा।

भारत के लिए ईयू के साथ एफटीए निर्यात और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ भारत के घरेलू बाजार को बढ़ाने, मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा। इसके जरिये भारत जहां अपने कपड़ा, चमड़ा और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा सकेगा, वहीं भारतीय पेशेवरों और आइटी सेवाओं के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के दरवाजे खुलेंगे और भारतीय श्रमिकों की यूरोप में सक्रियता बढ़ेगी। यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण से भारत के साथ एफटीए एक उभरती आर्थिकी के साथ उसका पहला समझौता है। इससे यूरोपीय संघ की निर्भरता चीन पर घटेगी। साथ ही उसे भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिकी में भी लाभ मिलेंगे। जहां शुल्क कटौती से कारों, मशीनरी, एयरक्राफ्ट और केमिकल के क्षेत्र में मौके खुलेंगे, वहीं सबसे तेजी से बढ़ते भारत के बड़े बाजार में सेवाओं, खरीद, निवेश तक ईयू देशों की पहुंच बेहतर होगी।

ईयू के साथ एफटीए भारत के निर्यात और निवेश के साथ विकास दर बढ़ाने में अहम होगा। देशों के साथ एफटीए के अधिकतम लाभ उठाने के लिए भारत को घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, सेवा क्षेत्र का लाभ उठाने, निर्यात में विविधता लाने, कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने, व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में लाने के साथ-साथ पर्यावरण और श्रम मानकों के परिपालन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आभामंडल

हर मनुष्य का अपना एक आभामंडल होता है। आभामंडल रूपी अदृश्य ऊर्जा हमारे आसपास के परिवेश को भी प्रभावित करती है। इसे विभिन्न रंगों के प्रकाश के रूप में देखा जा सकता है, जो सकरात्मकता और नकरात्मकता के साथ घटता-बढ़ता रहता है। देवी-देवताओं और महापुरुषों के चित्रों में उनके शरीर के चारों ओर जो प्रकाश का घेरा दिखाया जाता है, वह उनके आभामंडल का ही प्रतीक होता है। आभामंडल भी प्रायः चार प्रकार का होता है। शारीरिक, जो हमारे शरीर से निकलता है। भावनात्मक, जो हमारी भावनाओं से प्रकट होता है। मानसिक, जो हमारे विचारों से सृजित होता है। आध्यात्मिक, जो आत्मा से प्रस्फुटित होता है।

हम स्वयं अनुभव कर देख सकते हैं कि जहां कुछ लोगों से मिलकर हमे आत्मिक शांति और प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा के भंडार होते हैं। वहीं कुछ लोगों के संपर्क मे आने पर मन असहजता अनुभव कर उनसे शीघ्र छुटकारा पाने को उन्मुख होता है, क्योंकि उनमें अत्यधिक नकारात्मकता भरी होती है। यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग प्रकृति लिए होता है।

अदृश्य ऊर्जा परत के रूप मे फैला होने से आभामंडल और उसकी विकृति को न देखा जा सकता है न समय रहते सुधारा जा सकता है। अलबत्ता मानसिक रूप से अधिक से अधिक ईश्वरीय भक्ति में संलग्न रहकर तथा सकारात्मक बने रहकर अपने आभामंडल को और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान-साधना और योग सबसे प्रभावी उपाय हैं। इसलिए जहां तक संभव हो अपनी मानसिक स्थिति को शांत, सुस्थिर और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आभामंडल की प्रभा और प्रभावी होती है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

दूर हों संदेह

'यूजीसी के नए नियम' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। हमें इस मुद्दे पर समग्रता में विचार करना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में समान अवसर केंद्रों के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी शिकायत का अधिकार देना एक सकारात्मक पहल है। इससे यह संदेश जाता है कि शिक्षा परिसरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है। हालांकि, इन नियमों में भेदभाव की स्पष्ट और ठोस परिभाषा का अभाव चिंता का विषय है। अस्पष्ट प्रविधानों के कारण झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिससे संस्थानों का अकादमिक परिवेश प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, झूठी शिकायत करने वालों के लिए दंडात्मक प्रविधानों का न होना भी नियमों की प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े करता है। आवश्यक है कि यूजीसी इन नियमों में स्पष्टता, संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करे, ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिल सके और साथ ही शिक्षा संस्थान अनावश्यक विवादों से मुक्त रहकर अपने मूल उद्देश्य शिक्षा और शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के संकेत दिए हैं। इस समिति को सभी आशंकाएं दूर करने के उपाय करने चाहिए।

himanshushekhar.mca@gmail.com

सामाजिक न्याय की चुनौती

विश्वविद्यालय केवल डिग्री नहीं देते वहां समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्य आकार लेते हैं। देश में यह सवाल हमेशा से प्रासंगिक रहा है कि क्या हमारे शैक्षणिक परिसरों में सभी छात्रों को समान सम्मान और अवसर मिल पाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए नए नियम 'प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 सामने आए हैं। इसका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को रोकना और वंचित वर्गों को संरक्षण देना बताया गया है। लेकिन देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। सरकार और यूजीसी का तर्क यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की घटनाएं कोई कल्पना नहीं हैं। बीते एक दशक में सामने आई कुछ दर्दनाक घटनाओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। रोहित वेमुला व पायल तडवी जैसे मामलों ने यह सवाल उठाया कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नियमों को सख्त करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसका मकसद जवाबदेही तय करना था। इस दृष्टि से हर कालेज में ईक्वल अपार्च्युनिटी सेंटर, इक्वलिटी कमेटी और निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि नियमों की भाषा और संरचना असंतुलित है। भेदभाव की परिभाषा में केवल कुछ वर्गों को पीड़ित के रूप में चिह्नित किया गया है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

एफटीए से निर्यात में होगी वृद्धि

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हरी झंडी मिलना वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। इसी कारण इसे 'मदर आफ आल डील्स' कहा जा रहा है। यह समझौता केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, तकनीक, सेवाओं, सप्लाई चेन, बौद्धिक संपदा और सतत विकास जैसे अनेक आयामों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद हाउस में यूरोपीय नेतृत्व के साथ साझा प्रेस वार्ता में इस समझौते को साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया गया। वह इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम गढ़ने वाला देश बन रहा है। इस एफटीए से भारतीय किसानों को यूरोप जैसे उच्च क्रय-शक्ति वाले बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी वहीं एमएसएमई सेक्टर को टैरिफ और नान-टैरिफ बाधाओं में कमी का सीधा लाभ मिलेगा। जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने का काम करेगा। सर्विस सेक्टर विशेषकर आइटी, फिनटेक, हेल्थकेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज में भारतीय प्रतिभाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे।

विभूति बुपक्या, दिल्ली विश्वविद्यालय

X पोस्ट

जाति-आधारित भेदभाव केवल आरक्षित वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

इन दिनों कुछ सरकारी अधिकारी अलग-अलग कारणों से त्यागपत्र दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कम ही सुनने को मिलता है कि किसी ने कैंसर की तरह सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से तंग आकर इस्तीफा दिया हो?

राजीव रंजन@rajeevranjanMKH

एक ओर भारत रूस से लेकर चीन तक से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है तो यूरोप को भी उसी तरह से साधने में सफल हो रहा है। आज के दौर में रणनीतिक स्वायत्तता सिखाने के मामले में भारत सबसे बढ़िया उदाहरण है।

वेलिना@vtchakarova

यूरोप ने भारत के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता कर ही लिया है। जल्द ही कनाडा भी इस दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा और संभव है कि दक्षिण कोरिया का नाम भी इसमें शामिल हो जाए।

एम. दंडपाणी@dmuthuk

जनपथ

यूजीसी के एक्ट पर है मच रही गुहार,
क्यों सवर्ण पर ही सदा गिरती है तलवार?
गिरती है तलवार यही आसान निशाना,
दिखला दो 'ससुराल' ढूंढकर कोई बहाना!
कालेज को कह बाय कटा लें अपना टीसी,
कर इतना भयभीत रहा है ये यूजीसी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए, डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 194

बजट को अंतिम रूप देने में इन सात महारथियों ने दिया वित्त मंत्री का साथ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार नौवें बजट को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें वित्त मंत्रालय में नौकरशाहों की एक अनुभवी टीम ने उनकी मदद की है। वित्त मंत्री 7.4 प्रतिशत विकास दर और अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल के बीच एक फरवरी को लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। आइए जानते हैं कि 2026-27 के बजट की तैयारियों में कौन-कौन से प्रमुख अधिकारी शामिल रहे हैं...

बजट की मुख्य सूत्रधार। विभाग की प्रमुख होने के नाते संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक फ्रेमवर्क तय करने वाली मुख्य अधिकारी हैं। यह उनका पहला बजट है। हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आइएएस अधिकारी ठाकुर ने एक जुलाई, 2025 को इस विभाग की कमान संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि वह इस विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला आइएएस अधिकारी हैं। **-अनुराधा ठाकुर**, आर्थिक मामलों की सचिव

बजट भाषण के भाग-बी यानी टैक्स प्रस्तावों के लिए जिम्मेदार। इनकी टीम प्रत्यक्ष कर (आयकर, कारपोरेट कर) और अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा शुल्क) को संभालती है। राजस्व सचिव के तौर पर यह उनका पहला बजट है। लेकिन श्रीवास्तव वित्त मंत्रालय में अपने पिछले कार्यकाल में बजट डिवीजन में संयुक्त सचिव थे। सीमा शुल्क और टीडीएस के युक्तिकरण की उम्मीदों के साथ राजस्व जुटाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। **-अरविंद श्रीवास्तव**, राजस्व सचिव

खजाने के संरक्षक के तौर पर यह सरकार के खर्च, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की देखरेख करते हैं। उनका विभाग राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने और अगले वित्त वर्ष के लिए मार्गदर्शन देने के लिए वित्तीय अनुशासन लागू करता है। उनका विभाग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की गहन जांच करता है। **-वुमलुनमांग वुअलनाम**, व्यय सचिव

वित्तीय सेवा विभाग सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने में शामिल है। उनका विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणाली की वित्तीय सेहत की देखरेख करता है। यह विभाग सरकार के आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल अपनाने और सामाजिक सुरक्षा पहल शामिल हैं। **-एम नागराजू**, वित्तीय सेवा सचिव

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सरकार के विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन रोडमैप के लिए जिम्मेदार है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) में हिस्सेदारी बेचकर मिलने वाले गैर-कर राजस्व लक्ष्य को प्रबंधित करते हैं। इस विभाग का उद्देश्य गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से बाहर निकलना और रणनीतिक क्षेत्रों में सुधार करना है। यह 2004 से वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। **अरुणीश चावला**, दीपम सचिव

इस विभाग के प्रमुख के तौर पर यह चुनिंदा सीपीएसई के पूंजीगत खर्च की योजनाओं के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करते है कि बजट आवंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। उनके विभाग की भूमिका एसेट मोनेटाइजेशन और सरकारी कंपनियों की कुल वित्तीय सेहत की निगरानी में भी है। यह विभाग मुख्य रूप से आर्थिक विकास में सरकारी कंपनियों की भूमिका को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। **-के. मोसेस चलाई**, सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव

उनका कार्यालय महत्वपूर्ण इनपुट देता है जो बजट के लिए एक व्यापक आर्थिक संदर्भ को परिभाषित करते हैं। इसमें आर्थिक विकास का पूर्वानुमान लगाना, सेक्टरवार प्रदर्शन (कृषि, उद्योग, सेवाएं) का विश्लेषण करना और वैश्विक जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इसके अलावा, उनका ऑफिस वित्त मंत्री को प्रमुख आर्थिक सुधारों, राजकोषीय नीति और वित्तीय रणनीति पर भी सलाह देता है। **-वी अनंत नागेश्वरन**, मुख्य आर्थिक सलाहकार

बिजनेस डेस्क

वित्त मंत्री ने हलवा समारोह में लिया हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पारंपरिक 'हलवा' समारोह में भाग लिया। यह वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय के नए परिसर कर्तव्य भवन-1 में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने के कारण हलवा समारोह का आयोजन रायसीना हिल पर स्थित नार्थ ब्लाक में किया गया। यह वित्त मंत्रालय का पुराना पता है। वित्त मंत्री और उनकी अधिकांश टीम को सितंबर 2025 में नार्थ ब्लाक से आधुनिक केंद्रीय सचिवालय कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। यह समारोह एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें पारंपरिक मिठाई 'हलवा' तैयार की जाती है और बजट की तैयारी में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसी जाती है। 'हलवा समारोह' उन अधिकारियों के 'लाक-इन' से पहले होता है जो केंद्रीय बजट की तैयारी में शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही बजट टीम को शुभकामनाएं दीं।

निर्मला सीतारमण

एक नजर में

वोडाफोन आइडिया को 5,286 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली: कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को बताया कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में उसका कुल घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का कुल घाटा 6,609 करोड़ रुपये था। बीती तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व बढ़कर 11,323 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 11,117 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 में कंपनी का प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) 7.3 प्रतिशत बढ़कर 186 रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 173 रुपये था। कंपनी पर कुल 2.09 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। (प्रेट्र)

2027 तक 20 अरब डालर होगा प्लास्टिक निर्यात

नई दिल्ली: प्लास्टिक उद्योग की शीर्ष संस्था प्लास्टइंडिया फाउंडेशन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2030 तक भारत के प्लास्टिक उद्योग का आकार 44.5 अरब डालर हो जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2027 के अंत तक भारत का प्लास्टिक निर्यात दोगुना होकर 20 अरब डालर पर पहुंच गया है। 2025 में प्लास्टिक निर्यात 10 अरब डालर और उद्योग का आकार 26.5 अरब डालर रहा है। फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रविश कामथ ने कहा कि उद्योग में पैकेजिंग की ही 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो मार्डन कामर्स में इसके महत्व को दर्शाता है। (आइएएनएस)

प्यूमा की 29% हिस्सेदारी खरीदेगी चीन की एंटा स्पोर्ट्स

बेंगलुरु: चीन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर कंपनी एंटा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स ने मंगलवार को कहा कि वह पिनाल्ट परिवार से प्यूमा में 29.06 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीदेगी। यह हिस्सेदारी 1.5 अरब यूरो में खरीदी जाएगी। इसके साथ एंटा स्पोर्ट्स जर्मनी की स्पोर्ट्सवियर निर्माता में सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। एंटा ने कहा कि वह संघर्ष कर रही प्यूमा को आकर्षक चीनी बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगा। इस घोषणा के बाद प्यूमा के शेयरों में 17 प्रतिशत तक का उछाल दर्ज किया गया। (रायटर)

एक दिन में 40,500 रुपये किलो बढ़ी चांदी

दिल्ली में 3.70 लाख रुपये किलो हुआ सफेद धातु का मूल्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: चांदी की कीमतों में रिकार्ड तोड़ तेजी का सिलसिला जारी है। अकेले मंगलवार को यह सफेद धातु 40,500 रुपये या 12.3 प्रतिशत बढ़कर 3,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह धातु 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। सोना भी 7,300 रुपये या 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह पीली धातु 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। सोमवार को सराफा बाजार बंद रहे थे।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों की मजबूतत मांग और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और के बीच ग्लोबल तेजी का असर दोनों कीमती धातु पर दिखाई पड़ रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, 'बढ़ते व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के चलते घरेलू बाजार में चांदी 3,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है।' उन्होंने कहा कि चांदी को निवेश प्रवाह के साथ-साथ मजबूत औद्योगिक मांग का भी फायदा मिल रहा है। लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने कहा, ''निकट भविष्य में चांदी की कीमतों में मुनाफावसूली और समेकन देखने को मिल सकता है। हालांकि, जब तक डालर पर दबाव बना रहता है, तब तक सकारात्मक रुझान बना रहेगा।' कैलेंडर वर्ष 2026 की बात करें तो अब तक (1-27 जनवरी) चांदी में 1.31 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी का मूल्य 2.39 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब 3.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी प्रकार, सोने के मूल्य में जनवरी में अब तक 28,300 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने का मूल्य 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1.66 लाख रुपये प्रति दस ग्राम हो चुका है। कैलेंडर वर्ष 2025 में चांदी 1,48,500 रुपये किलो और सोना 58,310 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ा था।

7,300 रुपये बढ़कर 1.66 लाख रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंचा सोना

1.31 लाख रुपये किलो महंगी हो चुकी है सफेद धातु इस साल में अब तक

28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है सोने का मूल्य 2026 में

नए भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर डालर की वजह से विदेशी बाजार में हाजिर सोना करीब 5,080 डालर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देने के नए कदम ने बाजार को हिला दिया है और बुलियन की मांग को मजबूत किया है। **-प्रवीण सिंह**, रिसर्च एनालिस्ट, मिराए एसेट शेयरखान

ईयू से समझौते के चलते भारतीय कार कंपनियों के शेयर लुढ़के

नई दिल्ली, प्रेट्र: यूरोपीय यूनियन से लक्जरी कारों का आयात सस्ता होने से मंगलवार को कार बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई के शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल, भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से यूरोप से आयात होकर आने वाली कारों पर शुल्क कम हो जाएगा। इससे देश में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फाक्सवैगन के कारों की कीमत घट जाएगी। कंपनियों का मानना है कि इससे उनके उत्पादन पर असर पड़ेगा।

मारुति के स्टाक में 1.48 प्रतिशत, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के स्टाक में 1.22 प्रतिशत, एमआरएफ के स्टाक में 1.20 प्रतिशत, हीरो मोटोकार्प के स्टॉक में 0.24 प्रतिशत और अशोक लेलैंड के स्टाक में 0.05 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का आटो इंडेक्स 0.97 प्रतिशत गिरकर 58,980.72 पर आ गया। शेयर बाजार की बात करें तो मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत चढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर बंद हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि भारत के आटो सेक्टर में ज्यादातर छोटी कारों (10-25 लाख) का दबदबा है और उसमें ईयू की दिलचस्पी बहुत ज्यादा नहीं है। 25 लाख रुपये से कम की गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड माडल शामिल हैं। 25 लाख से ऊपर, भारत का बाजार सीमित है, लेकिन इस क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन की दिलचस्पी ज्यादा है, क्योंकि वे इस सेगमेंट में अच्छे मैन्यूफैक्चरर हैं। अधिकारी ने कहा, 'इसका ध्यान रखते हुए, हमने उन्हें कोटा-आधारित बाजार पहुंच दिया है।'

महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई के शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट, सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ

एथनाल मिश्रण से 19 अरब डालर की विदेशी मुद्रा बची

गोवा, एएनआइ: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा कि एक दशक में भारत को एथनाल मिश्रण से 19.30 अरब डालर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और इस दौरान किसानों को 15 अरब डालर का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। गोवा में चौथे इंडिया एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुरी ने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के लिए ऊर्जा बदलाव को आर्थिक सुरक्षा के साथ संतुलित करने की भारत की रणनीति के बारे में खुलकर चर्चा की।

मंत्री ने कहा कि बायोएनर्जी में बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के हिस्से के तौर पर भारत अपने कम्प्रेस्ड बायोगैस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि जहां नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल बिजली उत्पादन के पांचवें हिस्से से बढ़कर एक तिहाई हो गई है। वहीं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परंपरागत एनर्जी अभी भी जरूरी है। यह बात ठीक है कि नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन परंपरागत एनर्जी जरूरी बनी रहेगी। देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर बात करते हुए पुरी ने कहा, ''2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत का हिस्सा लगभग 30-35% बढ़ने का अनुमान है, जो कुल वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग 10 प्रतिशत हो जाएगा।' इसे पूरा करने के लिए सरकार ऊर्जा क्षमता को बढ़ा रही है, जिसमें 2047 तक नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना शामिल है।

भारत को 145 अरब डालर का सालाना निवेश करना होगा: वुड मैकेंजी ने मंगलवार को कहा कि भारत को लगातार आर्थिक विकास के साथ अपने कार्बन जीरो के लक्ष्य के अंतर को कम करना है तो अपने एनर्जी सेक्टर में लगभग 145 अरब डालर का सालाना निवेश करना होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में बोलते हुए, वुड मैकेंजी में एशिया पैसिफिक के वाइस चेयरमैन, जोशुआ न्गु ने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और डी-कार्बनाजेशन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इस तरह के निवेश को रणनीतिक रूप से बिजली उत्पादन, एनर्जी स्टोरेज और तुरंत ग्रिड उन्नयन पर ध्यान देना चाहिए।

भारत वैश्विक ऊर्जा विकास के केंद्र में: कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उद्योग मंत्री सुल्तान अहमद अल जाबेर ने मंगलवार को कहा कि भारत, उभरते बाजारों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव की वजह से ऊर्जा मांग वृद्धि के केंद्र में है। अगले 15 सालों में, भारत में हवाई यात्रा 150 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

हरदीप सिंह पुरी

- पेट्रोलियम मंत्री ने कहा-एक दशक में किसानों को 15 अरब डालर का प्रत्यक्ष भुगतान
- 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत का हिस्सा 30-35% तक बढ़ने का अनुमान

भारत के एनर्जी सेक्टर में 500 अरब डालर के निवेश अवसर : मोदी

गोवा, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के एनर्जी सेक्टर में 500 अरब डालर के निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि देश सुधारों को तेज कर रहा है और देश ऊर्जा सुरक्षा से ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इंडिया एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि बड़े सुधारों और तेल और गैस खोजने और बनाने के लिए 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खोलने के बाद दशक के आखिर तक अपस्ट्रीम सेक्टर में 100 अरब डालर के निवेश का लक्ष्य है जबकि डाउनस्ट्रीम में देश दुनिया का सबसे बड़ा आयल रिफाइनिंग हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा दोगुना से ज्यादा 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य एलएनजी और पाइपलाइन में निवेश के मौके पैदा करेगा।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

2032 तक होने लगेगा तीन नैनोमीटर की चिप का निर्माण

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2032 तक तीन नैनोमीटर नोड के हाईटेक छोटे चिप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इन चिप का इस्तेमाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर में होता है। वैष्णव ने कहा कि सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण के तहत चिप की छह श्रेणियों (कंप्यूटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नेटवर्किंग, पावर, सेंसर और मेमोरी) पर फोकस करेगी, जिससे देश की कंपनियों को 70-75 प्रतिशत टेक्नोलाजी प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत चुनी गई 24 चिप डिजाइन फर्मों के साथ बैठक के बाद कहा कि 2032 का हमें तीन नैनोमीटर चिप मैन्यूफैक्चरिंग और डिजाइन का लक्ष्य हासिल करना है। यह बात ठीक है कि इस तरह के चिप की डिजाइन हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह की चिप की मैन्युफैक्चरिंग भी देश में करनी होगी। वैष्णव ने कहा कि सरकार छह बड़े सिस्टम पर फोकस करना चाहती है, जिससे हम अपने पूरे सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। इससे भारत में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूसरे चरण की प्रोत्साहन योजना में छह श्रेणियों पर होगा सरकार का फोकस

अब भारत में भी बनेंगे वाणिज्यिक विमान

नई दिल्ली, प्रेट्र: अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने एक रणनीतिक सहयोग की मंगलवार को घोषणा की। इसका मकसद भारत में एक क्षेत्रीय विमान मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करना है। एम्ब्रेयर 150 सीट तक के कामर्शियल विमान बनाती है। इस समझौते के तहत निवेश और प्रस्तावित मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र के स्थल की जानकारी नहीं दी गई है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। यह साझेदारी छोटे व मझोले शहरों के लिए हवाई संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में भारत में क्षेत्रीय परिवहन विमानों पर रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) भी स्थापित करेंगी। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सहयोग केवल क्षेत्रीय विमानों के संयोजन तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रगतिशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और भारत को क्षेत्रीय विमानों का एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बनाना भी शामिल है। इस साझेदारी के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र में पहले से ही मजबूत उपस्थिति रखने वाला अदाणी समूह, भारत में विमान विनिर्माण के क्षेत्र में कदम रख रहा है। 'अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' के निदेशक जीत अदाणी ने जीत अदाणी ने कहा कि विनिर्माण सुविधा के लिए कुछ स्थलों की तलाश की जा रही है और अगले कुछ महीनों में इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। एम्ब्रेयर के ई-जेट ने 2005 में भारत में परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में इसके पास देश में करीब 50 विमान हैं जो भारतीय वायु सेना, सरकारी एजेंसियों, वाणिज्य विमान संचालकों और वाणिज्यिक विमानन कंपनी 'स्टार एयर' की सेवा में हैं। एम्ब्रेयर ने 21 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि अगले 20 वर्ष में भारतीय बाजार को 80 से 146 सीट के कम से कम 500 विमान की आवश्यकता होने का अनुमान है।

- अदाणी समूह ने ब्राजील की विमान निर्माता एम्ब्रेयर के साथ किया रणनीतिक समझौता
- समझौते के तहत देश में 150 सीट तक के वाणिज्यिक विमानों का किया जाएगा निर्माण

'लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए अब शपथ पत्र अनिवार्य'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी अपराध का आरोप लगाता है, तो ऐसी शिकायत के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार और झूठे आरोपों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस द्वारा सभी हाईकोर्ट को भेजे गए एक पुराने संचार का हवाला दिया। इसमें जोर दिया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे शपथ पत्र द्वारा समर्थित न हों। कोर्ट ने तर्क दिया कि जब न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की सत्यता के लिए शपथ पत्र आवश्यक है, तो लोक सेवकों के मामले में भी यही आवश्यकता होनी चाहिए। पीठ ने कहा, ''शपथ पत्र के आग्रह के संबंध में भेदभाव करने का कोई तर्कसंगत आधार नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर किसी भी आवेदन को मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है, यदि आरोप पूरी तरह से निराधार है। हालांकि, पीठ ने सचेत किया कि ऐसी शिकायतों को खारिज करने का आदेश मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ठोस और वैध कारण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। यह मामला एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़ा था।

- जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनाया अहम निर्णय
- भ्रष्टाचार और झूठे आरोपों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया जारी, जांच रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली, प्रेट्र: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी है। सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

गौरतलब है कि जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तब 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए जब अग्निशमन दल पहुंचा तो उसे वहां एक स्टोर रूम में भारी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। रिजीजू ने कहा, प्रक्रिया के अनुसार सदन की सहमति से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति को मामला भेज दिया गया है। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं।

नकली बीज बेचने पर 30 लाख रुपये तक जुर्माना और जेल

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : केंद्र सरकार बजट सत्र में लगभग सात दशक पुराने सीड एक्ट को बदलकर ऐसी आधुनिक और सख्त व्यवस्था लाने जा रही है, जिसमें गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा गया है। नए कानून के तहत हर बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण किसी भी बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। जानबूझकर घटिया बीज बेचने वालों को तीन वर्ष तक की जेल और 30 लाख रुपये तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल विधायी परामर्श के लिए विधेयक को सार्वजनिक किया गया है और किसान संगठनों एवं हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

1966 में बना मौजूदा सीड एक्ट उस दौर का कानून था, जब न डिजिटल निगरानी की व्यवस्था थी और न ही बाजार इतना जटिल था। दोषियों पर सिर्फ पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रविधान था। नतीजा हुआ कि नकली बीज बेचने जैसे गंभीर अपराध पर भी कार्रवाई के नाम पर मामूली जुर्माना भरकर बच निकलने की प्रवृत्ति बनी रही। इसी कमजोरी को दूर करते हुए सरकार ऐसे कानून की ओर बढ़ रही है, जिसमें बीज आपूर्ति की पूरी श्रृंखला को जवाबदेह बनाया जाएगा।

नए सीड बिल की सबसे बड़ी खासियत बीजों की ट्रेसिबिलिटी व्यवस्था है। बाजार में बिकने वाले हर बीज का डिजिटल रिकार्ड होगा। पैकेट पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्केन करते ही पता चल सकेगा कि इसका उत्पादन कहां हुआ, किस इकाई में प्रसंस्कृत हुआ और किस विक्रेता के माध्यम से किसान तक पहुंचा। बीज कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और पौधों के नर्सरियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे किसानों को भी भरोसा मिलेगा कि वे अधिकृत स्रोत से बीज खरीद रहे हैं।

- बिना पंजीकरण बीज बेचने की नहीं होगी अनुमति
- इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा नया विधेयक

वीआइपी दर्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआइपी दर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय के निर्णय लेने का विषय नहीं है कि मंदिर में कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं। ये निर्देश मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन व जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने मप्र हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल दर्पण अवस्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। कोर्ट ने सक्षम अथारिटी को ज्ञापन देने की छूट दे दी है।

दूषित पेयजल मामले की होगी न्यायिक जांच, आयोग का गठन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 29 मौतों और 3300 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले की अब न्यायिक जांच की जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को चार सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले में अगली सुनवाई पांच मार्च 2026 को होगी। दरअसल, भागीरथपुरा दूषित जल मामले में पांच जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार देर शाम जारी हुआ। हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग से जांच करवाना आवश्यक है, ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने जिला प्रशासन, नगर निगम, पीएचई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच में पूरा सहयोग देने और आवश्यक रिकार्ड व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यह आयोग भागीरथपुरा में पानी के दूषित होने के कारण, मृतकों की वास्तविक संख्या, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निगम के दावों सहित अन्य बिंदुओं पर जांच करेगा।

बच्चों को फटे पन्नों पर परोसा दिया गया मिड-डे मील

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर : गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश में मैहर जिले के शासकीय हाई स्कूल भटिगंवा में बच्चों को मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) थाली या डिस्पोजेबल पत्तल के स्थान पर रद्दी कापियों और किताबों के फटे पन्नों पर परोस दिया गया। विवशता में बच्चों ने उसी स्थिति में भोजन किया। ऐसा तब किया गया, जब स्कूलों में मिड-डे मील परोसने के लिए बाकायदा थाली की व्यवस्था है। मामले का वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद कलेक्टर ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी को निलंबित करने और ब्लाक संसाधन समन्वयक प्रदीप सिंह का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जिला पंचायत के मिड-डे मील प्रभारी और जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस दिया है। प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की संस्तुति रीवा संभाग आयुक्त से की गई है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

शिमला का जाम

संस्कृत से लेकर तमाम समकालीन भारतीय भाषाओं में ऐसी लोकोक्तियां हैं कि पर्यटन करने से आदमी के ज्ञानचक्षु खुलते हैं, उसकी समझ का दायरा बड़ा होता है। ऐसा लगता है, हम हिन्दुस्तानी आजकल ऐसी सारी लोकोक्तियों को झुठलाने पर तुले हैं। हमारे देश में लगातार पर्यटन का विस्तार हो रहा है, पर समझ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से मनाली में अभूतपूर्व जाम लगा है और बाकी पर्यटन स्थलों की हालत भी बहुत बुरी है। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है, तो स्वाभाविक ही था कि वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। ऐसे में, हजारों लोग अपने-अपने वाहन लेकर बर्फबारी देखने पहुंच गए और कुछ घंटों का नहीं, दिनों का जाम लग गया। जो लोग बर्फ में सड़क पर अपनी गाड़ियों में बंद पड़े हुए हैं, उनकी तकलीफों से सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पर्यटन स्थलों पर ऐसी भगदड़ मचाना कोई समझदारी का काम है?

हमारे ज्यादातर पहाड़ी पर्यटन स्थल अंग्रेजी राज में विकसित हुए कस्बे हैं, जब देश की जनसंख्या आज से चौथाई थी। पहाड़ों में सड़कों की चौड़ाई की सीमा होती है और कस्बों या शहरों के विस्तार की भी। अब पर्यटन के व्यावसायिक दबाव में सड़कें खतरनाक ढंग से चौड़ी की जा रही हैं, जिनसे भूस्खलन हो रहे हैं। खूबसूरत कस्बों और छोटे शहरों में महानगरों की तरह बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनसे उनका चरित्र ही नष्ट हो गया है। उनमें स्थानीय वास्तुशिल्प नहीं मिलता। इसके बावजूद हरेक पर्यटन स्थल में घुसने के पहले ही जाम का सामना करना पड़ता है। मनाली का जाम कुछ असाधारण है, लेकिन देश के हरेक पर्यटन स्थल पर कुछ न कुछ जाम होना जैसे अनिवार्य हो गया है। पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य रोजमर्रा की भागदौड़ से निकलकर प्रकृति के सान्निध्य में शांति और राहत के कुछ क्षण बिताना होता है। ऐसा लगता है, हमारे यहां पर्यटन एक भागदौड़ और आपाधापी से निकलकर उससे भी बड़ी आपाधापी में शामिल होने की प्रक्रिया है। समस्या यह भी है कि हमारे पर्यटक भी इससे विचलित नहीं होते, बल्कि वे पर्यटन स्थलों पर जाकर शोर और गंदगी में इजाफा करते चलते हैं। आम भारतीय पर्यटक के व्यवहार में स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता वैसी नहीं है, जैसी कि अपेक्षा की जाती है। हमने पर्यटन को तो जोर-शोर से अपना लिया है, लेकिन पर्यटन की संस्कृति नहीं सीखी है। इसलिए हम न सिर्फ अपने पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

भारत का पर्यटन अराजकता के जिस जाम में फंसा हुआ है, उससे निकलने के लिए अगर संजीदगी से कोशिश नहीं की गई, तो यह जाम और बड़ा होता जाएगा।

इसमें दोष सभी का है। सरकारें पर्यटन से होने वाली आय तो चाहती हैं, लेकिन उसे सुव्यवस्थित और संवेदनशील तरीके से विकसित करने पर ध्यान नहीं देतीं। अनाप-शनाप व्यवसायीकरण भले तुरंत लाभ दे दे, लेकिन आखिरकार वह पर्यावरण और समाज, दोनों के लिए बुरा है। भारत शताब्दियों से दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि छोटे-छोटे देशों में भारत से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं और फिर भी उनके पर्यटन स्थलों की सुंदरता व शांति बनी रहती है। इसी तरह, भारत के आम पर्यटकों को भी भेड़ियाधसान की प्रवृत्ति से बाहर आकर ज्यादा संवेदनशीलता और परिपक्वता सीखने की जरूरत है। भारत का पर्यटन अराजकता और लापरवाही के जिस जाम में फंसा हुआ है, उससे निकलने के लिए अगर संजीदगी से कोशिश नहीं की गई, तो यह जाम और बड़ा होता जाएगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 जनवरी, 1951

मित्रता की कसौटी

'धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपद काल परिखिए चारी', तुलसीदासजी की यह उक्ति सांसारिक व्यवहार के अनुशीलन पर आधारित है।

विपत्ति के समय ही वास्तव में मित्रता के खरे खोटेपन को परखा जा सकता है। सुख के समय मित्रों का जमघट लग जाता है, किन्तु जब दुःख का समय आता है, तो मित्र मंडली बहुधा काफूर हो जाती है। सुख के समय मित्र वर्ग आपके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की दुहाई देगा, किन्तु संकट उपस्थित होते ही वह मुंह फेर लेगा और पास फटकने का नाम भी न लेगा। किन्तु सच्चा मित्र वही है, जो ठकुर सुहाती नहीं कहता, बल्कि प्रसंग आने पर मित्र को कड़वी बात कहने में भी नहीं हिचकता। उसे अपनी भूल सुझाता है और बुरा बनने की जोखिम उठाकर भी उसको गलत राह पर जाने से रोकने की कोशिश करता है। सच्चा मित्र संकट के समय मित्र का कभी साथ नहीं छोड़ता और उसकी सहायता करने में सब से आगे रहता है। व्यक्तिगत व्यवहार में और राष्ट्रों के आपसी संबंधों में मित्रता की यही कसौटी लागू होती है। जो मित्रता इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उसे निरर्थक ही समझना चाहिए।

भारत को इस समय तीव्र रूप में खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ और भूकम्प आदि दैवी प्रकोपों के कारण इस वर्ष उसे 60 लाख टन अन्न की कमी पड़ेगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस संकट का कैसे मुकाबला किया जाये, यह उसकी चिंता का प्रधान विषय है। वह अन्न की कमी को पूरा करने के लिये हर तरह से प्रयत्नशील है। वह अन्न की खपत को घटा रहा है। उसने राशन की मात्रा घटा दी है। देश के भीतर अन्न की उपज बढ़ाने और अनाज का संग्रह करने की कोशिश कर रहा है। वह विदेशों से भी अन्न का अधिक से अधिक आयात करने की फिक्र में है। स्वभावतः उसने अपने मित्र देशों से, जो उसकी अन्न की आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में है, अन्न की याचना की है। ऐसे देशों में अमेरिका भी एक है। अमेरिका से भारत ने अनुरोध किया है कि इस समय यदि वह 20 लाख टन अनाज दे देगा, तो भारत को इस संकट में से पार होने में बड़ी सहायता मिलेगी। भारत को अन्न की बेहद आवश्यकता है और अमेरिका के पास अनाज की कोई कमी नहीं है।

दुनिया में भारत का कद बढ़ाता करार

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

यहां स्कैन करें

भारत और यूरोपीय संघ का यह समझौता कितना पुरअसर है, इसका अंदाज इसी से लग जाता है कि समझौते पर मुहर लगने के पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री के सुर बदलने लगे।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक तो है ही, वक्त की जरूरत भी है। वैसे भी, हर अंतरराष्ट्रीय समझौता अपनी तात्कालिक अनिवार्यताओं और भविष्य की संभावनाओं से प्रेरित होता है। दरअसल, यूरोप और भारत, दोनों को इस समय एक-दूसरे की बहुत जरूरत है। अमेरिका ने दोनों को ही दबाने की कोशिश की है। हमसे ज्यादा प्रतिकूल, बल्कि एकतरफा शर्तें उसने यूरोपीय संघ पर थोपी हैं।

अमेरिका ने यूरोपीय संघ के उत्पादों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क तो लगाया ही, इसके साथ यह शर्त भी नत्थी कर दी है कि यूरोपीय संघ अमेरिकी उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। यही नहीं, अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर का निवेश करने को भी कहा गया है। ग्रीनलैंड के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर जैसा दबाव बनाया है, वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में, स्वाभाविक ही यूरोप के देश वाशिंगटन से बेहद नाराज हैं। इधर, भारत भी ट्रंप प्रशासन की कारगुजारियों से खुश नहीं है। यूरोप के देश भारत के विशाल बाजार और आर्थिक भविष्य की अहमियत समझते हैं। इसलिए दोनों ने एक-दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया है।

भारत और यूरोपीय संघ का यह समझौता कितना पुरअसर है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस करार पर मुहर लगने के पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत देना शुरू कर दिया कि भारत पर लगा अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क हटाया जा सकता है। बेसेंट ने इसके लिए रूस से भारत द्वारा तेल आयात में कटौती की आड़ ली। हालांकि, इस समझौते को लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ की संसद से पारित होने के बाद सभी 27 देश अपनी-अपनी संसद में इसे पारित करेंगे। शायद इसीलिए इसे अगले साल से लागू होने की बात कही गई है, मगर इसका तात्कालिक राजनीतिक फायदा यही हो सकता है कि अमेरिका अतिवादी रुख अपनाने से बाज आ जाए।

पिछले करीब 18 वर्षों से भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत थे, मगर जिन कारणों से अमेरिका से बात नहीं बन पा रही थी, वही वजह यूरोपीय संघ के साथ हमारे समझौते में भी अड़चन बनी हुई थी। अमेरिका की तरह यूरोप के देश भी हमारे कृषि बाजार तक अपनी निर्बाध पहुंच चाहते रहे हैं, मगर यह मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। करार से ज्यादातर कृषि उत्पादों को अलग रखा गया है, लेकिन कुछ कृषि उत्पादों पर हमने अपने टैरिफ में कटौती करने का जो एलान किया है, उससे हमको कुछ नुकसान हो सकता है। इसी तरह, स्टील और कार्बन उत्सर्जन के सवाल पर हमें जितनी रियायत की अपेक्षा थी, वह नहीं मिल सकी, मगर अंतरराष्ट्रीय समझौतों में लेन-देन स्वाभाविक बात है।

अब समझौता हो चुका है और व्यापक तौर पर देखें, तो लाभ दोनों पक्षों को होने वाला है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा भी है कि इस समझौते के लागू होने के बाद लगभग 43.5 हजार करोड़ रुपये के टैरिफ कम हो जाएंगे। इस समझौते से हमारी 90 फीसदी से अधिक चीजें शून्य टैक्स के साथ यूरोपीय देशों में बिक सकेंगी। अमेरिकी टैरिफ से भारत के जिन कारोबारी क्षेत्रों को धक्का लगा था, उनको इस समझौते से यकीनन बड़ी राहत मिली है। खासकर कपड़ा, चमड़ा, मछली, आभूषण कारोबार आदि से जुड़े व्यापार को बड़ा फायदा होने वाला है। इन सामानों पर अभी जो अलग-अलग शुल्क लगते रहे हैं, वे शून्य हो जाएंगे। इसका बड़ा लाभ यह भी है कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है। यूरोप के नजरिये से देखें, तो जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को इसका अधिक फायदा होगा, क्योंकि ये देश ऑटोमोबाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देश हैं।

विश्व-व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी शर्तें ही होती हैं। प्रायः तकनीकी रूप से मजबूत देश तीसरी दुनिया के देशों को दबाते आए हैं। 'डब्ल्यूटीओ' या उसके पहले 'गैट' में यही होता रहा है। चूंकि उन्नत तकनीकी के मामलों में उनका दबदबा होता है, इसका वे फायदा उठाते हैं, इसका अंतिम नुकसान गरीब देशों के कामगारों को होता है। अमीर देशों में उपभोक्ताओं को चीजें चूंकि सस्ती मिलती हैं, इसलिए उनके यहां महंगाई नियंत्रित रहती है। इसीलिए संतुलित व्यापार सबके हित का माना जाता है। इस लिहाज से भारत-यूरोपीय संघ समझौते की शर्तें संतुलित हैं।

हालांकि, हमें यहां यह भी देखने की जरूरत है कि अब तक हमने जिन-जिन देशों के साथ व्यापार समझौता किया है, उनका निर्यात तो बढ़ गया, लेकिन हमारा उतना नहीं बढ़ा। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि हमारे पास उनके जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस लिहाज से इस समझौते से हमें मदद मिल सकती है। हमारे बच्चों को यूरोप के संस्थानों में जाकर पढ़ने का अवसर मिलेगा। भारतीय आईटी क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा। वहां उनके लिए काम करने की स्थितियां आसान होंगी। भारत और यूरोप की आबादी को जोड़ लें, तो यह दुनिया की दो अरब से अधिक आबादी हो जाती है। अगर इसमें अफ्रीका के देश भी जुड़ गए, तो अमेरिका विहीन शेष दुनिया की ओर कदम बढ़ जाएगा। इसलिए इस समझौते को इतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।

इसमें तो कोई दोराय नहीं हो सकती कि इस समझौते से दुनिया में भारत का कद और बड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि अमेरिका इससे क्या सबक लेता है और वह दुनिया को क्या 'ऑफर' करता है? उसने दस प्रतिशत का न्यूनतम टैरिफ तो सब पर लगा ही दिया है, उसके ऊपर ही वह बढ़ाता जा रहा था। अगर दुनिया के बड़े देश इसी तरह मिलकर आपस में व्यापार बढ़ाते हैं, तभी संतुलन आ सकेगा और अमेरिकी दबाव शिथिल पड़ेगा।

चूंकि यूरोप लोकतंत्र का बड़ा हिमायती रहा है, इसलिए भारत को यूरोप के साथ कदमताल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह समझौता अन्य देशों को भी भारत के साथ मुक्त व्यापार के लिए प्रेरित करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सांसद निधि की तुलना दूसरी योजनाओं से नहीं हो सकती

राकेश सिन्हा | पूर्व सदस्य, राज्यसभा

यहां स्कैन करें

सांसद स्थानीय विकास निधि को लेकर इन दिनों एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कुछ सांसदों के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने इस मद का एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इसी आधार पर कई लोग दलील दे रहे हैं कि इस योजना को ही खत्म कर देना जाना चाहिए, मगर सच यह है कि इसकी ऐसी उपयोगिता है, जिसकी विकास की अन्य योजना निधियों से तुलना नहीं की जा सकती।

इसे व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसका कारण है। देश की आधारभूत संरचनाओं में प्रगति अब ठोस यथार्थ बन चुकी है। सड़क, पानी, बिजली, नाली, सीवर आदि जो कल तक स्थानीय लोगों की ज्वलंत समस्याएं हुआ करती थीं और लोग उसके समाधान की अपेक्षा सांसद-विधायक विकास निधि से रखते थे, वह बात अब प्रायः नहीं रही। पंचायत से लेकर जिले तक का बजट पिछले दस वर्षों में कई गुना बढ़ा है।

यहां एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है। दुनिया के सभी पदों के पास घोषित शक्तियां होती हैं और पद के अनुपात में उनका विशेषाधिकार रहता है, परंतु सांसद के पास शक्ति शून्य है। वह जनता की वैधानिक ताकत से प्रतिनिधि बनता है, जनता के जीवन के सभी आयामों से उसका सरोकार होता है। अतः सांसद की ताकत विशेषाधिकार के गर्भ से उपजता है। सांसद निधि इसी विशेषधिकार को रेखांकित करता है।

विकास योजनाओं के मांग आधारित आवंटन से सांसद निधि का सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अंकुरित नहीं हो पाता है।

इसके उपयोग में जितनी प्रयोगधर्मिता होगी, परिणाम उतने ही प्रभावी होंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे-से मुहल्ले (टोला) में सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये के लोग रहते हैं। युवाओं से संवाद में पुस्तकालय-निर्माण की मांग उठी। इसकी घोषणा करके राशि आवंटित कर देना एक मिनट का काम था। मैंने ऐसा नहीं किया। घंटों अनौपचारिक संवाद चलता रहा। उसी सिलसिले में टोले का जातिसूचक नाम बदलने पर राय बनी। नया नाम तय हुआ- हनुमान-शिव टोला। मैंने पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण है। एक पुस्तकालय पीढ़ियों की सोच के निर्माण का पवित्र स्थल है, जहां अध्ययन, चिंतन, सृजन और संकल्प निर्माण होता है। पुस्तकालय भौतिकता, अनैतिकता, संकीर्णता आदि से उत्पन्न आपदाओं से समाज को बचाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, खेल के प्रति उन्होंने युवाओं में उत्साह बढ़ाया है। खेल में भी सुनहरा करियर है, गांव-कस्बों तक यह संदेश गया है। अतः खेल-सुविधाओं की भी मांग अब सांसदों से होने लगी है। चाहे निर्माण या विकास का रूप जो भी हो, इसमें बहुआयामी संवाद का जरिया बनने की असीम क्षमता है। सांसद निधि के साथ नैतिकता का आयाम लगते ही उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। एक तरफ, निर्माण कार्य होता है, दूसरी तरफ संकीर्णता की दीवार ढहने लगती है। सूची बनाकर विकास योजनाओं को जारी करना या मांग के आधार पर आवंटन की अपनी उपयोगिता है, पर वे जिलाधिकारी की योजना की तरह हो जाती हैं। उससे सांसद निधि का सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अंकुरित भी नहीं हो पाता है।

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में कोंगथोंग गांव को मैंने 2020 में गोद लिया था। सेंगखासी (जनजाति) का स्कूल सरकारी सहायता से वंचित था। सहायता देने से पूर्व लोगों के सामूहिक श्रमदान, स्वच्छता अभियान आदि पर संवाद होते रहे। ऐसे में, सांसद निधि स्कूल के विकास से अधिक वहां सामूहिकता के भाव को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गई। श्रमदान द्वारा निधि का उपयोग हुआ। सुखद बात यह रही कि ईसाई और सेंगखासी समुदायों के बीच चली आ रही कटुता मिट गई।

हमारे लोकतंत्र में एक कमी है, सांसदों के कार्यकलापों, विशेषकर सांसद निधि के उपयोग का सोशल ऑडिटिंग न होना। यह 'सब धान बाईस पसेरी' कर देता है। सोशल ऑडिटिंग से उनकी कमियों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ जनादेश नहीं है। इसकी बुनियाद में नैतिक व्यवस्था है। इसलिए सांसद निधि का उपयोग रचनात्मक तरीके से होना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आत्म-छल से बचिए

क्या यह छानबीन करना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप और मैं एक ऐसी दुनिया में, जहां मैं और आप कुछ भी नहीं हैं, सहयोग कर सकते हैं, संवाद में हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं? क्या हम औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि सही मायने में वास्तविक सहयोग कर सकते हैं?

यह हमारी जटिलतम समस्याओं में से एक है, संभवतः सर्वाधिक जटिल। मैं किसी लक्ष्य के साथ अपना तादात्म्य कर लेता हूं और आप भी उसी लक्ष्य के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं, हम दोनों उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं, हम दोनों उसे पा लेना चाहते हैं। सोचने की यह प्रक्रिया अत्यंत सतही हैं, क्योंकि तादात्म्य द्वारा, जुड़ाव द्वारा हम अलगाव ही लाते हैं और हमारे जीवन में यह कितना साफ दिखाई देता है। आप हिंदू हैं, मैं कैथोलिक। हम दोनों भाईचारे का उपदेश देते हैं और एक-दूसरे की गर्दन पर सवार रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह हमारी समस्याओं में से एक नहीं है? अचेतन रूप से अपने मन की गहराइयों में आपके अपने विश्वास हैं और मेरे अपने। भाईचारे की बात करने से आस्थाओं, धारणाओं की सारी समस्या हल नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ सैद्धांतिक व बौद्धिक रूप से सहमत हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर भीतर कहीं गहरे में हम एक-दूसरे के विरोधी बने रहते हैं।

जब तक हम इन अवरोधों को, जो आत्म-छल हैं और हमें एक तरह की जिंदादिली का एहसास कराते हैं, विसर्जित नहीं कर देते, तब तक आपके और मेरे बीच सच्चा सहयोग संभव नहीं है। हम किसी समूह, विचार, राष्ट्र विशेष के साथ अपना तादात्म्य करके सहयोग कभी नहीं ला सकते। विश्वास सहयोग का आधार नहीं हो सकता, बल्कि वह तो विभाजित करता है। हम देखते ही हैं कि कैसे एक राजनीतिक दल दूसरे के विरोध में होता है। उनमें से हर एक आर्थिक समस्याओं को हल करने के अपने खास तरीके में यकीन रखता है, और इस तरह वे सब एक-दूसरे की काट में लगे रहते हैं। वे भूख की समस्या के समाधान के लिए कृतसंकल्प नहीं हैं। वे उन सिद्धांतों में उलझे हैं, जिनके जरिये उसका समाधान होगा। इन दोनों के बीच कलह होना तय है, क्योंकि उनका सरोकार किसी धारणा से है, न कि उस समस्या से।

यदि मुझे कुछ अनुभव हुआ है, तो मेरी उसमें आसक्ति हो जाती है; मैं अनुभव प्रक्रिया की पूरी समस्या की छानबीन नहीं करता, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, मैं उसे ही पर्याप्त समझ लेता हूं।

मानवीय संबंधों में अनुभव विभाजन का कारण बन जाता है; अनुभव छलावे का जरिया है। यदि मुझे कुछ अनुभव हुआ है, तो उसमें मेरी आसक्ति हो जाती है; मैं अनुभव प्रक्रिया की पूरी समस्या की छानबीन नहीं करता, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, मैं उसे ही पर्याप्त समझ लेता हूं और उससे चिपका रहता हूं। इस प्रकार मैं आत्म-छलावे का शिकार हो जाता हूं। जब तक हम इन छलावों को समझकर गहरे तल पर उनका विसर्जन नहीं कर देते, विश्व में शांति नहीं हो सकती।

जे कृष्णमूर्ति

वीपी मलिक | पूर्व सेनाध्यक्ष

यह अजीब है कि पद्म सम्मान पाने वालों की काबिलियत पर बात करने के बजाय हम उनकी जाति, जनजाति, राजनीतिक पार्टी, चुनावी राज्य वगैरह देख रहे हैं। हमारा मीडिया इसकी बुराई करने के बजाय इसे हवा दे रहा है।

समावेशी विकास का दस्तावेज होगा बजट

अस्थिर वैश्विक माहौल, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के बीच पेश होने वाला आम बजट- 2026 भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यही बजट तय करेगा कि देश की आर्थिक रफ्तार को अगले कुछ वर्षों तक कैसे मजबूती दी जाएगी? यह सच है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की है। उसे एक ओर बुनियादी ढांचे में निवेश को गति देना होगा, ताकि रोजगार-सृजन, औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित हो सके, तो दूसरी ओर महंगाई और आय-असमानता के दबाव में कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर समर्थन देना होगा। इसीलिए, माना यही जा रहा है कि इस बार का बजट समावेशी विकास का दस्तावेज हो सकता है।

उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार सड़क, रेल, बंदरगाह और शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि जारी रखेगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कैपेक्स आधारित रणनीति ने निजी निवेश को खींचने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में 'मेक इन इंडिया' और 'पीएलआई' जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। आम बजट से मध्यम वर्ग को भी राहत की अपेक्षा है, विशेषकर आयकर ढांचे में संभावित संशोधन, मानक कटौती में बढ़ोतरी और बचत को प्रोत्साहन देने वाले प्रावधानों के जरिये खपत को बल मिल सकेगा और बाजार में मांग बनती रहेगी।

यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और किसानों की स्थिर आय जैसी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर नए प्रावधानों की संभावना जताई जा रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और हरित व अक्षय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करना चाहेगी। कुल मिलाकर, 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से अपेक्षा है कि केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर यह एक ऐसी दूरदर्शी रूपरेखा पेश करेगा, जिससे अस्थिरता के इस दौर में भारत स्थिर, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। सरकार इसके लिए प्रयास करती दिख भी रही है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
आम बजट

वित्त मंत्री के आगे बड़ी चुनौती

फरवरी की पहली तारीख को पेश होने वाला आम बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत अगले दशक में कहां तक पहुंचना चाहता है, उसका दिशासूचक भी होना चाहिए। बेशक, पिछले दस-बारह वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तेजी से अपना आकार बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सरकार की मंशा भी स्पष्ट है कि विकास की गति को बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर भारत, निर्यात वृद्धि और निवेश को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है- बढ़ता सार्वजनिक कर्ज।

देश पर कर्ज का बोझ अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। पिछले एक दशक में कुल कर्ज 53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 185 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और अनुमान है कि मार्च 2025 तक यह 196 से 200 लाख करोड़ रुपये के बीच पहुंच गया होगा। इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि हर साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं। यानी, सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विकास-कार्यों के बजाय पुराने कर्ज की भरपाई में खर्च हो जाता है। यह स्थिति लंबे समय में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। भले ही, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश भारत से कहीं अधिक कर्जदार हों, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए कर्ज का संतुलन बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में, इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्ज-नियंत्रण की स्पष्ट रणनीति सामने रखेगी।

बजट का आकार भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। पिछले बारह साल में केंद्र सरकार का बजट 15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। इस साल इसमें करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी बताती है कि सरकार विकास के लिए खर्च करने को तैयार है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह खर्च टिकाऊ वित्तीय ढांचे के साथ किया जाएगा? रक्षा क्षेत्र भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से हो रही है। आम आदमी की नजर से देखें, तो बजट की सबसे बड़ी कसौटी राहत की उम्मीदों पर टिकी है। महंगाई से जूझ रहे मध्यम और गरीब वर्ग को रोजमर्रा की चीजों में राहत चाहिए। ऐसे में, बाजार में स्थिरता लाने की चुनौती कोई छोटी नहीं मानी जाएगी।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

यूरोप के लिए भारत अहम

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को आर्थिक नजरिये से 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, मगर इसके रणनीतिक निहितार्थ भी काफी गहरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी के दौरान जिस तरह से वाशिंगटन ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, उसने 80 साल पुराने अपने यूरोपीय मित्र देशों को सोचने को मजबूर कर दिया कि वे अमेरिका पर कितना भरोसा कर सकते हैं, चीन की आक्रामक नीतियों से वे पहले ही चौकन्ना हैं। वे उसे दूसरा अमेरिका बनाने को तैयार नहीं। ऐसे में, विशाल बाजार, अपार श्रम शक्ति वाले भारत से अधिक भरोसेमंद साझीदार कौन मिलता? प्रस्तुत है हर्ष वी पंत का नजरिया...

जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। पिछले हफ्ते विश्व आर्थिक मंच के सभागार से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जिस तरह घोषणा की थी कि भारत के साथ जल्द ही 'मदर ऑफ ऑल डील्स', यानी सभी समझौतों की जननी साकार होने वाली है, ठीक उसी गर्मजोशी के साथ मंगलवार (27 जनवरी) को ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का एलान किया गया। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद तो है ही, इसके रणनीतिक निहितार्थ भी काफी गहरे हैं, खास तौर से, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए। यह समझौता बताता है कि यूरोपीय संघ अब अमेरिका के बरअक्स चीन को नहीं, बल्कि भारत को तवज्जो देना चाहता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नई दिल्ली का कद बढ़ गया है।

आर्थिक नजर से देखें, तो भारत यूरोपीय कंपनियों के लिए विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार है। ऐसे में, यह समझौता टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने में सहायक साबित होगा। इससे जहां एक ओर भारत से कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं की यूरोपीय संघ के बाजार में आवक बढ़ जाएगी, वहीं ईयू कंपनियों को अपने ऑटोमोबाइल, मशीनरी, शराब और उत्कृष्ट गुणवत्ता-विलासिता सामग्रियों को भारतीय बाजारों में पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे आपसी व्यापार बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आएगी और विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग व हरित तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

जाहिर है, इस समझौते का रणनीतिक महत्व कहीं ज्यादा है, खास तौर से वैश्विक व्यापार की प्रवृत्ति में आए बदलाव और बढ़ते संरक्षणवाद को देखते हुए। भारत से जुड़ने पर यूरोपीय संघ की चीन पर निर्भरता कम होगी, जिससे 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति को साकार करने में उसे मदद मिलेगी। भारत के लिहाज से देखें, तो यूरोपीय संघ से जुड़ने पर हमारे लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने का लक्ष्य पाना आसान होगा, साथ ही हम एक विश्वसनीय वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी स्थिति ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। यह समझौता भारत की व्यापक व्यापार कूटनीति को भी मजबूत करेगा, जिसमें हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ इसी तरह का समझौता करना संभव होगा। भारत के लिए स्थिति कहीं अधिक अनुकूल इसीलिए है, क्योंकि यूरोपीय संघ अमेरिका और चीन, दोनों पर से अपनी निर्भरता कम करने को उत्सुक है।

ट्रंप प्रशासन और यूरोपीय संघ के बीच तनाव का मुख्य कारण अटलांटिक सागर के आस-पास के देशों को लेकर उनकी अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका प्रथम) नीति गठबंधन की एकता के बजाय अमेरिका को एकतरफा फायदा पहुंचाती है। हालिया तनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीन लेने की आक्रामकता से पैदा हुआ है। ट्रंप ने धमकी तक दे डाली है कि अगर इस मुद्दे पर यूरोपीय देश सहमत न हुए, तो उन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ थोप दी जाएगी। ईयू नेतृत्व इसे ऐसा क्षेत्रीय अतिक्रमण मानता है, जो नाटो को कमजोर करेगा। दावोस जैसे मंचों पर इसको लेकर चिंताएं बढ़ी दिखीं, क्योंकि वहां विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने यदि संयम नहीं बरता, तो नाटो खत्म हो सकता है।

ट्रंप की टैरिफ-धमकी केवल ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं हैं। वह संरक्षणवादी नीतियों पर फिर से जोर दे रहे हैं और व्यापार असंतुलन पर यूरोपीय संघ से एकतरफा रियायतें मांग रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय संघ के 2050 तक 'कार्बन तटस्थता', यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को आर्थिक रूप से विनाशकारी बताया है, और उस पर चीन जैसे विरोधियों को सब्सिडी देने व अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

ट्रंप ने गाजा पुनर्निर्माण के लिए गठित 'शांति बोर्ड' में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता भेजकर रूस को अलग-थलग करने की यूरोपीय संघ की कोशिशों की भी अनदेखी की है। वह नाटो और संयुक्त राष्ट्र को रूस या चीन से बड़ा खतरा बताकर यूरोप के भरोसे को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं। मतभेद का एक प्रमुख केंद्र प्रवासन भी है, क्योंकि अमेरिका मानता है कि यूरोपीय संघ की नरमी से पहचान का संकट खड़ा हो रहा है।

वेनेजुएला में मिली सफलता से उत्साहित ट्रंप प्रशासन जिस तरह से ग्रीनलैंड पर अपना ध्यान लगा रहा है और यूक्रेन की तरफ से आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा है, उससे 80 साल पुराने उनके रिश्ते के दरकने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि, अमेरिका पर आर्थिक व सुरक्षा के लिए निर्भर होने के कारण यूरोप एक सीमा से आगे जाकर उसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका द्वारा लंबे समय तक टैरिफ लगाए रखने से यूरोप में स्वायत्तता की भावना गहरा सकती है। ऐसे में, अमेरिका का असर कमजोर पड़ेगा। ट्रंप की बयानबाजी से दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है और रूस इस तनाव का फायदा उठाने भी लगा है।

उधर, यूरोपीय संघ चीन पर से भी अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वह बीजिंग के बरअक्स आर्थिक, रणनीतिक और कई अन्य कारणों से नई दिल्ली के करीब आना चाहता है। बेशक, चीन अब भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, पर यूरोपीय संघ के साथ उसके रिश्ते जटिल और तनावपूर्ण हो रहे हैं। लिहाजा, ईयू के लिए जरूरी बन गया है कि वह साझेदारी में विविधता लाए और अपने दक्षिण एशिया रणनीति को फिर से संतुलित करे।

भारत के साथ अच्छी बात यह भी है कि इसे लंबे समय तक क्षमतावान बने रहने के साथ तेज विकास वाला बाजार माना जाता है। चीन की आर्थिक चाल जहां सुस्त है और बाजार सिकुड़ा हुआ, वहीं भारत में न सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, बल्कि यहां का कार्यबल युवा है और डिजिटल सेवाओं, दवा-निर्माण, अक्षय ऊर्जा व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तमाम अवसर पैदा हो रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों की नजर में भारत भविष्य में उनके लिए उत्पादन-आधार व बाजार दोनों है, जो आपूर्ति-श्रृंखला में विविधता लाने और 'जोखिम कम करने' के यूरोपीय संघ के उद्देश्यों के अनुकूल है।

राजनीतिक नजर से देखें, तो यूरोपीय संघ भारत को समान विचारधारा वाला साझेदार मानता है, जो बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था का हिमायती भी है। भारत के साथ सहयोग बढ़ाकर यूरोपीय संघ अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति को मजबूत करेगा, जिससे चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी और किसी सीधे टकराव को भड़काए बिना क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।

इस सच को भला कौन नकार सकता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो बहुलवाद, नियम-आधारित विश्व व्यवस्था और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। वहीं, चीन के शासन मॉडल, मानवाधिकार रिकॉर्ड और आक्रामक विदेश नीति यूरोपीय संघ के मूल्यों और संस्थानों के साथ टकराव के कारक बने हैं। इससे यूरोप के भीतर राजनीतिक विरोध भी बढ़ा हैं। फिर, तकनीक व सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम नहीं हैं। डाटा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और चीनी तकनीक पर निर्भरता को लेकर यूरोप में चिंताएं रही हैं। इसके बरअक्स, डिजिटल शासन, महत्वपूर्ण तकनीकों और हरित अर्थव्यवस्था को लेकर भारत सुरक्षित साझेदार माना जाता है।

साफ है, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता महज एक संधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के रूप में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियमों को लचीला बनाकर बाजार तक उत्पादों की पहुंच को किस हद तक संतुलित किया जाता है, तभी विकास, स्थिरता और रणनीतिक हित आपस में टकराने के बजाय कदमताल कर सकेंगे।

इतिहास के आईने में भारत-ईयू संबंधों का सफर

43.5

हजार करोड़ का टैरिक भारत-यूरोपीय संघ के बीच कम हो जाने की बात यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समझौता कार्यक्रम के दौरान कही।

क्या है एफटीए

एफटीए देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच आपसी बातचीत के जरिए व्यापार में रुकावटों को कम करने या खत्म करने का एक समझौता है। यह सामान, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और दूसरे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए व्यापक हो सकता है। सामान के मामले में, इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र कस्टम ड्यूटी या टैरिफ, मूल नियम, व्यापार में तकनीकी रुकावटें, व्यापार में समाधान आदि जैसे गैर-टैरिफ उपाय हैं। सेवाओं के मामले में, बातचीत घरेलू नियमों सहित आपूर्ति के विभिन्न तरीकों में आने वाली रुकावटें हैं।

01 — 1962 — **शुरुआती सहयोग**: भारत ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (ईईसी) के साथ समझौता किया।

02 — 1993 — **राजनीतिक आधार**: राजनयिक संबंधों के आधार पर भारत और यूरोपीय संघ की ओर से संयुक्त वक्तव्य जारी।

03 — 1994 — **संस्थागत सहयोग**: भारत-यूरोपीय संघ के बीच पारस्सरिक पहयोग समझौता किया गया।

04 — 2000 — **समिट का आयोजन**: भारत-ईयू प्रथम लिस्बन सम्मेलन से उच्च स्तरीय संबंधों के नए दौर की शुरुआत हुई।

05 — 2004 — **रणनीतिक ऊंचाई**: हेग में आयोजित पांचवें सम्मेलन में भारत-ईयू रणनीतिक सहयोग समझौता।

06 — 2007 — **व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं**: व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) के लिए दोनों पक्षों में बातचीत शुरू हुई।

07 — 2020 — **आगे की सोच**: भारत-यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक समझौता का 2025 तक का रोडमैप स्वीकृत हुआ।

08 — 2022 — **तकनीक और व्यापार सहयोग**: भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार एवं तकनीकी परिषद (टीटीसी) का गठन किया गया।

09 — 2025 — **भारत-ईयू रणनीतिक एजेंडा**: भारत के साथ अवसरों और सुरक्षा-व्यवस्था को आगे बढ़ाने की ईयू की रणनीति सामने आई।

स्रोत : Mea.gov.in

- आसियान देशों के साथ बाली में केवल सामानों के लिए हुआ समझौता 1 जनवरी 2010 से और सेवाओं व निवेश को लेकर हुआ समझौता 1 जुलाई 2015 से प्रभावी। 2023-24 में, आसियान-भारत द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर से अधिक का था। यह समझौता 4,000 से अधिक उत्पादों पर शुल्क समाप्त करने या कम करने से संबंधित है।
- जापान के साथ 1 अगस्त 2011 से प्रभावी। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 22.85 अरब डॉलर रहा, जिसमें जापानी निर्यात 17.69 अरब डॉलर और भारतीय निर्यात 5.15 अरब डॉलर था।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता 29 दिसंबर 2022 से चल रहा है। इसमें शेफ और योग शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान है। अगले 5 वर्षों में द्विवार्षिक व्यापार को लगभग 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर 45-50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- भारत और ब्रिटेन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर करने का समझौता जुलाई 2025 में किया।
- यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख रोजगारों के संकल्प वाला समझौता 1 अक्तूबर 2025 से लागू। इस एसोसिएशन में आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। यूरोपीय देशों में 9.31 लाख से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। कारोबार में बदलाव हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। माता से धन मिल सकता है।

वृष : मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यभार बढ़ेगा।

मिथुन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। पिता का साथ मिल सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं।

कर्क : आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भागदौड़ रहेगी।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परंतु मन परेशान भी हो सकता है। संयत रहे, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे।

तुला : आत्मविश्वास के बावजूद मन में उतार-चढ़ाव बहुत होंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

वृश्चिक : मन प्रसन्न रहेगा, परंतु सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है।

धनु : शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बहुत रहेगा। हालांकि धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। सेहत का ध्यान रखें। संयत रहें।

मकर : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद हो सकती है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्रों और वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं।

मीन : मन में उतार-चढ़ावों के बावजूद आत्मविश्वास महसूस होगा। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार से लाभ में वृद्धि हो सकती है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

28 जनवरी, बुधवार, **शक संवत्:** 08 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 15 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 08 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ शुक्ल दशमी तिथि सायं 04.37 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, कृतिका नक्षत्र प्रात: 09.27 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, गर करण। चन्द्रमा वृष राशि में (दिन रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 03.17 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम प्लाईबोर्ड बनाने की एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, परंतु कुछ न कुछ समस्या आ रही है। कृपया कोई वास्तु उपाय बताएं। -शैलेश वर्मा, कानपुर

- आपने फैक्ट्री बनाने के लिए जो प्लॉट लिया है, वह पश्चिम मुखी है। सड़क के घुमाव के कारण आपके प्लॉट की उत्तर-पश्चिम दिशा काफी बढ़ गई है। साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा काफी कम हो गई है। प्लॉट में पीछे भी पूर्व दिशा बढ़ी हुई है, जिसके कारण ईशान कोण एवं अग्नि कोण- दोनों कट गए हैं। यही कारण है कि आपका निर्माण कार्य बढ़ ही नहीं पा रहा है। पहले अपने प्लॉट को जितना हो सकता है, उतना समकोणीय बनाएं, उसके बाद इसमें निर्माण कार्य शुरू करेंगे तो सही होगा।

वर्ग पहेली : 8223

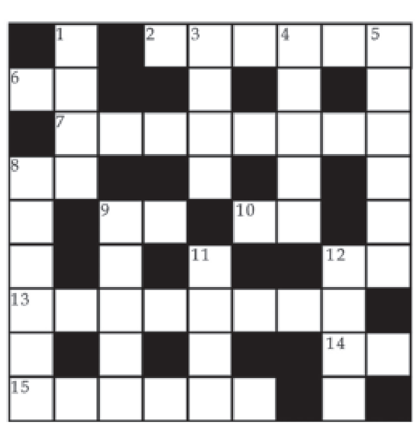

बाएं से दाएं
2. अर्जित करना; व्यापार करना; कमाना (3,3)
6. दूसरे को कष्ट पहुंचा कर सुखी-संतुष्ट होने वाला; दया-हीन; निर्दय; निष्ठुर (2)
7. काम पूरा करना; किसी के जीवन का अंत करना; घात करना; मार डालना (2,3,3)
8. आघात; निशाना; प्रहार; लक्ष्य; पिटाई (2)
9. घरों की आमने-सामने बनी पंक्तियों के बीच का रास्ता; वीथी (2)
10. छाती; टांका लगाना; सिलाई करना (2)
12. गमन करना; चलना; निकलना; रास्ता लेना (2)
13. छिपी हुई बात खोलना; भेद प्रकट करना; रहस्य अनावृत्त करना (3,2,3)
14. फूलों का व्यवसाय करने वाली जाति; बगीचे का रखवाला (2)
15. पालने वाले से द्रोह करने वाला; स्वामी से छल करने वाला; कृतघ्न, विश्वासघाती (6)

ऊपर से नीचे
1. मालिक; प्रशासन (4)
3. माल से भरपूर; धनी; संपन्न (4)
4. अरुचिकर लगना; चुनचुनाना; सावधान होना; रोमांचित होना (5)
5. बहुत प्रसन्न होना; स्वयं नाचते हुए दूसरों को नाचने के लिए खींच कर लाना (3,3)
8. आदर-अनादर (2,4)
9. गति देने वाला; गति बढ़ाने वाला (5)
11. दस प्रकार के पापों का हरण करने वाली गंगा; विजयादशमी (4)
12. ज्ञात; प्रचलित; देखभाल; प्रसिद्ध (2,2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8222

सुडोकू : 8205

* कठिन

					7			6
				6		7	8	
5					9		3	
	5				8		4	9
6								3
4	2		6				1	
	4		7					5
	1	9		4				
2			9					

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8204

3	5	8	2	7	4	9	1	6
7	9	1	6	8	5	3	2	4
6	2	4	1	3	9	7	8	5
2	4	7	3	9	1	5	6	8
1	3	6	8	5	7	2	4	9
5	8	9	4	2	6	1	7	3
4	7	5	9	6	2	8	3	1
8	1	2	5	4	3	6	9	7
9	6	3	7	1	8	4	5	2

तनाव के समय शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए कूटनीति बेहद जरूरी है। -एडवर्ड जोनाथन डेवी

विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुए बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों पक्षों को जो फायदे मिलेंगे, वे तो अपनी जगह हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, इसने खंडित हो रही दुनिया को सहयोग की एक नई राह दिखाई है।

सहयोग की राह

करीब दो दशकों के कूटनीतिक इंतजार, अनगिनत दौर की बातचीत और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच मंगलवार को भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने जिस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की नींव रखी है, वह दोनों ही पक्षों के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर आया है। इस समझौते की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही इसे ऐतिहासिक, तो यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच साझेदारी का एक नया अध्याय और 'मदर ऑफ ऑल डील्स' करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सफल भारत दुनिया को बेहतर बनाएगा। दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का करीब एक-तिहाई हिस्सा रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुए इस समझौते का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए मतभेदों को पीछे छोड़कर यूरोप अब भारत को एक महत्वपूर्ण और भविष्य के अनिवार्य साझेदार के रूप में देख रहा है, तो दूसरी ओर चीन पर निर्भरता कम करने की छटपटाहट ने भी भारत को उसके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। भारत भी यह स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विकल्प खुले रखेगा। गौरतलब है कि भारत-ईयू के बीच हुए इस समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण एक-दूसरे के बाजारों तक सुलभ पहुंच है। इसके तहत यूरोपीय संघ के 27 देशों को भारत के विशाल बाजार तक व्यापक पहुंच मिलेगी। लगभग 97 फीसदी यूरोपीय निर्यात पर शुल्क या तो कम होगा या पूरी तरह समाप्त किया जाएगा, जिससे मशीनरी, ऑटोमोबाइल, तकनीकी उपकरण और रसायन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे। बदले में भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण और अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों को यूरोप में शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, देश के

ऑटोमोबाइल उद्योग, जो अब तक उच्च टैरिफ के सहारे सुरक्षित रहा है, को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, कम कीमतों पर यूरोपीय उत्पादों के आने से गुणवत्ता, विकल्प और सुरक्षा मानकों में भले ही सुधार हो, पर इससे घरेलू उत्पादकों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव भी बढ़ सकता है। लिहाजा, इस समझौते को दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। खंडित दुनिया में यह समझौता सहयोग की मिसाल है। अगर प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ, तो यह आपूर्ति शृंखलाओं को नया रूप देगा, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाकर देशों के बीच सहयोग का एक नया आदर्श प्रस्तुत करेगा। जैसा उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा भी है, यह तो बस शुरुआत है।

पश्चिमी गठबंधन के दरकते तटबंध

ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन में आती दरारें साफ दिखाई पड़ रही हैं। ट्रंप अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो यूरोप अपनी गरिमा बचाने के लिए संघर्षरत है। ऐसे में, सब कुछ इसी पर निर्भर होगा कि यूरोपीय संघ अपनी ताकत के भरोसे तन के खड़ा रहेगा या अभी भी व्हाइट हाउस या पेंटागन की ओर देखेगा?

दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के मंच पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी परंपरागत शैली में ही दिखे। उन्होंने जो कहा, अब वह 'वेनेजुएला एक्शन' के बाद पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं रह गया। अगर दुनिया इस पर नासमझी दिखाए, तो यह इतिहास का दोष है। इसके साथ ही वह इतिहास में अमेरिका को देखते और यह कहते हुए आगे बढ़े कि अमेरिका कितना मूर्ख था, जो ग्रीनलैंड जीतकर डेनमार्क को सौंप दिया था। फिर उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि 'ग्रीनलैंड हमें दे दो।' अब अगर यूरोप 'ना' कहता है, तो अमेरिका इसे याद रखेगा। इस याद रखने का अर्थ क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

ट्रंप यह कहते हुए भी दिखे कि अगर मैं चाहूं, तो बहुत ज्यादा ताकत और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं, तब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। पर मैं बल प्रयोग नहीं करूंगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 'नियम आधारित व्यवस्था' के समाप्त हो जाने का संकेत दे रहे हैं? क्या अब भी यूरोप सहित पूरी दुनिया अमेरिकी नीतियों को 'शांति' का सारथी मानते हुए प्रशंसा करती रहेगी? एक प्रश्न और। क्या हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि आर्कटिक क्षेत्र अब वैज्ञानिक से भू-रणनीतिक क्षेत्र और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का नया थिएटर बन चुका है? यदि हां, तो इस भू-रणनीतिक बिंदु, जो कि उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच का सेतु है, से ही नए युद्ध अथवा विश्वयुद्ध की राह बनेगी?

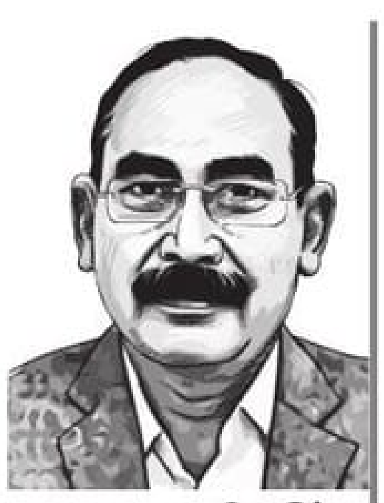

रहीस सिंह
वैदेशिक मामलों के जानकार

ट्रंप की धमकियां संभवतः सोए हुए यूरोप को जगाने का काम करने लगी हैं। वह नींद से बाहर आएगा या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन अगर यूरोपीय देश अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अमेरिका नियम आधारित व्यवस्था को ध्वंस कर रहा है, तो शायद इतिहास उन्हें कभी क्षमा न कर पाए। हाल के उदाहरण ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्हाइट हाउस के सामने डटे रहने वाले देशों के सामने ट्रंप की सनक घुटने टेकने पर विवश हुई। चीन और ब्राजील इसके उदाहरण हैं। वहीं, जो देश ट्रंप के

सामने झुक गए, उन्हें और झुकाने व अपमानित करने का कोई अवसर वह नहीं छोड़ रहे। इसलिए, न केवल यूरोप को, बल्कि पूरी दुनिया को इस विषय पर गंभीर होना चाहिए कि ग्रीनलैंड का प्रश्न केवल डेनमार्क के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह प्रश्न क्षेत्रीय अखंडता व आत्मनिर्णय के अधिकार का है। यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आत्मा में बसे सिद्धांतों का भी है। यूरोप को तो इसलिए गंभीर और संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप की सनक अब यूरोपीय संघ, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन के बचे-खुचे ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में बढ़ रही है। यूरोप को समझना होगा कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को देख रही है, इसलिए वह एक दिन यह निष्कर्ष अवश्य निकालेगी कि इस नए और क्रूर वैश्विक परिवेश में यूरोपीय संघ जीवित रहने में सक्षम है या नहीं?

यूरोप को यह सोचने की जरूरत है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र का ऐसा भू-रणनीतिक क्षेत्र है, जिस पर अमेरिका की ही नहीं, बल्कि चीन की भी गिद्ध दृष्टि है। इसलिए, ग्रीनलैंड पर यूरोप का अमेरिका के सामने झुकना या न झुकना बीजिंग के लिए एक रणनीतिक प्रयोग की तरह होगा। यदि यूरोप पीछे हट जाता है, तो चीन यह निष्कर्ष निकालने में देरी नहीं करेगा कि क्षेत्रीय अखंडता व आत्मनिर्णय, अब एक औपचारिक शब्दावली भर हैं, कोई बाध्यकारी नियम नहीं। दूसरे शब्दों में कहें, तो ग्रीनलैंड पर यूरोप का रुख ही तय करेगा कि भविष्य में दुनिया नियमों से चलेगी या दबदबे से? यदि नियम टूटते हैं, तो आज वे आर्कटिक में टूटेंगे, कल दक्षिण चीन सागर में और फिर शायद हिंद महासागर में। वैसे चीन तो पहले ही 'पोलर सिल्क रोड' के जरिये अपने आपको 'नियर आर्कटिक स्टेट' तक बता चुका है। ऐसे में, यदि यूरोप कमजोर पड़ता है, तो चीन आर्कटिक में स्थायी आर्थिक रणनीतिक उपस्थिति बना सकता है।

उल्लेखनीय है कि चीनी 'पोलर सिल्क रोड' उसके 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) का आर्कटिक संस्करण है, जिसका उल्लेख उसने 'चीनी आर्कटिक नीति श्वेत पत्र 2018' में किया था। यहां यह प्रश्न भी उभरकर आता है कि कहीं इसी का भय दिखाकर तो ट्रंप यूरोप को दबाव में नहीं लेना चाहते हैं? या फिर वह अपनी धमकियों के जरिये चीन के लिए एक अवसर तो निर्मित नहीं कर रहे? वैसे ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन अब पतन के सबसे निचले बिंदु तक पहुंच चुका है, इतना कि किसी दिन बिखर भी सकता है। आज अमेरिका नाटो के सदस्य डेनमार्क से उसका एक भू-भाग छीनने का प्रयास कर रहा है और यूरोप अलर्ट मोड पर है। यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में सेनाएं भेजकर आर्कटिक सुरक्षा के नाम पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं। ट्रंप भले ही इसे यूरोपीय देशों, विशेषकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का 'अत्यंत खतरनाक खेल' बता रहे हों, पर यह ट्रांस-अटलांटिक में आती हुई दरार का दृश्यांकन है। शह और मात का जो खेल अभी तक झुकने और उठने तक ही सीमित था, अब परिणाम के निकट पहुंच चुका है। अब देखना है कि यूरोपीय देश इसे स्वीकार कर 'प्रेज डिप्लोमेसी' (प्रशंसा की कूटनीतिक) की परंपरा का अनुसरण करेंगे या फिर तन कर खड़े हो जाएंगे? या प्रतीक्षा करेंगे कि ट्रंप केवल धमकियों तक ही सीमित रहेंगे या फिर जवाबी कार्रवाई होगी? पश्चिमी गठबंधन, जिसमें नाटो भी शामिल है, पूरी तरह से विघटित होगा या पुनर्निर्मित? इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि, ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपने दबाव को बढ़ा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अमेरिका अटलांटिक फाइव के सामूहिक सुरक्षा समझौते से बंधा नहीं है। फिर तो, पश्चिमी गठबंधन के बिखरने की आशंका ज्यादा है। तो क्या अमेरिकी व यूरोपीय सेनाएं ग्रीनलैंड पर आमने-सामने खड़ी हो सकती हैं? देखना होगा कि कौन पहले पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा?

दरअसल, पश्चिमी गठबंधन एक विचार भर नहीं, एक ढांचागत व्यवस्था है, जो सुरक्षा (यानी नाटो), राजनीतिक मूल्यों, आर्थिक साझेदारी और वैचारिक ढांचे (विशेषकर उदार लोकतंत्र) व नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसे स्तंभों पर खड़ी है। सुरक्षा पर एकजुटता इनकी विवशता है, पर वह ऊपरी सतहों पर भी अब पुख्ता नहीं दिख रही, अंदर से तो खोखली हो ही चुकी है। लोकतंत्र पश्चिमी जगत में भी उदारता का परिचय नहीं दे पा रहा, बल्कि वह संघर्षरत दिखाई दे रहा है और वैचारिक सहमति दरक चुकी है। असल समस्या यहीं से शुरू होती है। अब देखना यह है कि यूरोपीय संघ अपनी ताकत के भरोसे तन के खड़ा होगा या अभी भी व्हाइट हाउस या पेंटागन की ओर देखेगा? सब कुछ इसी पर निर्भर होगा। बहरहाल जो भी हो, दोनों ही स्थितियां एक इतिहास अवश्य लिखेंगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जॉन लॉक

जब हम सहिष्णुता, नैतिकता और न्याय को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तब समाज केवल एक ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि वह शांति और समानता का एक जीता-जागता उदाहरण बन जाता है।

विवेक ही सबसे अच्छा मार्गदर्शक है

मानवता का उदय तर्क और विवेक के उस पावन प्रकाश में हुआ है, जिसे 'प्राकृतिक अवस्था' कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मूल अस्तित्व की, जहां हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और जिसकी आत्मा पर किसी सत्ता का दासत्व नहीं है। यहां शासन किसी निरंकुश शासक का नहीं, बल्कि उस 'प्राकृतिक कानून' का है, जो हर हृदय में गूंजता है और यह बोध कराता है कि हम सब एक ही महान सृजन की उत्कृष्ट और समान रचनाएं हैं। यह कानून कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि एक दिव्य नैतिक प्रतिज्ञा है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता वहीं है, जहां हम दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वायत्तता और उसकी मेहनत से अर्जित संपत्ति का सम्मान करें। इस अवस्था में, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है और तर्क वह प्रकाश है, जो उसे अंधकार से दूर रखता है।

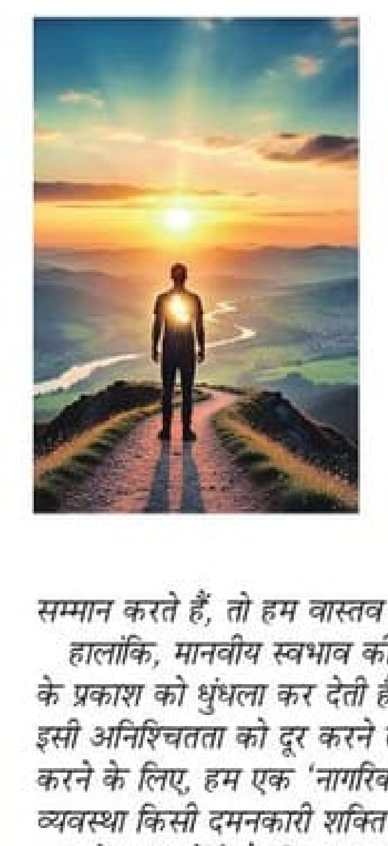

विवेक हमें यह महान सत्य समझाता है कि हमारी अपनी स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित है, जब तक हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यह आपसी सहयोग और न्याय की एक सक्रिय साधना है, जहां हर व्यक्ति प्राकृतिक कानून का पालन करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण जगत का निर्माण करता है। प्राकृतिक न्याय का यह मार्ग हमें सिखाता है कि हम विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षण के लिए बने हैं और जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी ही गरिमा को ऊंचा उठा रहे होते हैं।

हालांकि, मानवीय स्वभाव की सीमाओं के कारण जहां स्वार्थ या अज्ञानता तर्क के प्रकाश को धुंधला कर देती है, वहां विवादों की परछाई पड़ना स्वाभाविक है। इसी अनिश्चितता को दूर करने तथा अपने अधिकारों को और अधिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए, हम एक 'नागरिक समाज' के गठन का संकल्प लेते हैं। यह व्यवस्था किसी दमनकारी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र विश्वास के रूप में जन्म लेती है, जिसका एकमात्र आधार जनता की स्वेच्छा और सहमति है। सरकार कोई स्वामी नहीं, बल्कि एक रक्षक है, जिसकी वैधता केवल इस बात पर टिकी है कि वह कितनी निष्पक्षता से न्याय और सुरक्षा का विधान करती है। अतः, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ उच्छृंखलता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का वह आभूषण है, जिसे केवल विवेकशील मनुष्य ही धारण कर सकते हैं।

शिक्षा और एक सकारात्मक वातावरण के माध्यम से हम किसी भी मस्तिष्क को उस स्तर तक परिष्कृत कर सकते हैं, जहां वह समाज को केवल संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि साझा उन्नति का मंच मानने लगे। जब हम सहिष्णुता, नैतिकता और न्याय को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तब समाज केवल एक ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि वह शांति और समानता का एक जीता-जागता उदाहरण बन जाता है। हमें विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक स्थायी और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी है।

सबको साथ लेकर चलें

सूत्र

सच्ची उन्नति दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि सबके साथ आगे बढ़ने में निहित होती है। तर्क, सहिष्णुता और न्याय केवल विचार नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के आचरण होने चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर के विवेक को जाग्रत रखता है, तब समाज संघर्ष का क्षेत्र नहीं, बल्कि सहयोग और शांति का आधार बन जाता है।

दूसरा पहलू

यूं तो जालसाजी के तमाम किस्से सुनने को मिलते हैं, पर कुछ ऐसी भी जालसाजियां होती हैं, जो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं।

इतिहास की सबसे अजीब पुरातात्विक जालसाजी

यूं तो जालसाजी और धोखाधड़ी मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कुछ ऐसी भी जालसाजियां होती हैं, जो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही जालसाजी एक पुरातत्वविद ने एक बौद्ध भिक्षु के साथ की। हुआ कुछ यों कि 1895-96 में बर्मा (आज का म्यांमार) के बौद्ध भिक्षु ऊ मा बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा पर भारत आए थे। उसी बीच उनकी मुलाकात पुरातत्वविद डॉक्टर एए फ्यूहरर से हुई। वह जर्मनी के पुरातत्वविद थे और उन दिनों नेपाल की तराई में उत्खनन और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों की खोज कर रहे थे। तथागत के अस्थि अवशेषों को बौद्ध बहुत पवित्र मानते हैं। ऊ मा ने एए फ्यूहरर से कहा कि यदि उन्हें तथागत के अस्थि अवशेष मिलें, तो उनमें से कोई एक उन्हें दे दें, जिनकी स्थापना वह अपने देश में करेंगे। फ्यूहरर ने ऊ मा से वादा किया तथा कुछ समय बाद उन्हें एक दांत का अवशेष भेजा और कहा कि यह उन्हें श्रावस्ती से उत्खनन में मिला है।

ऐसी ही जालसाजी फ्यूहरर नामक पुरातत्वविद ने बौद्ध भिक्षु ऊ मा के साथ की, जब उन्होंने बुद्ध के बजाय घोड़े के दांत की तरह दिखने वाला दाढ़ का दांत भेज दिया था।

ऊ मा ने फ्यूहरर की इस जालसाजी की शिकायत ब्रिटिश अधिकारियों से की। इतिहासकार चार्ल्स एलन की पुस्तक *द बुद्धा एंड फ्यूहरर* में भी फ्यूहरर की कई और जालसाजियां उजागर की गई हैं।

यह दांत 21 सितंबर, 1897 को भेजा गया। लेकिन जब यह दांत ऊ मा के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इसे बुद्ध का दांत मानने से इन्कार कर दिया। यह एक मोलर टूथ (दाढ़ का दांत) था और आकार में बहुत बड़ा था। ऐसा लगा कि यह किसी घोड़े का दांत था। इस पर उन्होंने आपत्ति की और फ्यूहरर को पत्र लिख कर इसके फर्जी होने की बात कही। फ्यूहरर ने उन्हें पत्र लिख कर आश्वस्त किया कि यह बुद्ध का ही दांत है और उन्होंने उसे उत्खनन में ही पाया है। चूंकि, बुद्ध का शरीर बड़ा था, इसलिए दांत का आकार भी बड़ा है। लेकिन उसे लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें इस दांत के साथ ही एक अभिलेख भी मिला है, जिसमें बताया गया है कि यह दांत सम्राट अशोक ने उपगुप्त को उपहार में दिया था। इसलिए यह दांत सही है। हालांकि, उस समय ऐसा कोई अभिलेख फ्यूहरर को नहीं मिला था, लेकिन सांची और अन्य जगहों पर बाद में ऐसे अभिलेख पाए गए। पर भिक्षु ऊ मा ने फ्यूहरर की बात नहीं मानी और ब्रिटिश अधिकारियों से उनकी शिकायत कर दी और प्रमाण में वे सभी पत्राचार भी प्रस्तुत किए, जो दोनों के बीच हुए थे। यह जांच लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर के सामने गई, जिनके अधिकार क्षेत्र में उस समय हो रहे उत्खनन के काम भी थे। यह पूरा रोचक विवरण पत्रकार और इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अपनी पुस्तक *द बुद्धा एंड फ्यूहरर* में बहुत विस्तार से लिखा है, जिसमें एए फ्यूहरर की कई और जालसाजियां भी उजागर की गई हैं।

- रामधनी द्विवेदी

आंकड़े

ग्रीनहाउस गैस

वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) में लगातार वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक तापमान को प्रभावित कर रही हैं। इसमें चीन का सर्वाधिक योगदान है।

चीन	25.92
अमेरिका	11.12
भारत	7.83
ब्राजील	5.15
रूस	5.05

आंकड़े 2024 के जीएचजी उत्सर्जन में देशों की हिस्सेदारी के, प्रतिशत में। | स्रोत : जौस एट अल. (2025)

परीक्षा लेने के बाद राजा को यह बोध हुआ कि जो कुछ भी हमारे पास है-धन, सम्मान या सामर्थ्य-वह सब ईश्वर की अनुकंपा से है। मनुष्य केवल माध्यम है, स्वामी नहीं।

देने वाले तो परमपिता हैं

एक राज्य में एक प्रतापी और उदार राजा का शासन था। उसके महल के द्वार पर प्रतिदिन दो भिक्षुक आते थे। पहला भिक्षुक शांत भाव से कहता, 'जो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो, वही मेरा है।' दूसरा भिक्षुक गर्व और भरोसे से कहता, 'जो राजा देंगे, वही मेरा भाग्य है।'

राजा का मन दूसरे भिक्षुक की ओर अधिक झुकता था, क्योंकि वह स्वयं को ही सब कुछ मानता था। परंतु राजा के भीतर एक प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में सब कुछ मनुष्य की शक्ति से मिलता है, या फिर किसी अदृश्य शक्ति की कृपा से? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने परीक्षा लेने का निश्चय किया।

राजा ने एक रोटी बनवाई, जिसके भीतर बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राएं छिपी थीं, और उसने वह रोटी दूसरे भिक्षुक को दे दी। किंतु कुछ पैसों के लालचवश भिक्षुक ने रोटी पहले भिक्षुक को दे दी। उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए रोटी स्वीकार कर ली। जब उसने रोटी तोड़ी, तो उसमें छिपा हुआ धन उसके सामने आ गया। इससे उसका पूरा जीवन ही बदल गया।

अंतर्यात्रा
संकलित

जब राजा को यह बात पता चली, तो उसके भीतर का अहंकार शांत हो गया। उसने समझ लिया कि देने वाला वह नहीं, बल्कि परमपिता हैं। उसे यह बोध हुआ कि जो कुछ भी हमारे पास है-धन, सम्मान या सामर्थ्य-वह सब ईश्वर की अनुकंपा से है। मनुष्य केवल माध्यम है, स्वामी नहीं।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 28 जनवरी, 1954

भारत पूर्व व पश्चिम को भली-भांति समझा सकता है

भारत पूर्व व पच्छिम को भली भांति समझा सकता है

भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत संसार को सुखी व समृद्ध बनाने में काफी योगदान दे सकता है। भारत में गांधीवाद एक दर्शन है। निस्संदेह भारत पूर्व व पश्चिम को भली-भांति समझा सकता है।

आखिर इस मर्ज की दवा क्या है

सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही सड़कों पर आक्रामक आवारा कुत्तों की गंभीर समस्या से निपटा जा सकता है।

विजय त्रिपाठी | मुद्दा

पुराने लखनऊ निवासी रामचरन घर से निकलकर चौराहे के मोड़ तक पहुंचे ही थे कि कुत्तों का झुंड उनके पीछे लपका। रामचरन आज असमंजस में थे। पीढ़ियों से उनका परिवार कुकुर, गैया, चिरैया के भरण-पोषण की चिंता करते आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट का यह दो टूक फरमान उनकी आंखों के सामने तैर गया कि अगर कुत्तों से ज्यादा मोहब्बत है, तो अपने घर में रखो, खबरदार जो सड़क या चौराहे पर खाना-पीना दिया तो। अब उन्हें फिक्र हो रही है कि आगे से कहीं गाय-कुत्ता को रोटी (अग्राशन) खिलाने उन्हें कांजी हाउस या कुत्तों की जेल न जाना पड़े।

वहीं, तेलंगाना के याचाराम गांव में करीब सौ कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। एक पखवाड़े के भीतर राज्य में करीब 500 आवारा कुत्तों को मारा जा चुका है। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एक कार्यकर्ता ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है। इससे पहले हनमकोंडा व कामारेड्डी जिले में सैकड़ों बेजुबानों को मार दिया गया था। पांच सरपंचों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

भारतीय संस्कृति प्राणिमात्र के कल्याण की बात करती है, पर अब मनुष्य-श्वान के सह अस्तित्व पर संकट है। जन सुरक्षा (अनुच्छेद 21) और जीव कल्याण के बीच बना संतुलन डगमगा रहा है। आवारा कुत्तों की समस्या अब गली-मोहल्ले से निकलकर संसद व सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंची है। यह सच है कि पिछले कुछ सालों से कटखने कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आक्रामक आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था। साथ ही, गली-मोहल्लों में कुत्तों को सड़क पर भोजन देने पर रोक की हिदायत दी थी, मगर पशु प्रेमियों को यह फैसला रास न आया और फिर यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आवारा कुत्तों के खिलाफ एकजुट संगठनों की दलील है कि घर-दफ्तर-दुकान से बाहर कुत्तों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। पशु कल्याण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि देश में रोज करीब दस हजार लोगों को लावारिस कुत्ते काट लेते हैं। अपने देश में रेबीज की दर दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से पिछले साल जारी आंकड़ों पर गौर करें, तो वर्ष 2022 में कुत्तों के काटने के करीब 22 लाख मामले, 2023 में 27.5 लाख, 2024 में 37 लाख मामले दर्ज हुए।

केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर कुत्तों के आबादी नियंत्रण के कार्यक्रम बेकार साबित हुए हैं। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को भारी मुआवजा के लिए कहना पड़ा। एक पक्ष की जिद है कि सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर बाड़े में बंद कर दिया जाए, जबकि दूसरे पक्ष की दलील है कि यह अमानवीय है। ऐसे में, इस पर पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता से विचार की जरूरत है कि सरकार व समाज से सामूहिक प्रयासों से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। कमी एक ऐसी नीति की है, जिसमें दोनों की सुरक्षा की व्यवस्था हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निजात पाने का सरल व प्रभावी उपाय आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में टीकाकरण के जरिये कुत्तों का बंध्याकरण करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, पर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और इच्छाशक्ति के अभाव में यह मुहिम कागजों पर ही दम तोड़ती नजर आ रही है। अपर्याप्त पशु कल्याण बुनियादी ढांचा इस समस्या का मूल कारण है। यही वजह है कि आवारा कुत्तों की संख्या और इन्सानों को काटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अदालत ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे महत्वपूर्ण स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थल भेजें। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। बड़े पैमाने पर नसबंदी का अभियान नगर निकायों, पशु अस्पतालों और पशुप्रेमी संगठनों की सक्रिय भूमिका के बगैर संभव नहीं है। कुछ लोग व्यावहारिक समाधान सुझाते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी-टीकाकरण के बाद उन्हें उनके पुराने ठिकाने पर छोड़ दिया जाए। इसमें मानवीय दृष्टि रखने वाले पशुप्रेमी संगठनों का भी यह दायित्व है कि वे ऐसे आवारा कुत्तों को गोद लें। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार विदेशी नस्ल के कुत्तों की आमद पर रोक लगाए या सीमित छूट दे।

नियमन-नियंत्रण का विरोध कर रहे पशु अधिकारों के पैरवीकारों का तर्क है कि कुत्तों को जंगलों से अपने स्वार्थ के लिए लाया कौन-आदमी, उनसे चौकीदारी कराया कौन-आदमी, उनसे अपनी भेड़-बकरियां चरवाया कौन-आदमी...अब वे हमारे लिए अवांछित हो गए हैं (नस्ल आधारित) और उन्हें अब जंगल या बाड़े का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या यही रास्ता है, क्या मौजूदा जंगल या बाड़े काफी होंगे उन्हें संभालने के लिए...शायद नहीं, हमें तो यह गिनती तक नहीं पता कि देश भर में ऐसे आवारा कुत्ते हैं कितने। फिर रास्ता क्या है...यही रास्ता हमें तलाशना है। इस पंचायत में पुराने लखनऊ के रामचरन की बात भी सुनी जाएगी और तेलंगाना के याचाराम गांव के लोगों की भी। फॉर्मूला इसी रास्ते से निकलेगा।

न्यूज डायरी

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर से 22 पैसे उछला

मुंबई। अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के चलते रुपया मंगलवार को रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरते हुए 22 पैसे की बढ़त के साथ 91.68 पर बंद हुआ। डॉलर की कमजोरी को दूर करने के लिए कारोबारियों की जल्दबाजी से रुपये में सुधार हुआ। हालांकि, क्रूड में तेजी से बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 91.82 पर खुला व 91.90 के निचले स्तर पर आ गया। एजेंसी

एशियन पेंट्स का लाभ घटकर 1,128 करोड़

नई दिल्ली। नए श्रम संहिता के लागू होने के चलते एशियन पेंट्स का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 4 फीसदी घटकर 1,073.92 करोड़ रुपये रह गया है। राजस्व 3.71 फीसदी बढ़कर 8,867 करोड़ रुपये हो गया। 157.61 करोड़ ग्रेच्युटी में वृद्धि के लिए और 63.74 करोड़ के एकमुश्त खर्च व 93.87 करोड़ के व्हाइट टीक के अधिग्रहण जैसे खर्चों से लाभ में कमी आई। एजेंसी

टाटा कंज्यूमर का फायदा 36 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को तीसरी तिमाही में 384.52 करोड़ का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 36.4 फीसदी अधिक है। राजस्व 15 फीसदी बढ़कर 5,112 करोड़ हो गया। खर्च 4,582.24 करोड़ रहा, जो 12.11 फीसदी अधिक है। अन्य आय सहित टाटा कंज्यूमर की आय 14 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 5,145.01 करोड़ रही। एजेंसी

मैरिको को 460 करोड़ रुपये का फायदा

नई दिल्ली। मैरिको लि. को दिसंबर तिमाही में 460 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 13.3 फीसदी अधिक है। राजस्व 26.6 फीसदी बढ़कर 3,537 करोड़ रुपये हो गया। खर्च 29.8 फीसदी बढ़कर 3,009 करोड़ हो गया। एजेंसी

रिकॉर्ड : चांदी एक दिन में 40,500 रुपये महंगी, सोना भी 1.66 लाख के शीर्ष पर

मजबूत मांग और देशों के बीच तनाव से सोना 7,300 रुपये महंगा, चांदी 3.70 लाख रुपये पर पहुंची

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। निवेशकों की मजबूत मांग और देशों के बीच बढ़ते तनाव से दोनों कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। सोना 7,300 रुपये या 4.6 फीसदी महंगा होकर 1.66 लाख रुपये प्रति दस ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसी के साथ चांदी भी पहली बार एक दिन में 40,500 रुपये की तेजी के साथ सार्वकालिक उच्च स्तर 3.70 लाख रुपये किलो पर पहुंच गई।

शुक्रवार को सोने की कीमत 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। गणतंत्र दिवस के कारण सोमवार को बाजार बंद रहे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, बढ़ते व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की मजबूत मांग के चलते घरेलू बाजार में चांदी ने एक और रिकॉर्ड ऊंचाई छू लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें 8.55 डॉलर या 8.24 फीसदी बढ़कर 112.41 डॉलर प्रति औंस हो गईं। पिछले सत्र में 14.42 डॉलर या 14 फीसदी बढ़कर 117.73 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई थी।

5,110 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची थी पीली धातु सोमवार को

121.07 डॉलर बढ़ गई थी सोने की कीमत

▪ **2.37 लाख रुपये पर बंद हुई थी चांदी इस साल एक जनवरी को**

9% बढ़ गया सोने का वैश्विक बाजार में भाव सात कारोबारी सत्रों में

पिछले सात कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतें 19 जनवरी को 4,670.89 डॉलर प्रति औंस से 416.59 डॉलर या लगभग 9 प्रतिशत बढ़ गई हैं। नए भू-राजनीतिक तनाव एक प्रमुख कारण रहे हैं क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और लकड़ी पर टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। इन घटनाक्रमों ने सुरक्षित निवेश की मांग को और मजबूत किया है।

चांदी इस महीने अब तक 1.33 लाख महंगी हुई

इस महीने में चांदी 1.33 लाख रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। एक जनवरी को यह 2.37 लाख रुपये पर बंद हुई थी जो अब 3.70 लाख रुपये हो गई है। इसी तरह, सोना भी 22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। एक जनवरी को यह 1,38,340 रुपये प्रति दस ग्राम था जो अब 1.66 लाख रुपये पर पहुंच गया है। कीमती धातुओं में ट्रंप के तहत नीतिगत अनिश्चितता प्रमुख कारक रही है। विशेष रूप से एशिया और यूरोप में पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों की एक नई लहर आक्रामक रूप से सोने और चांदी की व्यक्तिगत होल्डिंग्स बढ़ा रही है।

सोने ने भी वैश्विक बाजारों में अपनी तेजी जारी रखी और लगातार सातवें दिन इसमें वृद्धि दर्ज की गई। यह 79.13 डॉलर बढ़कर 5,087.48 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सोमवार को सोने की कीमत में पहली बार 5,000 डॉलर प्रति औंस का मनोवैज्ञानिक स्तर पार हो गया। इसमें 121.07 डॉलर या 2.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 5,110.24 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। निकट भविष्य में सफेद धातु की कीमतों में मुनाफावसूली और स्थिरीकरण के दौर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक वैश्विक जोखिम भावना कमजोर बनी रहती है और डॉलर पर दबाव बना रहता है, तब तक व्यापक रुझान सकारात्मक बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को 100 फीसदी टैरिफ की धमकी देने के हालिया कदम से तनाव और बढ़ गया है। कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है। इसने बाजारों को हिला दिया है और सोने की कीमतों की मांग को मजबूत किया है। एजेंसी

बैंकिंग हड़ताल से 4 लाख करोड़ रुपये के चेक क्लियरेंस में अटके

यूनियन ने कहा, पांच कार्य दिवस को तुरंत लागू करे सरकार

नई दिल्ली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की हड़ताल के चलते देशभर में कई जगहों पर जमा और निकासी जैसी शाखा बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। साथ ही, 4 लाख करोड़ रुपये के चेक क्लियरेंस में अटक गए। यूनियन की मांग सप्ताह में पांच कार्य दिवस को लागू करने की है। नौ यूनियनों के समूह यूएफबीयू की ओर से आयोजित यह हड़ताल 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक के विफल होने के बाद हुई।

यूएफबीयू की हड़ताल में सरकारी बैंकों की विभिन्न यूनियनों के 8 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने बताया, नकद लेनदेन प्रभावित हुए और बिल ट्रेडिंग, बिल डिस्काउंटिंग और ट्रेडिंग पर असर पड़ा। सरकारी बैंकों में कई जगहों पर ट्रेजरी संचालन भी बंद रहा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के महासचिव रूपम रॉय ने बताया, दिसंबर, 2023 में हुई चर्चाओं के बाद यह सहमति बनी थी कि सोमवार से शुक्रवार तक दैनिक कार्य समय में 40 मिनट की वृद्धि की जाएगी। शेष शनिवार को अवकाश घोषित किया जाएगा। एजेंसी

एफटीए पर सहमति से बाजार में तेजी, 2.11 लाख करोड़ बढ़ी पूंजी

वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख और भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर सहमति से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त में बंद हुए। बैंक और धातु कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी से भी बाजार बढ़त बनाने में कामयाब रहा, जिससे कंपनियों की संयुक्त पूंजी 2.11 लाख करोड़ बढ़ गई। ब्यूरो

319.78 अंक की बढ़त सेंसेक्स में

81,857.48 के स्तर पर हुआ बंद

▪ 82,000 के पार पहुंच गया था दिन में कारोबार के दौरान

126.75 अंक की बढ़त निफ्टी में 25,175.40 पर बंद

निफ्टी-50 के 34 शेयर बढ़त में बंद

17 शेयर बढ़त में

30 में से 17 कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे

▪ 13 कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

4.33% के सर्वाधिक लाभ में अदाणी पोर्ट्स

▪ एमएंडएम सबसे ज्यादा 4.19 फीसदी टूटा

1,803 कंपनियों के शेयर तेजी में रहे, 2,510 गिरावट में हुए बंद

इंडेक्स में भी तेजी

3.11% की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई धातु इंडेक्स में

बिकवाली जारी

3,068.49 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की विदेशी संस्थागत निवेशकों ने

8,999.71 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने

ऊर्जा क्षेत्र में भारत को सालाना 145 अरब डॉलर निवेश जुटाने की जरूरत

गोवा। सतत आर्थिक विकास और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों के बीच के अंतर को पाटने के लिए भारत को ऊर्जा क्षेत्र में 145 अरब डॉलर का वार्षिक निवेश जुटाने की जरूरत होगी।

वुड मैकेन्जी के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष जोशुआ न्गु ने इंडिया एनर्जी वीक में कहा, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए पूंजी का उपयोग रणनीतिक रूप से बिजली उत्पादन, ऊर्जा भंडारण और ग्रिड के तत्काल आधुनिकीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। जोशुआ न्गु ने कहा, भारत का अगला दशक निर्णायक है। भारत को तात्कालिक ऊर्जा सुरक्षा के जोखिम को कम करना होगा। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरी कम कार्बन उत्सर्जन वाली संरचना का निर्माण करना होगा। निवेश विकल्प यह तय करेंगे कि देश कार्बन बुनियादी ढांचे में फंसा रहेगा या कम कार्बन उत्सर्जन वाले औद्योगीकरण में विश्व का नेतृत्व करेगा। मैकेंजी ने कहा, विद्युत क्षेत्र भारत में उत्सर्जन का बड़ा स्रोत होने के साथ ऊर्जा परिवर्तन का इंजन भी है। एजेंसी

शून्य कार्बन उत्सर्जन और सतत आर्थिक विकास के अंतर को कम करने पर देना होगा जोर

2032 तक तीन नैनोमीटर वाले चिप्स निर्माण का लक्ष्य : वैष्णव

नई दिल्ली। सरकार का लक्ष्य 2032 तक आधुनिक स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले 3 नैनोमीटर नोड के उच्च तकनीक वाले छोटे चिप्स का निर्माण करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण के तहत छह श्रेणियों के चिप्स कंप्यूट, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नेटवर्किंग, पावर, सेंसर और मेमोरी पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना के तहत देश की कंपनियों को 70-75 फीसदी तकनीकी उत्पादों के विकास पर प्रमुख नियंत्रण मिलेगा। वैष्णव ने कहा, डिजाइन तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन निर्माण के मामले में हमें 3 नैनोमीटर तक पहुंचना होगा। 2029 तक चिप्स के निर्माण और डिजाइन की एक बड़ी क्षमता होगी। इनकी हमारे देश में लगभग 70-75 फीसदी एप्लिकेशन में व्यावहारिक रूप से आवश्यकता होती है। ब्यूरो

देश

मान पड़े नरम, कहा- एसवाईएल के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं

हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच सातवीं बैठक

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता करते सीएम सैनी व सीएम मान। सूचना विभाग

चंडीगढ़। सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच मंगलवार को बैठक हुई। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहली बार एसवाईएल के मुद्दे पर नरम पड़ते दिखाई पड़े। इस विवाद का हल अब पंजाब और हरियाणा के अफसर तलाशेंगे। दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर तथ्यों और मौजूदा परिस्थितियों पर बैठक करेंगे और यह विवाद कैसे निपट सकता है उसका एक सेंट्रल आइडिया ढूंढ़ेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच यह सातवीं बैठक थी।

बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में भगवंत मान ने कहा, हम भाई घनैया की धरती से आते हैं जिन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा भाई है। न हरियाणा का हक मरना चाहिए और न ही पंजाब का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि एसवाईएल से जुड़े मुद्दे पर आगे विस्तृत चर्चा के लिए अब दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के स्तर पर बैठकें होंगी। मान ने कहा कि अब अधिकारी नियमित रूप से मिलेंगे। महीने भर में तीन से चार बैठकें हो सकती हैं। ये बैठकें केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नहीं बल्कि नियमित रूप से होंगी और दोनों राज्यों के अधिकारी अपनी सरकारों को विचार-विमर्श की प्रगति से अवगत कराएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हुई बैठकों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त रुख अपनाते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब पहले से पानी का मार झेल रहा है।

चाची के ताने से आहत भाई व बहन ने खाया जहर, मौत

बांदा। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में चाची के ताने से आहत होकर भाई-बहन ने जहर खाकर जान दे दी। ताऊ को पांच सौ रुपये देने को लेकर भी कलह की बात सामने आई है। प्रकाश चंद्र के पुत्र आनंद प्रकाश (30) व पुत्री चंचल (34) सोमवार की दोपहर घर से निकले थे। करीब चार किमी दूर बागै नदी किनारे उन्होंने जहर खा लिया। संवाद

शंकराचार्य विवाद के बीच सरकार के समर्थन में जीएसटी उपायुक्त का इस्तीफा

अयोध्या। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से आहत होकर स्टेट जीएसटी के उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने मंगलवार को सीएम योगी और सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को संबोधित इस्तीफा आयुक्त ग्रेड-1 संतोष कुमार को सौंपा है। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि प्रयागराज में प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी से वह आहत हैं। वह प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। यदि कोई प्रदेश सरकार के मुखिया के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करता है, तो उसका विरोध करना उनका राजकीय धर्म है। संवाद

प्रशांत सिंह

यूपी गैंगस्टर एक्ट और बीएनएस में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार से मांगा जवाब

राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 (संगठित अपराध) के बीच सांविधानिक स्तर पर कोई टकराव है।

कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिया। पीठ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में यूपी गैंगस्टर एक्ट की कई धाराओं को चुनौती दी गई है। इनमें धारा 3 (दंड), धारा 12 (विशेष अदालतों द्वारा प्राथमिकता से सुनवाई), धारा 14 से 17 (संपत्ति की कुर्की, रिहाई और अधिग्रहण से जुड़ी जांच) और 2021 के नियमों की कुछ धाराएं शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ब्यूरो

देश में यात्री विमान बनाने के लिए अदाणी-एम्ब्रेयर के बीच करार

साझेदारी से विमान निर्माण का हब बनेगा भारत

नई दिल्ली। अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर मिलकर भारत में यात्री विमानों का निर्माण करेंगे। यह साझेदारी छोटे शहरों के बीच हवाई संपर्क बेहतर बनाने में मदद करेगी। दोनों कंपनियों ने मंगलवार को इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के तहत भारत में विमान निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव (एमआरओ), बिक्री के बाद की (आफ्टर-सेल्स) सेवाएं और पायलट प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। शुरुआत में देश में विमान असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी और बाद में धीरे-धीरे स्वदेशी हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। कंपनियों ने एक बयान में कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत और सरकार की उड़ान योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। ब्यूरो

रोजगार पैदा होंगे : इस मौके पर अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि क्षेत्रीय विमानन देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। उड़ान जैसी योजनाओं ने टियर-2 और टियर-3 शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। ऐसे में देश में एक स्वदेशी क्षेत्रीय विमानन पारितंत्र की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी के अनुसार इस पहल से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत को वैश्विक एयरोस्पेस उद्योग में नई पहचान मिलेगी। एम्ब्रेयर कमर्शियल एविएशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जन मेइजर ने कहा कि भारत एम्ब्रेयर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। यह साझेदारी हमारी एयरोस्पेस विशेषज्ञता को अदाणी ग्रुप की मजबूत औद्योगिक क्षमताओं के साथ जोड़ती है।

एम्ब्रेयर की पहले से मौजूदगी : एम्ब्रेयर की भारत में पहले से मजबूत मौजूदगी है। देश में इसके करीब 50 विमान वाणिज्यिक, रक्षा और व्यापारिक उड्डयन सेवाओं में इस्तेमाल हो रहे हैं। वायुसेना भी एम्ब्रायर के नेत्रा विमान का उपयोग करती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। आगामी 20 वर्षों में देश को लगभग 2,000 विमानों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

यूजीसी नियमों के खिलाफ यूपी में जगह जगह प्रदर्शन, भाजपा नेता भी हुए मुखर

लखनऊ। यूजीसी नियमों के खिलाफ यूपी में अलीगढ़, संभल और कुशीनगर समेत कई जगह प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन और क्षत्रिय महासभा ने यूजीसी का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए।

संभल के चंदौसी में ब्राह्मण शक्ति संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। गोंडा सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह का पोस्ट मंगलवार को सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं, अकसर मुखर रहने वाले विधायक के पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मसले पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। विधायक ने बिना किसी संगठन का नाम लिए फेसबुक पोस्ट में लिखा है...इतिहास के दोहरे मापदंडों पर गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के अत्याचारों को भुला दिया जाता है, लेकिन भारतीय समाज के कुछ वर्गों को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिह्नित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो

लखनऊ में करणी सेना का प्रदर्शन।

खून से लिखा ज्ञापन

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को नए यूजीसी बिल के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र सुबह से ही विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खून से लिखा हुआ एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी व एसडीएम को सौंपा। ब्यूरो

पूर्व शिक्षा मंत्री ने दी भाजपा से त्यागपत्र की चेतावनी

झांसी। यूजीसी के नए नियम के विरोध में बीजेपी के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यूजीसी का घातक जाति संघर्ष को बढ़ाने वाला कानून वापस नहीं हुआ तो वह भाजपा से त्यागपत्र दे देंगे। भाजपा सरकार को विचार कर इस नियम को तत्काल वापस लेना चाहिए। पूर्व मंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूजीसी के प्रावधानों का खुला विरोध करता हूं। ब्यूरो

यूजीसी मामले में कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यह भाजपा की चाल है। इन नियमों से पीडीए समाज को कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकतर संस्थाओं पर गैर पीडीए समाज के लोग काबिज हैं।

-अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

कफ सिरप : विकास नरवे सहित 3 आरोपी नेपाल सीमा से गिरफ्तार

लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस को सफलता मिली है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और एसआईटी ने मंगलवार सुबह 50-50 हजार रुपये के इनामी विकास सिंह नरवे, आकाश पाठक सहित तीन आरोपियों को सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। तीनों नेपाल भागने की कोशिश में थे। सभी को वाराणसी लाकर पूछताछ की जा रही है और बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

आजमगढ़ निवासी विकास सिंह नरवे ने अपनी फर्म देवनाथ फार्मेसी के जरिये कफ सिरप की 5.13 लाख शीशियां मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स को बेची थीं, जिनकी कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई है। वह शुभम का करीबी था व तस्करी से जुड़े पैसों का लेनदेन संभालता था। वहीं, मैदागिन निवासी आकाश पाठक ने फर्जी फर्म मेड रेमेडी लाइफकेयर बनाई थी और वह नेटवर्क में शुभम दाहिना हाथ था। तीसरा आरोपी जौनपुर निवासी अंकित श्रीवास्तव है। ब्यूरो

भारतीय रेल

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2025/Tk-II/22/6/3 (ZITMS) नई दिल्ली, दिनांक: 27.01.2026

शुद्धिपत्र संख्या 11

विषय : ई-निविदा क्रमांक टीएम-2501 शून्य एकीकृत रेलपथ निगरानी प्रणाली (ZITMS) की खरीद और इसके संचालन और रखरखाव के लिए।

निविदा की अंतिम तिथि, दिनांक 28.01.2026 (बुधवार 15:00 बजे) से बढ़ाकर 26.02.2026 (बृहस्पतिवार 11:00 बजे) कर दी गई है।

निविदा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(अनुराग कुमार)
कार्यकारी निदेशक/रेलपथ आधुनिकीकरण
रेलवे बोर्ड
दूरभाष 011-47845530
ईमेल: anuragkumar.dtk2@gmail.com

295/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

नौएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, (उ.प्र.)
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अर्ह निविदाकारों से निम्न जॉब हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिन्हें निम्नानुसार तिथियों तक अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई-निविदाओं को उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों पर खोला जाएगा। निविदा संबन्ध में समस्त विवरण व शर्तें नौएडा प्राधिकरण की अधिकारिक website: www.noidaathorityonline.in & https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधित एवं अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट देखते रहें।

ए) फेस- टेण्डर कार्य:-

क्र सं	जॉब संख्या	कार्य का नाम	निविदा की धनराशि (रू० लाख में)
1.	14/उ.म.प्र/वरि.प्र (व.स.-7)/ई०नि०/2025-26	सड़कों का अनुरक्षण (सैक्टर-88 में डी० एस० सी० मार्ग से कैन्ट आर०ओ० 45.00 क्रासिंग तक मी० चौडी फूलमण्डी सड़क पर आर०सी०सी० फुटपाथ एवं रिसरफेसिंग का कार्य), नौएडा।	81.27
2	19/उ.म.प्र./वरि.प्र. (व.स.-9)/ई०नि० /2025-26	सड़कों का अनुरक्षण (सैक्टर-124 व 125 के मध्य 45.00 मी० चौडी सडक, की सर्विस रोड नाली का निर्माण कार्य), नौएडा।	82.56
3	17/उ.म.प्र./वरि.प्र. (व.स. 10)/ई०नि०/2025-26	सैक्टर-150 में ए०टी०एस० प्रिस्टीन सोसाईटी के सामने पुस्ता सडक के कच्चे हिस्से म इन्टरलॉकिंग टाईल रोड लगाये जाने एवं मार्किंग पेन्ट कराये जाने का कार्य, नौएडा।	55.09
4	18/उ.म.प्र./वरि.प्र.(व.स.-10)/ई०नि०/2025-26	विनोद कसाना और शमी प्रधान के घर के सामने ग्राम-कोण्डली बांगर में सी० सी०सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा	48.94
5	06/उ.म.प्र./परि.प्र. (व.स-8)/ई०नि०/2025-26	सड़कों का अनुरक्षण (सेक्टर-91 में भुमिया माता जी मन्दिर परिसर में सी० सी० रोड एवं अन्य विविध कार्य), नौएडा।	61.28
6	13/उ.म.प्र./वरि.प्र. (व.स.-8) /ई०नि०/2025-26	नालियों का अनुरक्षण (ग्राम सलारपुर में सिंचाई नाले पर भंगेल से सैक्टर-101 मैट्रो स्टेशन तक नालियों की मरम्मत एवं अन्य सिविल सम्बन्धित मरम्मत कार्य), नौएडा।	59.20

उपरोक्त निविदा को दिनांक 11.02.2026 सायं 5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 12.02.2026 को 11.00 बजे खोली जायेगी।

बी) रि- टेण्डर कार्य:-

क्र सं	जॉब संख्या	कार्य का नाम	निविदा की धनराशि (रू० लाख में)
7	13/उ.म.प्र./वरि.प्र. (व.स-9)/ई०नि०/2025-26	नालियों का अनुरक्षण (ग्राम दल्लुपुरा में आर०सी०सी० नाली का निर्माण एवं ढकने का कार्य), नौएडा।	69.73

उपरोक्त निविदा को दिनांक 03.02.2026 सायं 5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 04.02.2026 को 11.00 बजे खोली जायेगी।

महाप्रबन्धक (सिविल) नौएडा

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

एजुकेशन & कॅरिअर

सीमित निराशा स्वीकारें, लेकिन असीम आशा कभी न छोड़ें।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

स्टेनोग्राफर व ग्रुप-सी के पद रिक्त

4871 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष
यहां आवेदन करें : hssc.gov.in

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना ■ 78 पद

अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि
27 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
bpssc.bihar.gov.in

आईसीडीएस में निकली भर्ती ■ 50 पद

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
31 जनवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष
यहां आवेदन करें
upanganwadibharti.in

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ■ 572 पद

ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 04 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष
यहां आवेदन करें : rbi.org.in

नालको में रोजगार के अवसर ■ 48 पद

मैनेजर के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
02 फरवरी, 2026
पात्रताएं
इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
nalcoindia.com

इंडिया एक्जिम बैंक में रिक्तियां ■ 20 पद

डिप्टी मैनेजर के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
15 फरवरी, 2026
योग्यताएं
ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
eximbankindia.in

यहां भी रोजगार के अवसर ...

- एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड : सलाहकार का पद रिक्त।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 07 फरवरी, 2026
- ddpdoo.gov.in
- ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी : प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 04 फरवरी, 2026
- thsti.res.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

आप सबको खुश नहीं कर सकते

सिर्फ दूसरों को तवज्जो देने की आदत आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं, इसलिए अपना महत्व भी समझें

माइकल गेरवाइस
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

अक्सर हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं, हमारी तारीफ हो रही है या नहीं। धीरे-धीरे यही आदत हमारे आत्म-सम्मान को दूसरों के हाथों में सौंप देती है। सच यह है कि हर इन्सान की सोच अलग होती है, इसलिए सबको खुश करना संभव नहीं। जब आप खुद को समझना, स्वीकार करना और अपने मूल्यों, मेहनत व लक्ष्यों पर ध्यान देना सीखते हैं, तो अंदर से संतुष्टि मिलती है। यही आंतरिक संतुष्टि आपको मजबूत बनाती है और दूसरों की राय आपके आत्म-सम्मान को प्रभावित नहीं कर पाती।

Harvard Business Review

■ आंतरिक संतुष्टि विकसित करें
अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आपके मूल्य क्या हैं। जब आप अपने काम और फैसले इन्हीं मूल सिद्धांतों के अनुसार लेते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से, तो भीतर से संतुष्टि मिलती है। साथ ही, अपनी छोटी-बड़ी उपलब्धियों और अच्छी खूबियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना सीखें, क्योंकि इससे खुद पर भरोसा बढ़ता है। ऐसी गतिविधियां अपनाएं, जो आपको सुकून और खुशी दें और अपने लक्ष्यों पर शांत मन से काम करते हुए हर प्रगति पर खुद को शाबाशी दें। यही आदतें आपको संतुलित और आत्मविश्वासी बनाती हैं।

■ अपनी समझ को प्राथमिकता दें
अपने भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों को सच मान लेने के बजाय पहले उन्हें पहचानें और उनकी जगह सकारात्मक और यथार्थपूर्ण सोच रखें। मन को समझने के लिए रोज थोड़ा समय अकेले बिताएं, ताकि आप अपनी भावनाओं, जरूरतों और थकान को पहचान सकें। जिन लोगों की बातें आपको कमजोर महसूस कराती हैं या आपकी ऊर्जा खत्म कर देती हैं, उनसे दूरी बनाना गलत नहीं है। यह आत्म-सुरक्षा का हिस्सा है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की राय उसके अपने अनुभव और सोच से बनती है, इसलिए किसी का निर्णय आपकी पूरी काबिलियत या मूल्य को तय नहीं करता। अंत में,

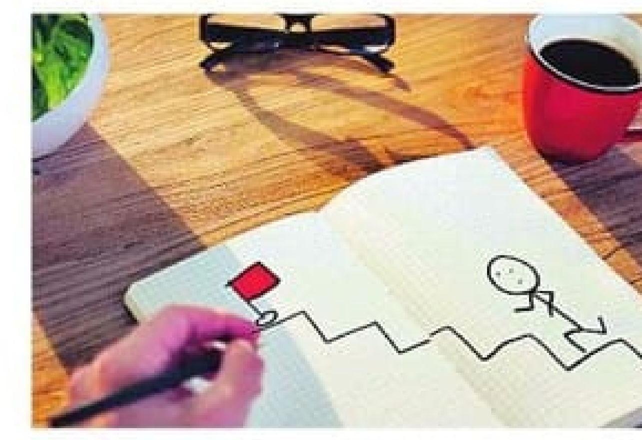

अपने लिए खुद मार्गदर्शक बनें और बाहरी प्रतिक्रियाओं की जगह अपने सही-गलत की समझ को प्राथमिकता दें।

■ सहायता लेना कोई गलत नहीं
अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दें, जो आपको समझें, सम्मान दें और जिनके साथ आप सुरक्षित महसूस करें। अगर ऐसा कोई तुरंत न मिले, तो खुद के लिए ही मित्र बनें। साथ ही, सोशल मीडिया और लगातार खबरें देखने से मन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, इसलिए इनके प्रभाव को सीमित करें और बार-बार दूसरों से पुष्टि पाने की आदत से बाहर निकलने की कोशिश करें। यदि यह समस्या गहरी हो और अकेले संभालना मुश्किल लगे, तो पेशेवर सहायता लेना बिल्कुल सही कदम है।

खुद को परखें

1. हाल ही में खबरों में छाई फुलकारी कढ़ाई की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी?
   (a) राजस्थान और गुजरात
   (b) महाराष्ट्र और कर्नाटक
   (c) पंजाब और हरियाणा
   (d) उत्तर प्रदेश और बिहार
2. उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) किस भारतीय कानून के अंतर्गत संचालित होती है?
   (a) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
   (b) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
   (c) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
   (d) कंपनी अधिनियम, 2013
3. पांगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
   (a) सिक्किम (b) त्रिपुरा
   (c) असम (d) मेघालय

उत्तर : 1.c, 2.c, 3.a

फेलोशिप प्रोग्राम

एनसीएएसआर ग्रीष्मकालीन अनुसंधान फेलोशिप

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), बंगलूरू द्वारा जेएनसीएएसआर ग्रीष्मकालीन अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम (एसआरएफपी) 2026 की पेशकश की जा रही है। इसके लिए विज्ञान या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत वे उम्मीदवार पात्र हैं, जो वर्तमान में बीएससी, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमटेक, एमएस या समकक्ष पाठ्यक्रमों में नामांकित हों और जिनकी विज्ञान, इंजीनियरिंग या अंतःविषयक क्षेत्रों में मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो। उम्मीदवारों के 10वीं और 12वीं कक्षा में मुख्य विषयों में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक तथा वर्तमान डिग्री के सेमेस्टर में प्रथम श्रेणी होना अनिवार्य है। चयनित फेलोज को प्रतिमाह 10,000 रुपये की फेलोशिप के साथ न्यूनतम यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक लिंक aitchnu.tech/jncasr/srfp/landing# पर जाकर 31 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप अलर्ट

एनजीएसएफ इंटर्नशिप प्रोग्राम-2025

नेक्स्ट जेन साइंटिस्ट्स फाउंडेशन (एनजीएसएफ) द्वारा इंटर्नशिप-2025 के जरिये उम्मीदवारों को जीवन विज्ञान में काम करने का अवसर देती है। यह दो महीने (कम से कम 56 दिन) या तीन महीने (कम से कम 84 दिन) की होगी। पात्र छात्र तीन साल के स्नातक के दूसरे साल, चार साल के स्नातक के दूसरे/तीसरे साल, दो साल के मास्टर के पहले साल, या पांच साल के एकीकृत प्रोग्राम के दूसरे/तीसरे/चौथे साल के हो सकते हैं। छात्र किसी भी भारतीय संस्थान में अपने संस्थान के बाहर प्रोफेसर/प्रधान अन्वेषक (पीआई) की प्रयोगशाला में काम कर सकते हैं, बशर्ते पीआई के पास तीन साल का अनुभव और कम से कम तीन शोध पत्र प्रकाशित हों। चयनित इंटर्न को 6,000 रुपये प्रतिमाह तक वजीफा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mrvhz88u पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट — हफ्ते की परीक्षाएं

आईओसीएल गैर-कार्यकारी कार्मिक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 30 जनवरी, 2026
- यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) होगा। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस व सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/8u3sejwe

आरपीएससी सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 01 फरवरी, 2026
- इस परीक्षा में राजस्थान से संबंधित व संबंधित विषय से 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे 30 मिनट निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** rpsc.rajasthan.gov.in

सामान्य ज्ञान

मद्रास हेजहोग

■ क्या है
मद्रास हेजहोग मुख्यत: दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पाया जाने वाला एक छोटा स्तनधारी जीव है, जिसे स्थानीय रूप से मुलेली कहा जाता है। इसे नंगे पेट वाला हेजहोग भी कहा जाता है।

■ चर्चा में क्यों?
हाल ही में पहली बार तमिलनाडु के वन विभाग ने जिले के थेरी जंगलों में दुर्लभ स्तनधारी प्रजाति मद्रास हेजहोग पर विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।

■ विशेषताएं
इसकी पीठ पर नुकीले कांटे और पेट पर मुलायम सफेद फर होता है। इसके कांटे लोमड़ी और नेवले जैसे शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह एक निशाचर प्रजाति है, जो खतरे के समय खुद को गेंद की तरह गोल कर लेती है।

■ आबादी में गिरावट के कारण
इसकी आबादी में भारी गिरावट का मुख्य कारण पौराणिक मान्यताओं के चलते हुआ शिकार रहा है, जिनमें इसके कांटों और मांस को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता था। इसी कारण आज यह आईयूसीएन की संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है।

टेक-टॉक

Gadgets Ai Technology

नई स्मार्ट चिप, कम खपत में तेज नतीजे

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट चिप तैयार की है, जो न केवल ऊर्जा की खपत को बहुत कम करेगी, बल्कि भारी मात्रा में डेटा को पहले से कहीं अधिक तेज गति से प्रोसेस करेगी।

आज उच्च प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई स्मार्ट चिप विकसित की है, जो न केवल ऊर्जा की खपत को बहुत कम करती है, बल्कि भारी मात्रा में डेटा को पहले से कहीं अधिक तेज गति से संसाधित (प्रोसेस) कर सकती है। यह चिप इटली के पॉलिटेक्निको डी मिलानो विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं बायोइंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। इस परियोजना का नेतृत्व प्रोफेसर डेनिएले इलमिनी ने किया और शोधकर्ता पियरजूलियो मानोच्ची इसके प्रमुख लेखक हैं।

■ एएनआईएमएटीई परियोजना से शुरुआत
यह शोध एनालॉग इन-मेमोरी कंप्यूटिंग विद एडवांस्ड डिवाइस टेक्नोलॉजी (एएनआईएमएटीई) परियोजना के अंतर्गत हुआ, जो प्रो. इलमिनी के क्लोज्ड-लूप इन मेमोरी कंप्यूटिंग (सीएल-आईएमसी) विचार पर आधारित है। इसका उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटरों की तुलना में 5000 गुना कम ऊर्जा में गणनाएं करना था।

■ इन-मेमोरी कंप्यूटिंग तकनीक
पारंपरिक कंप्यूटरों में डेटा को बार-बार मेमोरी से प्रोसेसर तक लाना-ले जाना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं। यह नई चिप इन-मेमोरी कंप्यूटिंग तकनीक अपनाती है, जिससे गणनाएं सीधे मेमोरी के भीतर होती हैं और डेटा ट्रैफिक समाप्त हो जाता है।

■ उन्नत चिप संरचना
इस चिप में 64×64 आकार के दो प्रोग्रामेबल रेसिस्टिव मेमोरी एरे लगे हैं। ये एरे एसआरएएम तकनीक पर आधारित हैं, जो तेज और स्थिर मेमोरी मानी जाती है। इसमें प्रतिरोध स्तर बदलकर अलग-अलग गणनाएं की जा सकती हैं।

■ एनालॉग प्रोसेसिंग का प्रयोग
चिप में ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर जैसे घटक जोड़े गए हैं, जिससे यह चिप जटिल गणनाएं अधिक कुशलता से कर सकती है।

■ बेहतर प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत
परीक्षणों में इस चिप ने पारंपरिक डिजिटल सिस्टम जितनी सटीकता दिखाई, लेकिन इसके साथ ही कम बिजली खपत, कम समय में परिणाम, कम सिलिकॉन स्थान की आवश्यकता, जैसे लाभ सामने आए। वैज्ञानिकों के अनुसार, 'यह चिप औद्योगिक स्तर पर एनालॉग इन-मेमोरी कंप्यूटिंग को संभव बनाती है। इससे विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ऊर्जा लागत कम होगी।' वहीं शोधकर्ता मानोच्ची का कहना है कि यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थानों ने भाग लिया।

■ भविष्य की संभावनाएं
यह शोध भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर, 5जी और 6जी नेटवर्क, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह नई स्मार्ट चिप न केवल कंप्यूटिंग को तेज और सस्ता बनाएगी, बल्कि इसे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भी बनाएगी। इन-मेमोरी कंप्यूटिंग आने वाले समय में तकनीकी दुनिया की रीढ़ बन सकती है। यह शोध प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित हुआ है।

व्हाट्सएप पर भी आएगा पेरेंटल कंट्रोल फीचर

व्हाट्सएप जल्द ही एक नया 'पैरेंटल कंट्रोल' फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे माता-पिता बच्चों के व्हाट्सएप उपयोग पर नजर रख सकेंगे। यह फीचर बच्चों के व्हाट्सएप अकाउंट को पेरेंट्स के अकाउंट से लिंक करने की अनुमति देगा। इससे अनजान नंबरों से कॉल/मैसेज पर रोक लगेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। इस फीचर को नाबालिगों को खास ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। इससे बच्चे केवल उन लोगों से बात कर पाएंगे, जो उनके माता-पिता के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं। इससे माता-पिता बच्चों की चैट और कॉल को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे यह देख सकते हैं कि अकाउंट का उपयोग कैसे किया जा रहा है। पेरेंट्स बच्चों की प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट इंफो जैसी सेटिंग्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे। यह फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही सभी के लिए जारी किया जा सकता है।

आसानी से ढूंढ सकेंगे लंबे और शॉर्ट वीडियोज

अब आप यूट्यूब पर आसानी से लंबे वीडियो और शॉर्ट्स और दूसरे वीडियो फॉर्मेट्स में अंतर देखते हुए सर्च कर सकेंगे। इसके लिए यूट्यूब नए एडवांस्ड सर्च फिल्टर ला रहा है। इसके तहत यूट्यूब ने डेडीकेटेड शॉर्ट फिल्टर को लागू करने का फैसला लिया है जिसके बाद यूजर्स लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, शॉर्ट्स फॉर्म क्लिप के बीच देखने का चुनाव करने के लिए स्पेसिफिक ब्राउजिंग कर सकेंगे। इसके जरिए यूट्यूब की कोशिश है कि अपने तेजी से बढ़ते शॉर्ट्स के दर्शकों को और आसानी से इनको देखने की सुविधा दी जा सके, जिससे ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक से मुकाबले में आगे निकल सकें।

आने वाला है

अगले महीने यामाहा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर

जापानी वाहन निर्माता कंपनी यामाहा अगले महीने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ईसी-06 बाजार में उतार सकती है। इसकी कीमत डेढ़ से एक लाख साठ हजार हो सकती है। कंपनी के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन शहरों की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ईसी-06 में 4.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसमें 4 किलोवाट घंटा की उच्च क्षमता वाली बैटरी है। इसे साधारण चार्जिंग से लगभग नौ घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक हैं। ईसी-06 में बिल्ट-इन टेलीमैटिक्स यूनिट एक सिम के साथ है, जिससे कनेक्टिविटी के साथ डेटा का एक्सेस भी मिलेगा।

न्यू लॉन्च

पानी और डिटर्जेंट बिना भी होगी सफाई

व्हर्लपूल ने भारतीय बाजार में अपनी नई फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 'व्हर्लपूल एक्सपर्ट केयर' लॉन्च की है, जिसकी खासियत ओजोन फ्रेश एअर टेक्नोलॉजी है। कंपनी के अनुसार, यह मशीन बिना पानी और डिटर्जेंट के भी कपड़ों को ताजा बना सकती है। इसमें बिल्ट-इन ओजोनाइजर ऑक्सीजन को ओजोन में बदलकर ड्रम में छोड़ता है, जिससे बदबू और बैक्टीरिया खत्म होते हैं। यह तकनीक खासतौर पर ड्राई-क्लीन फैब्रिक्स के लिए उपयोगी है। मशीन में स्टीम वॉश, जीरो प्रेशर फिल और 1400 आरपीएम स्पिन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 24,500 रुपये है।

आज का दिन

28 जनवरी, 1901

अमेरिका के मिल्वौकी शहर में 'अमेरिकन बेसबॉल लीग' की स्थापना हुई। इसने आठ टीमों के साथ 140-मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे यह नेशनल लीग की दूसरी प्रमुख पेशेवर लीग बन गई।

- **1912:** अमेरिकी चित्रकार जैक्सन पोलक का जन्म हुआ था।
- **1915:** रेवेन्यू कटर सर्विस और लाइफसेविंग सर्विस को मिलाकर यूएस कोस्ट गार्ड का गठन हुआ।
- **1986:** अमेरिकी अंतरिक्ष यान चैलेंजर फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया।
- **2021:** अभिनेत्री सिसिली टायसन का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष दशमी।
कल : जया एकादशी व्रत, शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** दिन में 13.30 से 15.00 तक।

■ सूर्योदय : 07.15
■ सूर्यास्त : 17.54
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 09 माघ मास शक 1947, माघ मास 16 प्रविष्टे, 09 सावान हिजरी 1447, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी 13.55 तक उपरांत द्वादशी, रोहिणी नक्षत्र 07.31 तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र 29.28 तक तदोपरांत आर्द्रा नक्षत्र, ऐंद्र योग 20.26 तक उपरांत वैधृति योग, विष्टि (भद्रा) करण 13.55 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में 18.29 बजे।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : योजनाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। विश्वासपात्र से धोखा हो सकता है।

वृष : अर्थ प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

मिथुन : स्वास्थ्य नरम रहेगा। अकारण विवाद से परेशानी होगी। संतान से निराशा होगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

कर्क : सुखद समाचार मिलेगा। राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। चल-अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है।

सिंह : समाज में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी अनुकूल रहेंगे। राजकाज में सफलता मिल सकती है।

कन्या : धैर्य रखने पर कार्य सफल होंगे। सरकारी कार्य में आंशिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय में लाभ होगा।

तुला : सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय में उतावलेपन से हानि होगी।

वृश्चिक : नौकरी में मन नहीं लगेगा। पूर्व नियोजित कार्य अधूरा रहेगा। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

धनु : कॅरिअर में उन्नति का अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिल सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा।

मकर : मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। अत्यधिक विश्वास से कष्ट होगा। साझेदारी में धैर्य बनाए रखें।

कुंभ : पूर्व नियोजित योजना सफल होगी। शुभचिंतकों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

मीन : राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रहेगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र का विकास होगा।

जन्मदिन

श्रुति हासन, अभिनेत्री

इस वर्ष आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। अटकी योजनाओं में अनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति से संतुष्ट रहेंगे। शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख साधनों पर व्यय होगा। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतें। इस वर्ष स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सुडोकू

	9			3		1		
		4		7				
	3	1	9	6				4
3	6		7					
	2						1	
					6		5	7
1				8	4	6	3	
				9		8		
		3		2			7	

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

7	9	2	4	3	8	1	6	5
6	8	4	1	7	5	2	9	3
5	3	1	9	6	2	7	8	4
3	6	5	7	1	9	4	2	8
4	2	7	8	5	3	9	1	6
9	1	8	2	4	6	3	5	7
1	7	9	5	8	4	6	3	2
2	5	6	3	9	7	8	4	1
8	4	3	6	2	1	5	7	9

डेली हेल्थ कैप्सूल

अडूसा से ठीक होती हैं कई बीमारियां

अडूसा से आर्थराइटिस, बैक्टीरिया संक्रमण, टीबी और ब्लीडिंग (रक्तस्राव) जैसी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं।

अडूसा या वासाका एक औषधीय पौधा है। यह श्वसन रोगों जैसे-सर्दी, खांसी, गले में खराश, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस में अधिक आराम पहुंचाता है। साथ ही यह गले में सूजन, खराश बुखार, डेंगू, डायरिया, हार्ट बर्न और पेट दर्द में भी फायदेमंद है। आप अडूसा की पत्तियों को उबालकर इसमें शहद डालकर सेवन करें। इससे लाभ मिलेगा।

इसमें मौजूद तत्व मुंह के छालों, अंदरूनी या बाहरी घाव में लाभ पहुंचाते हैं। अडूसा की सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर सेवन करने से ब्लीडिंग डिसऑर्डर में लाभ मिलता है। अडूसा में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण वाले स्थान पर अडूसा के पत्तों का लेप लगाने से लाभ मिलता है। इससे त्वचा संक्रमण दूर करने में मदद मिलती है। अडूसा में एंटीइंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण घुटनों में दर्द है, तो अडूसा के पाउडर का पानी के साथ सेवन करें। आप इसकी पत्तियों को पीसकर लेप की तरह घुटने पर लगा सकते हैं। इससे मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में सहायता मिलती है। यह रक्त को भी शुद्ध करता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली महिलाएं और छोटे बच्चों को अडूसा के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज रोगी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें।
-डॉ. राजीव पुंडीर
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 293

नए अवसरों का द्वार

भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर मंगलवार को हस्ताक्षर हुए। हाल के दिनों का यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता है जो दो अरब लोगों का बाजार तैयार करता है। बहरहाल, 16वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक और दोनों पक्षों के नेताओं का संवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। इस अवसर पर कई अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए ताकि आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके और रिश्तों को मजबूती प्रदान की जा सके। उदाहरण के लिए दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ की सामरिक साझेदारी के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया है। भारत और यूरोपीय संघ रक्षा और सुरक्षा पर सहयोग को बेहतर बनाएंगे। गतिशीलता पर सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा भी सहमति से तय किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ सेवाओं के क्षेत्र में कई उप क्षेत्रों को एक-दूसरे की प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए खोलेंगे। यूरोपीय संघ ने भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद कामकाजी वीजा देने का भी वचन दिया है।

जहां तक व्यापार समझौते की बात है, यह कानूनी अनिवार्यताएं पूरी होने के बाद ही लागू होगा लेकिन इससे जो हासिल हुआ है वह उल्लेखनीय है। वर्ष 2024-25 में भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार करीब 136.54 अरब डॉलर का था। भारत ने उस वर्ष 75.85 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जबकि उसका आयात 60.68 अरब डॉलर का रहा। पैमाने को देखते हुए व्यापार बहुत तेजी से बढ़ सकता है। भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25 फीसदी और वैश्विक व्यापार में एक तिहाई हिस्सेदारी रखते हैं। दोनों पक्षों का सेवा क्षेत्र में भी गहरा कारोबारी रिश्ता है। इस बात पर सहमति बनी है कि यूरोपीय संघ भारत से आयात होने वाली वस्तुओं के लिए मूल्य के आधार पर 99.5 फीसदी पर शुल्क कम करेगा जबकि भारत 92 फीसदी से अधिक वस्तुओं पर शुल्क को उदार बनाएगा। समझौता लागू होते ही भारत मूल्य के हिसाब से 30 फीसदी व्यापार वस्तुओं पर शुल्क को शून्य कर देगा और इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) पर रियायत नहीं दी है। यद्यपि उसने यह सहमति दी है कि किसी भी अन्य देश को दिया गया लचीलापन भारत को भी प्रदान किया जाएगा।

इस एफटीए को अंतिम रूप देना एक कामयाबी है और दोनों पक्षों की नियम आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। परंतु भारत को कम से कम तीन अहम मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पहला, यह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विकल्प नहीं है। अमेरिका अभी भी मिलेजुले संकेत दे रहा है लेकिन भारत को एक पारस्परिक लाभकारी समझौते तक पहुंचने के प्रयास जारी रखने चाहिए। लंबे समय तक अमेरिकी बाजार की पहुंच खोने की आशंका से बचना बहुत आवश्यक है। दूसरा, भारत को अपनी पूरी व्यापार नीति की समीक्षा करनी चाहिए और शुल्कों को उल्लेखनीय रूप से कम करना चाहिए। भारत ने यूरोप के प्रति खुलापन दिखाया है इसलिए सामान्य रूप से शुल्कों को कम करना अब आसान होना चाहिए। आगामी केंद्रीय बजट इस प्रक्रिया को सार्थक तरीके से शुरू करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पुनर्मूल्यांकन भी जरूरी है जो वास्तव में व्यापार बाधाएं ही हैं।

भारत को यदि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना है तो यह अहम है। अब उसे व्यापक क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं मसलन 'प्रशांत पार साझेदारी का व्यापक और प्रगतिशील समझौता' आदि का हिस्सा बनने पर विचार करना होगा। तीसरा भारत को अब आंतरिक सुधारों को और अधिक आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाना होगा। वह केवल तभी व्यापार समझौतों का लाभ ले पाएगा जब भारत के व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। एफटीए की एक आम आलोचना यह होती है कि वे भारतीय व्यवसायों को लाभ नहीं पहुंचाते। ऐसा प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण होता है। आंतरिक सुधार भविष्य में ऐसे नतीजों से बचने में मददगार साबित हो सकते हैं।

समृद्धि हासिल करने का एक रास्ता यह भी

हम यूरोप की औद्योगिक क्रांति पर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोएल मोकिर के काम और उनके लेखन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बता रहे हैं नौशाद फोर्ब्स

पिछले वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एगियों और पीटर हॉविट को दिया गया। उन्हें यह समझाने के लिए पुरस्कृत किया गया कि नवाचार कैसे आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करता है। डॉ. मोकिर जिन्हें आधा पुरस्कार दिया गया उन्हें उन किताबों के लिए जाना जाता है जिनमें उन्होंने समझाया है कि कैसे विभिन्न देश दीर्घकालिक तकनीकी बदलाव और औद्योगीकरण से विकसित होते हैं।

डॉ. मोकिर की औद्योगिक क्रांति की कहानी ज्ञान के क्रमिक संचय की कहानी है। इस ज्ञान का बड़ा हिस्सा, विशेषकर ब्रिटेन में, वह जिसे निर्देशात्मक ज्ञान कहते हैं, ऐसा ज्ञान है जिसने अधिक कुशल स्टीम इंजन या कपास कातने का बेहतर तरीका खोजा। यह एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे उनसे पहले कई लोग बता चुके हैं। नई मशीनें अत्यंत चतुराई से बनाई गई थीं, लेकिन वे वैज्ञानिक खोज पर आधारित नहीं थीं। वे कुशल कारीगरों द्वारा वर्षों तक किए गए प्रयोग और सुधार का परिणाम थीं। डॉ. मोकिर की अंतर्दृष्टि यह दिखाती है कि विज्ञान अब भी एक ज्ञान-भंडार और सोचने के तरीके के रूप में आवश्यक भूमिका निभा रहा था, जो आविष्कारकों के दिमाग में मौजूद था जब वे प्रयोग कर रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को महान कारीगरों की मौलिकता के साथ जोड़कर उद्यमियों ने तकनीकी नवाचार को बनाए रखा और दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की।

डॉ. मोकिर ने हाल ही में 'टू पाथ्स टु प्रॉस्पेरिटीः कल्चर ऐंड इंस्टीट्यूशन्स इन यूरोप ऐंड चाइना, 1000-2000' नामक नई पुस्तक का सहलेखन किया है, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक है। इस पुस्तक का शीर्षक वास्तव में वन पाथ टु प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। आधुनिक चीन पर लिखा गया अंतिम से पहले का अध्याय किसी दूसरे समृद्धि मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाने में विफल रहा है। हालांकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के स्रोतों की मुख्य कहानी अत्यंत संतोषजनक है। सांस्कृतिक विशेषताओं ने संस्थागत परिवर्तन की शुरुआत की, जिसने बदले में सकारात्मक सांस्कृतिक विशेषताओं को और मजबूत किया। पश्चिमी यूरोप में यह सांस्कृतिक और संस्थागत विकास वैज्ञानिक और शिल्पकारी ज्ञान के संचय को प्रेरित करता है, जिसने 18वीं और 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के तकनीकी परिवर्तन की नींव रखी।

डॉ. मोकिर और उनके सह-लेखक एवनर ग्रेइफ और गुइडो टाबेलिनी का तर्क है कि यूरोप की खंडित राजनीतिक व्यवस्था ने नवाचार को बढ़ावा दिया। नवाचार यथास्थिति को बदल देता है। यह अक्सर उन लोगों को असहज कर देता है जो राजनीतिक शक्ति या प्रभाव रखते हैं। खंडित यूरोप में, कोई भी नवप्रवर्तक जो प्रभावशाली लोगों को इतना नाराज कर देता कि प्रतिशोध का सामना करना पड़े, वह पास के किसी अन्य देश में जा सकता था। चीन में, वे केंद्रीय सरकार की पहुंच से बच नहीं सकते थे। यूरोपीय शहरों में वास्तविक शक्ति और संसाधनों वाले स्थानीय सरकारों के विकास ने सुरक्षित ठिकानों की उपलब्धता को बढ़ाया। शहरों ने इसे गर्व का प्रतीक माना कि वे देश और विदेश से सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर वहां बसने के लिए प्रेरित करें। यूरोप में वैज्ञानिक समाजों का गठन हुआ, जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच को फैलाया। अवलोकन और प्रयोग पर आधारित नए सिद्धांतों ने कट्टरपंथ पर आधारित पुराने सिद्धांतों की जगह ले ली। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति, व्यापार और नगर प्रशासन के व्यापक अभिजात वर्ग तक फैल गया। सोचने के इन नए तरीकों का प्रसार उद्यमियों को उस समय महत्त्वपूर्ण सहारा देता था जब वे स्थापित शक्तियों को चुनौती देते थे। विचारों के आदान-प्रदान और बहस का ऐसा वातावरण स्वीकृत ज्ञान की परतों के संचय को बढ़ावा देता था।

ये अंतर्दृष्टियां केवल दो, पांच और दस शताब्दियों पहले के यूरोप और चीन को समझने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये हमारे लिए भारत में भी मायने रखती हैं, क्योंकि हम 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। हमें वही फलदायी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और संस्थागत परस्पर क्रिया चाहिए, जो तकनीकी परिवर्तन की नींव प्रदान करती हो। इससे उच्च वृद्धि दर प्राप्त होगी। तेजी से विकास के लिए सामाजिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके कठोर और नरम दोनों घटक होते हैं। कठोर घटक हैं जनसंख्या का शिक्षा और कौशल स्तर। उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल शिक्षा प्रणाली शायद दीर्घकालिक प्रगति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है। उत्पादकता और निहित ज्ञान के के कौशल व्यापक कार्यबल में कार्य अनुभव से आते हैं। आज चीन दुनिया के विनिर्माण उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा रखता है, और इसके साथ ही हर उद्योग में गहराई से जमे हुए विनिर्माण कौशल की सबसे व्यापक श्रृंखला को लागू करने की क्षमता भी। यही हमारी प्रतिस्पर्धा है। हमें कंपनियों द्वारा लाखों विनिर्माण नौकरियों में गंभीर निवेश की आवश्यकता है, जो कौशल और कार्य नैतिकता का निर्माण करें। हाल ही में फोन असेंबली में हमारे निवेश, जिसमें अब 2 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, एक शुरुआत है।

सामाजिक पूंजी का एक नरम घटक भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यूरोप में प्रगति का एक विचार विकसित हुआ, और इसके साथ विकास की भूख भी पैदा हुई। अधिक से अधिक व्यक्तियों ने विश्वास करना शुरू किया कि उनके पास अपनी भूमिका निभाने की क्षमता है और प्रत्येक पीढ़ी के साथ जीवन बेहतर होता जाएगा। भारत में यह भूख भरपूर मात्रा में मौजूद है। 1991 से, हममें से अधिक से अधिक लोगों ने यह मानना शुरू किया है कि हमारे पास अपनी जिंदगी सुधारने की क्षमता है। फिर भी हम अभी बहुमत में नहीं हैं; हममें से बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार या कोई महान नेता ही हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। इसलिए हमें अभी काम करना है।

हाल के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों से तीसरा सबक हैः क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन (रचनात्मक विनाश)। डॉ. मोकिर के साथ नोबेल पाने वाले जोड़ीदार, एगियों और हॉविट, को इसी विषय पर उनके काम के लिए उद्धृत किया गया। औद्योगिक क्रांति ने महान प्रगति को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही बड़ी दुर्दशा भी पैदा की क्योंकि कुशल श्रमिक नई तकनीक के कारण बेरोजगार हो गए। एक स्थायी विश्वास था कि कुल रोजगार बढ़ता रहेगा, भले ही व्यक्तिगत पेशे गायब हो जाएं। आंकड़ों ने इस विश्वास को सही साबित किया।

कोई यह सुझाव नहीं देता कि हम उसी रास्ते पर चलें जो जितना शक्तिशाली था उतना ही क्रूर भी। हमें सुरक्षा जाल, समायोजन कार्यक्रम और पुनः प्रशिक्षण योजनाओं की आवश्यकता है क्योंकि नई तकनीक मौजूदा रोजगार को बाधित करती है। लेकिन हमें तकनीकी परिवर्तन के लिए भूख भी चाहिए, जो तेज प्रगति को आगे बढ़ाए, और जो सृजन करते हुए विनाश भी करे। हमारा दिवालिया एवं शोधन अक्षमता अधिनियम 2016 में पारित हुआ, जिसने ऐसे ही पुनर्गठन को तेज करने का वादा किया। लेकिन सिर्फ एक उद्योग यानी एयरलाइंस को देखें तो जेट एयरवेज ने 2019 में उड़ान बंद कर दी और गो फर्स्ट ने 2023 में। दोनों एयरलाइनों के विमान अब भी हमारे हवाई अड्डों पर खड़े हैं। नतीजा यह है कि एक मौजूदा कंपनी के पास 60 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है। जब वह लंबे समय से घोषित नियमों के लिए तैयारी नहीं करती, तो पूरे उद्योग में अराजकता पैदा करने की क्षमता रखती है।

यूरोप की वर्तमान कठिनाइयां काफी हद तक इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि उसने विकास की भूख को खो दिया है। उसने रचनात्मक विनाश के प्रति सहनशीलता भी खो दी है, और पुराने पेशों तथा स्थापित कंपनियों से चिपके रहने का विकल्प चुना है। अमेरिका की वर्तमान शुल्क नीति भी ठीक उसी दिशा में जा रही है।

विकसित भारत की मांग है कि हम इससे बेहतर करें। हम एक समाज के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करें। विनिर्माण और सेवाओं दोनों में उद्यमी क्षमता और रोजगार में निवेश करें, जिससे हमारे व्यापक कार्यबल को कौशल मिले। हम एक समाज के रूप में प्रगति के विचार पर विश्वास रखें, कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, और उस बेहतर भविष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं बल्कि हम पर स्वयं हो। और यह भी कि हम उस रचनात्मक विनाश को अपनाएं जो अक्षम स्थापित कंपनियों को अधिक चुस्त प्रतिस्पर्धियों से बदल देता है।

(लेखक फोर्ब्स मार्शल के सह-अध्यक्ष, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष और सेंटर फॉर टेक्नॉलजी इनोवेशन ऐंड इकनॉमिक रिसर्च के अध्यक्ष हैं)

तटस्थ नीति और निश्चित नियमों से वृद्धि को मिलेगा बढ़ावा

बजट जिस पृष्ठभूमि में तैयार होता है वही आगे का माहौल तय करती है। मगर इस साल हालात भ्रमित करने वाले लग रहे हैं। ऐसे पर्याप्त संकेत हैं जो यह बताते हैं कि आर्थिक वृद्धि कमजोर और मजबूत दोनों है।

कुछ लोगों का तर्क है कि आर्थिक वृद्धि तेजी की ओर बढ़ रही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के आंकड़े मजबूत रहे हैं और कई क्षेत्रों में ऋण आवंटन बढ़ रहा है।

मगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अच्छा दौर खत्म हो गया है। वर्ष 2025 में कई बातें अनुकूल रहीं मसलन अच्छा मॉनसून, तेल की कम कीमतें, मुद्रास्फीति में कमी आदि। ये सभी बातें अनौपचारिक क्षेत्र के लिए फायदेमंद थीं। नीतिगत नरमी जैसे कर दरें कम रहने से खपत को मदद मिली और कम ब्याज दरों से भी खूब मदद मिली। मगर वह दौर शायद पीछे चला गया है। ऐसे लोगों का कहना है कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि बेहद कमजोर रही है और व्यापार घाटा पूरा करने के लिए विदेशी निवेश अपर्याप्त रहा है। पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के आंकड़े भी मजबूत रहने के बाद अब कमजोर होने लगे हैं।

मगर हमारा मानना है कि वास्तविकता कहीं न कहीं इन दोनों दलीलों के बीच है। भारत इस समय एक महत्त्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है। साल 2025 काफी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र की मजबूती की कहानी लिख गया मगर अब अवसर है कि 2026 में औपचारिक क्षेत्र को दुरुस्त किया जाए। ऋण आवंटन में वृद्धि और पूंजीगत व्यय में मजबूती के रूप में कुछ सकारात्मक संकेत देख रहे हैं। ऋण आवंटन बढ़ रहा है मगर यह सिलसिला लगातार बनाए रखना मुख्य चुनौती है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली और धातु जैसे कुछ क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। मगर यह बहुत व्यापक नहीं है। पूर्व में मजबूत निवेश (जिससे घरेलू वृद्धि को बढ़ावा मिला) केवल उन वर्षों में हुआ जब निर्यात मजबूत था। अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए शुल्क में अगर कमी होती है तो वह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में और खपत से निवेश में सफल बदलाव सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माता क्या भूमिका निभा सकते हैं? इसमें दो चीजें मदद कर सकती हैं। पहली, अल्पावधि में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच एक अच्छा संतुलन और दूसरी है मध्यम अवधि में रिटर्न बढ़ाने और जोखिम कम करने वाले महत्त्वपूर्ण सुधार।

प्रांजुल भंडारी

आइए, शुरुआत राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच संतुलन के साथ करते हैं। क्या राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति एक स्थिर संतुलन की ओर बढ़ सकती है जो स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करे? क्या यह नीति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ-साथ निवेशकों और बचतकर्ताओं के हितों के बीच एक अच्छा संतुलन बना सकती है? बेहतर संतुलन अक्सर तटस्थ नीति की अवधारणा से संबंधित होता है मगर व्यवहार में इसका क्या मतलब है?

राजकोषीय मोर्चे पर घाटा और ऋण अनुपात ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक सार्वजनिक ऋण अनुपात को कम कर कोविड पूर्व स्तर तक ले जाना है जिसके लिए अगले पांच वर्षों में निरंतर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी। आगामी बजट में हम सरकार से निरंतर संयम बरतने की उम्मीद करते हैं यानी वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटा सीमित रखने का लक्ष्य और (वित्त वर्ष 2026 के 4.4 फीसदी से जीडीपी का 4.2 फीसदी) घटाना। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च लगातार जारी रखते हुए योजनाओं की संख्या घटाकर इसे थोड़ा समेकित करने की उम्मीद करते हैं।

मगर असल समस्या राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी है। राज्यों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के अभाव में सार्वजनिक ऋण अनुपात अगले कुछ वर्षों तक बढ़ता रहेगा। हालांकि, अच्छी बात यह है कि 3 फीसदी की राजकोषीय सीमा राज्यों का घाटा सीमित रख सकती है। कुल मिलाकर, राजकोषीय नीति 2026 तक तंग रहने की संभावना है।

हम जॉन टेलर द्वारा प्रतिपादित ढांचे में तटस्थ मौद्रिक नीति का अनुसरण करते हैं। पिछले एक दशक में भारत के लिए यह नीति कारगर रही है। हमें लगता है कि अगले साल मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य से ठीक नीचे रहेगी (आंशिक रूप से चीन से आयातित अपस्फीति के कारण) जिससे ब्याज दरें बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है। वास्तव में अगर वृद्धि दर में गिरावट आती है तो और ढील देने की गुंजाइश है।

सख्त राजकोषीय और आसान मौद्रिक नीति का एक संयोजन (जो एक बेहतर आर्थिक संतुलन बनाता है) पूरे वर्ष सभी परिसंपत्ति श्रेणियों के लिए सकारात्मक होना चाहिए खासकर अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कम प्रदर्शन वाले वर्ष के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीद रहा है और हम बजट में राजकोषीय विवेक की उम्मीद करते हैं। जहां तक शेयरों की बात है तो हाल में हुई आर्थिक सुधारों की घोषणाएं, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में क्रमिक वृद्धि और अधिक उचित मूल्यांकन से मदद मिलनी चाहिए। मुद्रा की बात करें तो रुपया पहले ही बहुत गिर चुका है जबकि बेहतर बॉन्ड और शेयर अनुमान पोर्टफोलियो निवेश बढ़ा सकते हैं।

ये सभी उपाय अस्थायी तौर पर तो आर्थिक गतिविधियां प्रोत्साहित कर सकते हैं मगर अर्थव्यवस्था एवं बाजार में निरंतर वृद्धि के लिए सुधार महत्त्वपूर्ण हैं। पिछले वर्ष में कुछ अहम आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं और हमें उम्मीद है कि 2026 में उन्हें और अधिक सक्रियता से आगे बढ़ाया जाएगा। घरेलू मोर्चे पर इनमें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर विनियमन हटाने का अभियान शामिल है। बाहरी मोर्चे पर इनमें सीमा शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं जैसे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को कम करना और न केवल पश्चिमी देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना शामिल है बल्कि पूर्वी देशों (क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत होने के लिए) के साथ व्यापार संबंध गहरे करना भी शामिल है।

मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऊपर जिन सुधारों का जिक्र है वे अगर अच्छी तरह लागू किए जाएं तो फायदे (रिटर्न) बढ़ सकते हैं। मगर हमें जोखिम कम करने की भी उतनी ही जरूरत है। यहां नीतिगत पारदर्शिता, स्थिरता और पूर्वानुमान योग्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना अहम है। नियम-कायदे या उनकी व्याख्या को अचानक बदल देना ठीक नहीं होगा। यह सब इस महत्त्वपूर्ण नीतिगत हालात में अधिक स्वागत योग्य निवेश वातावरण तैयार करने में योगदान कर सकते हैं।

(लेखिका एचएसबीसी में मुख्य भारत अर्थशास्त्री और मैक्रो रणनीतिकार, आसियान अर्थशास्त्री हैं)

आपका पक्ष

वैश्विक बाजार में अमेरिका और चीन एक समान

इस समाचार पत्र में चीन की मुद्रा रणनीति पर प्रकाशित लेख बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा करता है और इस परिदृश्य में भारत के लिए भी सबक सिखाता है। कुल मिलाकर सत्यनिष्ठा से कहें तो अमेरिका और चीन अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। विश्व के सभी देश अमेरिका और चीन से सशंकित हैं। अमेरिका का टैरिफ और चीन का ऋण जाल पूरे विश्व के लिए सिरदर्द है। अमेरिका और चीन भी एक दूसरे की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या चीन और अमेरिका से सबक लिया जा सकता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन की मुद्रा रेनमिनबी आज भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन सकी और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम की जाए और सभी देशों में अधिपत्य बढ़ाया जाए। अब तो

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग

स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका और यूरोपीय देशों पर कब्जा करने, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जबरन अपहरण करने लगा है। चीन भी एक विस्तारवादी देश रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव चीन पर पड़ता है। जब सभी देशों की नीति 'आत्म-निर्भरता' पर केंद्रित हो जाएगी, तब अमेरिका और चीन की आवश्यकता किसको रहेगी। भारत जिस गति से और जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसमें वैमनस्यता और एकाधिकार जैसे नकारात्मक कारक नहीं है और सतत विकास और प्रगति निहित हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

गिरता रुपया, आसमान छूतीं सोने-चांदी की कीमतें

पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सबसे अधिक चांदी की कीमतें बढ़ीं हैं और यह 3.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले साल के आरंभ में इसके दाम एक से डेढ़ लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक थे। वैश्विक उथलपुथल के बीच सोने और चांदी की कीमतों में उछाल अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने से वैश्विक व्यापार का संतुलन बिगड़ने लगा है। अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे देश वैश्विक व्यापार के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। भारत भी वैश्विक बाजार के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहा है। भारत में सोने के दाम बढ़ने के बावजूद आभूषणों की बिक्री 10 फीसदी तक ही बढ़ी है। उधर, रुपये का भाव लगातार गिरता जा रहा है तथा यह 92 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है। रुपये की गिरती कीमत और बेशकीमती धातुओं की बढ़ती कीमतों पर नजर रखने की आवश्यकता है। रुपये में गिरावट का असर वैश्विक व्यापार में लेनदेन पर पड़ता है। अचानक बहुमूल्य धातुओं के दाम बढ़ने से इसकी तस्करी बढ़ने की भी आशंका है। अतः सरकार को इस पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग में सोमवार को बर्फीले तूफान के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। मिसिसिपी विश्वविद्यालय ने ऑक्सफर्ड परिसर के बर्फ से ढक जाने के कारण कक्षाएं पूरे सप्ताह के लिए रद्द कर दीं। अमेरिका में 8,000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और उन्हें रद्द किया गया। साथ ही देश के 7,50,000 से अधिक जगहों पर बिजली गुल रही।

ईयू व्यापार करार से कुशल पेशेवरों की राह होगी आसान

बीएस संवाददाता

अमेरिका एक तरफ अपने देश में कुशल विदेशी प्रतिभाओं की आवाजाही को मुश्किल बना रहा है वहीं इसके विपरीत यूरोप इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के नए मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है।

इस समझौते के तहत भारत में एक यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस स्थापित किया जाएगा, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र से शुरू होकर, श्रमिकों की यूरोपीय संघ (ईयू) में आवाजाही को सुगम बनाने और समर्थन देने के लिए एक अहम केंद्र होगा। इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों के लिए ईयू के सदस्य देशों में जाना और काम करना काफी आसान हो जाएगा। अमेरिका के बाद यह ब्लॉक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी बाजार है।

देश के आईटी सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली उद्योग संस्था नैस्कॉम ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियों को यूरोप में अधिक अवसर मिलने से फायदा मिलेगा जिसमें सेवाओं का सुगम सीमा पार प्रावधान (जीएटीएस के तहत मोड 1) और पेशेवरों के लिए संभावित रूप से आवाजाही की बेहतर संभावनाएं (हालांकि मोड 4) शामिल हैं। भारत का 280 अरब डॉलर का आईटी उद्योग अपनी ज्यादातर कमाई के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन ब्रिटेन और ईयू भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब वीजा नवीनीकरण साक्षात्कार को अगले साल तक के लिए टालने के साथ ही एच-1बी वीजा की प्रक्रिया अब अधिक जटिल होने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहने के कारण, आईटी सेवा कंपनियां अपने कर्मचारियों को यूरोप में भेजने पर अधिक ध्यान दे सकती हैं क्योंकि इस क्षेत्र की कंपनियां पुरानी प्रणालियों के डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में तेजी ला रही हैं।

उद्योग संस्था, नैस्कॉम ने एक बयान में कहा, 'भू-राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, यह एफटीए भारतीय आईटी निर्यातकों के लिए बाजारों में विविधता लाएगा जिससे वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं से बचाव होगा। यह डिजिटल सेवाओं के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।'

समझौते से प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल सेवाओं में ईयू-भारत के बीच सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। नैसकॉम का मानना है कि इससे भारत के आईटी तंत्र में यूरोपीय निवेश, संयुक्त उद्यम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित तकनीक और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) को लेकर सहयोग बढ़ सकता है। भारतीय आईटी कंपनियों को तकनीकी हस्तांतरण, सह-निर्माण और विस्तारित साझेदारी से भी फायदा हो सकता है।

भारत ने पिछले साल ब्रिटेन के साथ भी दोहरे अंशदान करार के माध्यम से इसी तरह का एक समझौता किया था, जो भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को तीन साल तक ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा भुगतान योगदान से छूट देता है जिससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाले वेतन में काफी वृद्धि होती है और भारतीय कंपनियों के लिए लागत कम होती है। इस कदम का मकसद ब्रिटेन को भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक आकर्षक जगह बनाना था।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन

टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने ईयू समझौते पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। एनएलबी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन अलुग ने कहा कि अब यूरोप की कंपनियां भारत में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं तो उनका ध्यान सिर्फ भारत से लोगों को काम पर रखने पर नहीं है। वो अब भारत में मजबूत वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) बनाना चाहती हैं जिनमें बेहतर तरीके से काम हो, नियमों का पालन हो और काम करने का तरीका सख्त हो यानी वो भारत में अपने दफ्तर को और भी बेहतर और भरोसेमंद बनाना चाहती हैं।

अलुग ने कहा, 'इस बदलाव से कंपनियों को नियमों का पालन करने, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) को संरक्षित करने, डेटा को सुरक्षित रखने और नई तकनीक के हिसाब से काम करने के लिए खास लोगों की जरूरत होगी। साथ ही उन्हें भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) अपने दफ्तरों को बेहतर बनाने और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर क्षमता वाले लोगों की जरूरत होगी।'

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) रणनीतिक एआई क्षेत्रों में सहयोग का भी प्रस्ताव करता है, जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुभाषी प्राकृतिक भाषा डेटासेट, एआई प्रशिक्षण डेटा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जलवायु कदमों जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के लिए एआई समाधान शामिल हैं, साथ ही एआई सुरक्षा, परीक्षण और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, भारत और यूरोप मिलकर काम करेंगे। दोनों देश संयुक्त रूप से शोध एवं विकास, पर जोर देने के साथ प्रतिभा और कौशल का पारस्परिक आदान-प्रदान करेंगे और चिप बनाने, उसकी पैकेजिंग तथा रणनीतिक आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग वाला ढांचा तैयार करेंगे।

इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक ने एक बयान में कहा, 'यूरोप से आने वाली महंगी मशीनों और कलपुर्जे पर कर कम होने से भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के कारखानों को कम खर्च में बेहतर चिप बनाने में मदद मिलेगी जिससे वो दुनिया के बाकी कारखानों से अच्छी तरह मुकाबला कर पाएंगे।'

छात्रों के लिए भी, एफटीए अच्छी खबर लेकर आया है। समझौते में यूनियन ऑफ स्किल्स, इरास्मस+ (जिसमें इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम शामिल है), और मैरी स्कोडोव्स्का-क्यूरी एक्शन्स (एमएससीए) जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की एक-दूसरे के देश में आसानी से आवाजाही हो सकेगी। साथ ही भारतीय फंडिंग कार्यक्रम, जैसे कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक ऐंड रिसर्च कोलैबोरेशन (स्पार्क) भी शामिल है।

विदेशी उच्च शिक्षा परामर्श संस्था यूनिवर्सिटी लिविंग के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) मयंक माहेश्वरी ने कहा कि भारतीय छात्रों के लिए बिना किसी सीमा के यूरोप में पढ़ाई करने के अवसर बढ़ने से, अब उनके पास पहले से अधिक विकल्प होंगे। इससे यूरोप भी पढ़ाई के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की तरह ही एक अच्छा विकल्प बन जाएगा।

उन्होंने कहा, 'छात्र अब पढ़ाई से जुड़ी योजना बनाते वक्त काफी सोचते हैं और वे किसी देश के सिर्फ नाम पर ही नहीं जाते बल्कि ये भी देखते हैं कि वहां का अनुभव कैसा होगा, माहौल कितने अच्छे से समझ आएगा और आगे क्या फायदा होगा। इस संदर्भ में देखें तो यूरोप में अच्छी पढ़ाई होती है और फीस भी ज्यादा नहीं होती। साथ ही, वहां कई देशों में पढ़ाई और काम करने के मौके मिलते हैं, जिससे छात्रों को सिर्फ एक शहर या कॉलेज तक सीमित नहीं रहना पड़ता।'

भारत-यूरोपीय संघ में बड़ा करार, बढ़ेगा साझा व्यापार

पृष्ठ 1 का शेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता ऐसे समय में स्थिरता देगा, जब दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता संपन्न होने के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ एक संयुक्त संवादाता सम्मेलन में कहा, 'यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। यह साझा समृद्धि के लिए एक नया खाका है।'

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी यह सशक्त संदेश देगी कि वैश्विक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान सहयोग है। ये टिप्पणियां यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई हैं।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि 'व्यापार समझौते नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं और साझा समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज का मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक महत्त्व रखता है।'

समय के साथ एफटीए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के बाजार में ज्यादा पहुंच प्रदान करेगा। जिस दिन से यह करार लागू होगा उसी दिन से भारत ईयू के संग व्यापार मूल्य के लगभग 30 फीसदी पर शुल्क शून्य कर देगा। 10 साल में चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में दोनों देशों के व्यापार मूल्य का 93 फीसदी आ जाएगा। दूसरी ओर यूरोपीय संघ पहले दिन से ही 90 फीसदी भारतीय निर्यात पर से शुल्क खत्म कर देगा और बाकी पर 7 साल में धीरे-धीरे शुल्क खत्म किए जाएंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है। गोयल ने कहा, 'हमने अलग-अलग आय वर्ग वाले दो देशों के बीच आर्थिक विकास में अंतर को दूर करने की कोशिश की है लेकिन दोनों अर्थव्यवस्था की पूरक ताकतों पर ध्यान दिया गया है ताकि सभी 28 देशों को सामूहिक फायदा हो।'

27 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ को भारत के विशाल बाजार तक व्यापक पहुंच का लाभ मिलेगा। सर्वाधिक तरजीही देश के मामले में भारत में औसत शुल्क 16 फीसदी जबकि शराब और वाहन जैसे उत्पादों पर 100 फसदी से भी ज्यादा शुल्क है

इस समझौते से बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारत-ईयू के रिश्तों में नई धार आने की उम्मीद है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ईयू का औसत शुल्क लगभग 4 फीसदी तक कम होने से समुद्री उत्पाद, कपड़े, रत्न एवं आभूषण, रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक और रबर, फर्नीचर, होम डेकोर, मूल धातुओं जैसे क्षेत्रों के निर्यातकों को फायदा होगा क्योंकि ईयू इनमें से ज्यादातर उत्पाद श्रेणी पर अभी 10 फीसदी से अधिक आयात शुल्क लगाता है।

27 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ को भारत के विशाल बाजार तक व्यापक पहुंच का लाभ मिलेगा। सर्वाधिक तरजीही देश के मामले में भारत में औसत शुल्क 16 फीसदी जबकि शराब और वाहन जैसे उत्पादों पर 100 फसदी से भी ज्यादा शुल्क है। यूरोपीय आयोग ने कहा कि भारत ने ईयू को किसी भी दूसरे व्यापार भागीदार से ज्यादा शुल्क में कटौती का लाभ देने पर सहमति जताई है। वाहन, कृषि और स्टील जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क धीरे-धीरे कम किया जाएगा और इनमें शुल्क कोटा होगा।

वाहन क्षेत्र के मामले में भारत ने कारों पर शुल्क 110 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने के लिए कोटा आधारित व्यवस्था पर सहमति जताई है, जिसमें हर साल 2,50,000 गाड़ियों के आयात का कोटा होगा। पहले साल में शुल्क को घटाकर 30-35 फीसदी किया जाएगा। भारत घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा के लिए सस्ती कार सेगमेंट में यूरोपीय कारों के आयात को सीमित करेगा और 25 लाख रुपये तक की कारें इसके दायरे में आएंगी। प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा कोटा दिया जाएगा, जहां स्थानीय कंपनियों की मौजूदगी कम है। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन कोटा के अलावा शुल्क में कोई कटौती का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर ईयू को दिए गए हर कार कोटा के लिए भारत को अपने निर्यात के लिए 2.5 गुना ज्यादा पहुंच मिलेगा।

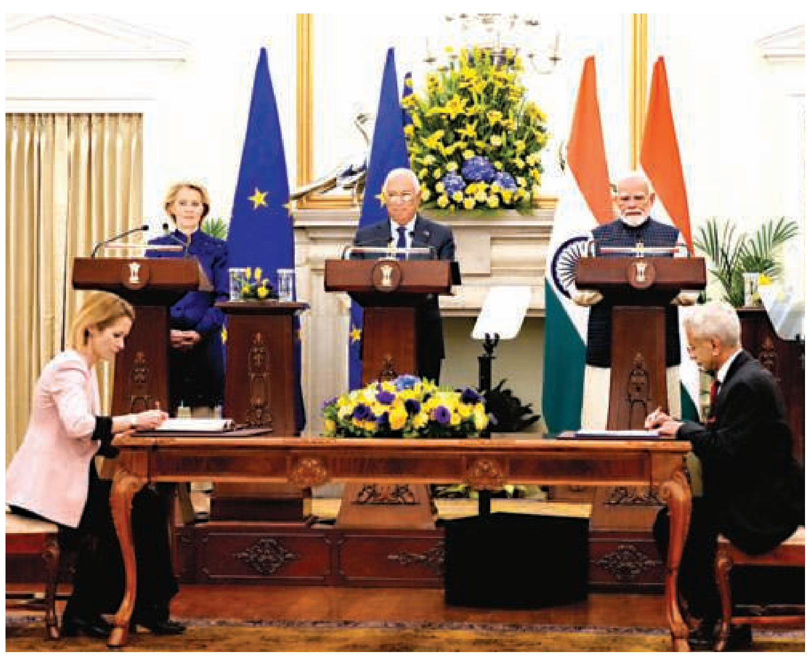

भारत और यूरोपीय संघ के बीच कई करार हुए

ईयू के इलेक्ट्रिक वाहनों को तत्काल बाजार पहुंच नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोटा पांच साल बाद शुरू होगा, जिससे स्थानीय विनिर्माताओं को विस्तार करने के लिए काफी समय मिलेगा।

इस तरह के शुल्क ढांचे के पीछे का कारण समझाते हुए गोयल ने कहा कि ईयू का ध्यान ज्यादातर महंगी गाड़ियों पर रहा है क्योंकि वे 15,000-20,000 यूरो से कम कीमत वाली कारें नहीं बनाते हैं। दूसरी ओर भारत छोटी और किफायती कारें बनाता है।

गोयल ने संवाददाताओं से कहा, 'हम बहुत ही अच्छे समझौते पर पहुंच पाए हैं जहां जर्मनी का वाहन उद्योग असल दिलचस्पी वाले क्षेत्र में ज्यादा बाजार पहुंच पाकर बहुत खुश है जबकि भारतीय उद्योग खुश है कि हम छोटे और कम कीमत वाले वाहन सेगमेंट वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं।'

इसी तरह ईयू के दिलचस्पी वाले विशेष क्षेत्र शराब के मामले में जहां भारत 150 फीसदी आयात शुल्क लगाता है, उसे शुरू में घटाकर 75 फीसदी कर दिया जाएगा और अंत तक शुल्क घटकर प्रीमियम शराब पर 20 फीसदी और मध्यम स्तर की शराब पर 30 फीसदी तक रह जाएगा। स्पिरिट पर शुल्क 40 फीसदी और बीयर पर 50 फीसदी हो जाएगा।

यूरोपीय आयोग के अनुसार इस समझौते से ईयू के कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात पर अक्सर लगने वाला बहुत ज्यादा शुल्क खत्म या कम हो जाएगा जिससे यूरोप के किसानों के लिए बड़ा बाजार खुल जाएगा।

बीफ, चीनी या चावल जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्र में यूरोप शुल्क में कोई राहत नहीं देगा। इसी तरह भारत ने डेरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयामील, कुछ फल और सब्जियों जैसे संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखा है और निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकता के साथ संतुलित किया है।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 1 जनवरी से लागू ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) नियमन बातचीत में सबसे मुश्किल मुद्दों में से एक था क्योंकि यूरोपीय संघ किसी भी देश को खास रियायत देने को तैयार नहीं था। हालांकि दूसरे देश को दी जाने वाली कोई भी सीबीएएम रियायत भारत पर भी लागू होगी।

भारतीय कंपनियों को अपना कार्बन डेटा सत्यापित करने और ईयू के नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक तकनीक समूह बनाया जाएगा। इससे भारत के भविष्य के कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली को पहचान मिल सकती है और दोहरे कराधान से बचा जा सकता है।

सेवा उद्योग में ईयू ने 144 उप-क्षेत्र और भारत ने 102 उप-क्षेत्र खोले हैं। इसके अलावा छात्रों की आवाजाही को लेकर भी प्रतिबद्धताएं की गई हैं। भारत को पढ़ाई के बाद वर्क वीजा पर भी कुछ प्रतिबद्धताएं मिली हैं।

इस समझौते से ईयू कंपनियों को भारत के सेवा बाजार में विशेष पहुंच मिलेगी जिसमें वित्तीय सेवाएं और मैरीटाइम सेवाएं प्रमुख हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी व्यापार करार में वित्तीय सेवाओं पर भारत की यह सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है जो दूसरे व्यापार भागीदारों के साथ की गई प्रतिबद्धता से कहीं ज्यादा है।

समझौते में 21 अध्याय हैं, जिनमें व्यापार में तकनीकी अड़चनें, बौद्धिक संपदा अधिकार, सब्सिडी, धोखाधड़ी रोधी, मूल देश के नियम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गैर-सेवा खंड में निवेश को उदार बनाने वाले अध्याय को फिलहाल हटा दिया गया है लेकिन दोनों ने बातचीत जारी रखने और समझौता लागू होने के दो साल के अंदर इसे अंतिम रूप देने का फैसला किया गया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार पाठ की कानूनी जांच-पड़ताल चल रही है जिसका मकसद अगले पांच से छह महीनों में प्रक्रिया पूरा करके समझौते पर हस्ताक्षर करना है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए व्यावसायिक रूप से अहम करार है, जो शुल्क में भारी कटौती के साथ ही दुनिया के सबसे समृद्ध बाजार में से एक तक पहुंच को मजबूत करता है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (TOGETHER, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH THE CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

MADHUR
TESTED IN QUALITY

MADHUR IRON & STEEL (INDIA) LIMITED

Our Company was incorporated as "Madhur Iron & Steel (India) Private Limited", a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated February 24, 2012, issued by Registrar of Companies, Chhattisgarh. Subsequently, our Company was converted from a private limited company to a public limited company under the provisions of the Companies Act pursuant to a resolution passed by our Board on June 02, 2024, and a special resolution passed by our Shareholders on June 24, 2024. Accordingly, upon conversion, the name of our Company was changed to "Madhur Iron & Steel (India) Limited" by deletion of the word 'Private' from its name and a fresh certificate of incorporation dated July 26, 2024, to that effect was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing Corporate Identity Number U35105CT2012PLC000189. For details of changes in the name and registered office address of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** beginning on page 274 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: 21/A, Light Industrial Area, Bhilai, Durg – 490026, Chhattisgarh, India.
Contact Person: Ketan Kumar Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 – 90309042488; **E-mail:** info@madhurironandsteel.com;
Website: https://madhurironandsteel.com/; **Corporate Identity Number:** U35105CT2012PLC000189

OUR PROMOTER: JAYANT AGRAWAL

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 1,00,00,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF MADHUR IRON & STEEL (INDIA) LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•]/- LAKHS (THE "ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHATTISGARH WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND (TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**** Subject to finalisation of basis of allotment***

In case of any revision to the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of one Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the websites of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to SelfCertified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**" and such portion, the "**QIB Portion**"), provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis, in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which 40% shall be reserved in the following manner (i) 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, Life Insurance Companies and Pension Funds, as applicable, at or above the Anchor Investor Allocation Price. Any under-subscription in the Life Insurance Companies and Pension Funds category specified in (ii) above may be allocated to domestic Mutual Funds, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to QIB bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. One-third of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹2.00 lakhs and up to ₹10.00 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹10.00 lakhs provided that under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Portion may be allocated to Non-Institutional Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 485 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the Regulation 26(2) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirement, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity shares pursuant to the issue and has filed the DRHP dated January 23, 2026. With Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Stock Exchanges on January 24, 2026.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with the SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com , NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be Listed and the Company at https://madhurironandsteel.com/ and at the website of BRLM i.e. Share India Capital Services Private Limited at www.shareindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public is requested to send a copy of their comments to SEBI, Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have neither been recommended, nor approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the Investors is invited to ***"Risk Factors"*** beginning on page 32 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus ('**RHP**') has been filed with ROC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Main Board of BSE and NSE.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
Share India	
SHARE INDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED **Address:** A-25, Basement Sector-64, Gautam Buddha Nagar, Noida – 201301, Uttar Pradesh, India **Tel No.:** +91-120-6483000 **Email:** vinay.pareek@shareindia.co.in / kunal.bansal@shareindia.co.in **Investor Grievances Email Id:** mb@shareindia.com **Contact Person:** Mr. Vinay Pareek / Mr. Kunal Bansal **Website:** www.shareindia.com; **SEBI Registration No.:** INM000012537 **CIN:** U65923UP2016PTC075987	**Bigshare Services Private Limited** **Address:** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India **Telephone:** 022 - 6263 8200 **E-mail:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Babu Rapheal **SEBI Registration Number:** INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **Madhur Iron & Steel (India) Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Jayant Agrawal
Managing Director

Place : Bhilai
Date : January 27, 2026

Disclaimer: Madhur Iron & Steel (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated January 23, 2026 with SEBI and Stock Exchanges on January 24, 2026. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com , NSE at www.nseindia.com , on the website of the Company at https://madhurironandsteel.com/ and at the website of BRLM i.e. Share India Capital Services Private Limited at www.shareindia.com. Potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating such risk, see the section titled ***"Risk Factors"*** in the Red Herring Prospectus, when filed. Potential Investor should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "**U. S. Securities Act**") or any state securities law in United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the U. S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance of Regulations and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made.

KIRIN ADVISORS

न्यूज विंडो

जिलाधिकारी ने मंडल कारा का किया निरीक्षण

छपरा @ पत्रिका. बिहार में सारण जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा छपरा में मंगलवार सुबह जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने छापामारी कर सभी वार्डों की सघन तलाशी ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान किसी भी वार्ड से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। निरीक्षण के दौरान सभी वार्डों की साफ-सफाई, कैदियों की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था का भी अधिकारी दव्य ने निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मंडल कारा प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

लूटकांड मामला: गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित

जमुई @ पत्रिका. जमुई जिलान्तर्गत गिद्धौर थाना क्षेत्र में डॉ विजयेंद्र सत्यार्थी के घर हुई लूटकांड की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष एसआइ दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई जमुई के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र के आदेश से की गई है। 26 जनवरी को गिद्धौर थाना गेट के सामने स्थित डॉ विजयेंद्र सत्यार्थी के आवास में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका को अपराध नियंत्रण में निष्क्रिय और लापरवाह पाया गया, जिसके बाद उनके निलंबन की अनुशंसा की गई।

कर्तव्य में लापरवाही पर दो अधिकारी निलंबित

पटना @ पत्रिका. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के दो अधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। संचिका समय पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में प्रशाखा पदाधिकारी उमेश्वर कुमार सिंह और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। करीब एक सप्ताह पहले विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक की योगदान संचिका समय पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। पूछताछ में दोनों अधिकारियों की लापरवाही सामने आई।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपहृत कारोबारी पुत्र सकुशल बरामद

रांची @ पत्रिका. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से अपहृत कारोबारी पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हजारीबाग जिले के बरही इलाके में की गई। बरामदगी के बाद कैरव को सुरक्षित परिजनों के पास पहुंचा दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसे हजारीबाग के चौपारण क्षेत्र से बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू की। पुलिस की घेराबंदी देख अपराधी कैरव को कार में छोड़कर फरार हो गए।

कस्टम हायरिंग सेंटर से खेती होगी समयबद्ध, उत्पादन बढ़ेगा : यादव

पटना @ पत्रिका. बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे किसान जुताई, बुआई/रोपनी, कटाई और मड़ाई जैसी प्रमुख कृषि गतिविधियों के लिए आधुनिक मशीनें किराये पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी, समय पर कृषि कार्य पूरे होंगे और पैदावार व गुणवत्ता में सुधार होगा।

ट्रेलर की चपेट में आए तीन टेम्पो समेत कई बाइक, एक की मौत

बोकारो @ पत्रिका. झारखंड में बोकारो जिले के पिंड्रा जोड़ा थाना क्षेत्र के काशी झरिया काजूबगान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में अनियंत्रित ट्रेलर ने तीन टेम्पो, कई बाइक व साइकिल सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में पश्चिम बंगाल निवासी सुरेश महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बोकारो सदर अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, चास से पुरुलिया की ओर जा रहे ट्रेलर शराब के नशे में धुत चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया जिसके कारण यह हादसा हुआ।

समृद्धि यात्रा : मधुबनी जिले को दी 391 करोड़ की योजनाओं की सौगात

राज्य में सरकार क्षेत्रीय विकास को दे रही प्राथमिकता : नीतीश

सीएम ने 101 योजनाओं का किया शिलान्यास

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मधुबनी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिले को 391 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रिमोट के माध्यम से 395 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 294 योजनाओं का उद्घाटन 93 करोड़ रुपए की लागत से तथा 101 योजनाओं का शिलान्यास 298 करोड़ की लागत से किया गया।

नीतीश कुमार की यह यात्रा केवल विकास कार्यों का निरीक्षण भर नहीं थी, बल्कि इसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। मिथिला हाट फेज- II, रिंग रोड, औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन स्थल फुलहर स्थान जैसी परियोजनाओं का जायजा लेकर उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी सरकार क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की घोषणाओं और निरीक्षणों के जरिए मुख्यमंत्री जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नवनिर्मित जीविका भवन का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित जीविका भवन का लोकार्पण किया और इसकी चाबी जीविका दीदियों को सौंपी। उन्होंने 26,312 स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 301 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया। साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 507 लाभार्थियों को दो करोड़ 53 लाख की राशि दी। यह कदम ग्रामीण महिलाओं और गरीब तबके को सीधे साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान लाभार्थियों को छात्र आइडी कार्ड वितरित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

सांप्रदायिकता के खिलाफ नीतीश का सख्त रुख : जदयू

पटना @ पत्रिका. जदयू ने कहा है कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के विरुद्ध 'जीरो टोलरेंस' ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम और परिमल कुमार ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही इस नीति पर दृढ़ता से काम करते रहे हैं। यह केवल घोषणा नहीं बल्कि शासन-प्रशासन के हर स्तर पर लागू एक सख्त और पारदर्शी व्यवस्था है, जिसने बिहार की प्रशासनिक संरचना में सकारात्मक बदलाव किए हैं। प्रवक्ताओं ने कहा कि जनता का समर्थन और विश्वास इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कानून का राज और सुशासन स्थापित हुआ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली सफलता भी इसी जन-आस्था की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ईमानदार छवि और सशक्त नेतृत्व पर जनता का भरोसा कायम है और भविष्य में भी नीतीश कुमार बिना किसी समझौते के अपनी नीतियों पर चलते रहेंगे। जदयू का दावा है कि जनता के सहयोग से बिहार विकास, सुशासन और सामाजिक सौहार्द की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

छठ घाट निर्माण का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश

छठ घाट निर्माण का निरीक्षण नीतीश ने तालाबों के सौंदर्यीकरण और छठ घाट निर्माण का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समय पर पूरे हों। उन्होंने कहा कि चारों ओर सीढ़ीनुमा घाट बनने से छठ पूजा जैसे अवसरों पर लोगों को सुविधा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, छात्र क्रेडिट कार्ड, नारी शक्ति योजना और प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को चेक और वाहन की चाबी भी प्रदान की। इन घोषणाओं को सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राजनीति के रूप में देखा जा रहा है।

23 फरवरी को मतदान, 27 फरवरी को मतगणना, आचार संहिता लागू

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रांची. झारखंड में पिछले कई वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से गति मिलने जा रही है। आयोग के अनुसार राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक ही चरण में 23 फरवरी (सोमवार) को मतदान कराया जाएगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना की जाएगी।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 23 फरवरी को मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह नगर निकाय चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। इन चुनावों के दायरे में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 से ही नगर निकाय चुनाव लंबित थे। निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की विस्तृत व्यवस्था की गई है। नगर निगमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और अनारक्षित श्रेणियों के अनुसार आरक्षण लागू किया गया।

हाईकोर्ट के दखल से चुनाव का रास्ता हुआ साफ

पहले कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, बाद में ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर लगातार कानूनी और प्रशासनिक उलझनें बनी रहीं। इन वर्षों के दौरान कई बार चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आरक्षण से जुड़े मामलों में स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण चुनाव टलते रहे। आखिरकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पूरा किया और आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया। हाल ही में हाईकोर्ट ने नगर निगमों के वर्गीकरण और मेयर पद के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया, जिससे चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया।

पूर्णिया में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

पूर्णिया @ पत्रिका. बिहार में पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार को आपसी विवाद में एक गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि वसंत विहार में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी विवाद को सुलझाने के लिए वहां गए हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने गोलियां चलाईं। गोली लगने से सूरज बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरज बिहारी को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरंगा थाना प्रभारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। स्पेशल टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

भाजपा जाति और परिवार के नाम से नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ रही : संजय सरावगी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा जाति और परिवारवाद की राजनीति से अलग है और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर आगे बढ़ती है। उन्होंने मंगलवार को गया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में बूथ स्तर पर काम करने वाला सामान्य कार्यकर्ता भी संगठन के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।

सरावगी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भी भाजपा अपनी विचारधारा पर कायम रहती है। उन्होंने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कई राजनीतिक दल परिवारवाद पर चलते हैं, जबकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और अनुशासन से मजबूत होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे उत्साह और अनुशासन के साथ पार्टी को मजबूत बनाने में सहयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा।

सुख और समृद्धि की कामना की: सरावगी ने कहा कि सभी का सामूहिक कर्तव्य है कि पार्टी को मजबूत बनाकर उपलब्धियों का नया कीर्तिमान स्थापित करें।कार्यक्रम के बाद सरावगी मंगला गौरी और विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूजा-अर्चना कर बिहारवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की।

पानी में डूबने से दो सहेलियों की मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

छपरा. बिहार में सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को पानी में डूब जाने से दो सहेलियों की मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भदरिया गांव निवासी धर्मनाथ महतो की पुत्री प्रियंका कुमारी (19) एवं विश्वनाथ महतो की पुत्री सिंकी कुमारी (18) अपने खेत में पटवन के बाद हाथ-पैर धोने के लिए पास के चंवर में पहुंची थी। वहां जेसीबी मशीन से खोदे गए गड्ढे में प्रियंका कुमारी का पैस फिसल गया, जिसे बचाने पहुंची उसकी सहेली सिंकी कुमारी भी गड्ढे में गिर गई। जिसके बाद पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को गड्ढे से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

छपरा @ पत्रिका. बिहार में सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।पुलिस सूत्रों ने बताया कि हाईस्कूल चौंक निवासी किशुन चौधरी (40) भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में बाइक मैकेनिक का काम खत्म कर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सेंगर टोला गांव के समीप मुख्य पथ पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में वह घायल हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

बोले सिन्हा | **परिसीमन के बाद भी कार्यकाल पूरा होने तक चुनाव नहीं कराया जाएगा**

निर्वाचित पार्षदों का अधिकार सुरक्षित रहेगा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जिन नगर निकायों का परिसीमन हो चुका है और जहाँ समिति का कार्यकाल शेष है, वहां नया चुनाव नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय होगा।

मंगलवार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल उपमुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में हाल ही में शामिल किए गए गांवों के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और कहा कि अभी निर्वाचित सदस्यों का डेढ़ वर्ष का कार्यकाल बचा है।

सिन्हा ने आश्वासन दिया कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने पिछले वर्ष जिला पदाधिकारियों से नए नगर निकायों के गठन और पुराने निकायों के क्षेत्र विस्तार के प्रस्ताव मांगे थे। इसके आलोक में आठ नगर निकायों के प्रस्ताव अधिसूचित कर निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं। वर्तमान में 29 नगर निकायों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन जनगणना आयोग के निर्देशानुसार इन पर 31 मार्च 2027 तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने की पुष्टि होती है, तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पदाधिकारियों या कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने भू-लगान भुगतान और रसीद निर्गत करने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। इसके बावजूद कुछ जिलों से ऑफलाइन रसीद जारी करने की शिकायतें मिली हैं। विभाग ने इसे गंभीर नियम उल्लंघन और संभावित आपराधिक षड्यंत्र करार दिया है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ऑफलाइन रसीदों की स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराएं और यह भी स्पष्ट करें कि अव्यवहृत रसीदें किस अधिकारी की अभिरक्षा में हैं। साथ ही दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है।

200 लोगों की समस्याएं सुनीं, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान : मुख्यमंत्री योगी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गोरखपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और प्रार्थना पत्र पढ़ते हुए भरोसा दिलाया कि "घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा।"

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण किया जाए। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई करने को कहा।

बच्चों को दिया स्नेह और प्रेरणा: परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलार किया और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बच्चों को मिष्ठान्न भी वितरित किए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा पर शीश नवाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए।

इलाज में धन की कमी नहीं बनेगी बाधा

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल से इस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शासन में भेजने का निर्देश दिया। विवेकाधीन कोष से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

हड़ताल पर जाएंगे बिजली इंजीनियर

लखनऊ @ पत्रिका. बिजली क्षेत्र के निजीकरण और विद्युत संशोधन विधेयक-2025 के विरोध में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का नोटिस केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को सौंपा है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सार्वजनिक बिजली क्षेत्र को कमजोर करने वाली नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मियों में गहरा असंतोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि देशभर में तात्कालिक 'लाइटनिंग एक्शन' शुरू किया जाएगा।

माघ मेला पवित्र स्थल, राजनीति का अखाड़ा नहीं : रामानुजाचार्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

प्रयागराज. माघ मेले को लेकर पिछले दस दिनों से जारी विवाद पर श्रृंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शांडिल्य महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि माघ मेला क्षेत्र एक पवित्र तीर्थ स्थल है, न कि राजनीति का अखाड़ा।

मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ प्रशासन द्वारा कथित दुर्व्यवहार के बाद साधु-संत दो गुटों में बंट गए हैं।

स्वामी शांडिल्य महाराज ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बटुकों के साथ मारपीट निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों की उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि मुख्यमंत्री लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में अनूठी तपस्या की जा रही

माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधुओं ने की धूनी साधना

मंगलवार को प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान साधुओं ने धूनी पूजा की।

प्रयागराज @ पत्रिका. माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनशन के समर्थन में मंगलवार को साधु-संतों ने अनूठी साधना शुरू की। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में बड़ी संख्या में संतों ने शिविर के सामने धूनी साधना आरंभ की। वैष्णव परंपरा में वसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक संत अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करते हैं, जिसे धूनी तापना कहा जाता है। इसी साधना के माध्यम से संतों ने शंकराचार्य का समर्थन जताया। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी सहित जा रहे शंकराचार्य को प्रशासन ने रोक दिया था। शिष्यों के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। स्वामी बिना स्नान किए शिविर लौट आए और 18 जनवरी से वहीं धरने पर बैठे हैं।

कानपुर-उन्नाव को जोड़ने वाले फोर लेन पुल का भूमि पूजन

कानपुर @ पत्रिका. कानपुर नगर से शुक्लागंज (उन्नाव) को जोड़ने वाले प्रस्तावित फोर लेन पुल का भूमि पूजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने 235 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। बताया गया कि पुल लगभग 30 माह में तैयार होगा और इसके निर्माण से प्रतिदिन करीब चार लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।पुल से कानपुर, शुक्लागंज और उन्नाव के बीच आवागमन और अधिक सरल, सुगम एवं सुरक्षित होगा। यह परियोजना न केवल यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि आसपास के गांवों के विकास को भी गति देगी। व्यापार, उद्योग और स्थानीय बाजारों को बढ़ावा मिलेगा।

मथुरा में यूजीसी बिल के विरोध में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन

लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मंगलवार को लखनऊ में यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉलेजों में यूजीसी के नए जाति-आधारित समानता नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

मथुरा . केंद्र सरकार के यूजीसी बिल के विरोध में मंगलवार को विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। परशुराम शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा ने कहा कि यूजीसी बिल सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और यह कानून हिंदू समाज तथा उच्च जाति के भविष्य को प्रभावित करेगा।

बैंकिंग सुविधाओं से बढ़ रहा स्वरोजगार, महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर : आनंदीबेन

लखनऊ@ पत्रिका. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचने से स्वरोज़गार और उद्यमिता को नई गति मिली है। महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर व्यवसाय प्रारंभ कर रही हैं और आधुनिक तकनीकों के सहारे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

राज्यपाल मंगलवार को गोमती नगर स्थित विराज खंड में एचडीएफसी बैंक के मेगा करेंसी चेस्ट एंड डब्ल्यूबीओ परिसर के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस
(सिविल राईट्स एवं ए.एच.टी.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एएचटी / एमपीसी / समाचार प्रकाशन / 2025 / 2820 दिनांक – 23.12.2025

गुमशुदा की तलाश

फोटो गुमशुदा

नाम	: सदाराम
पिताजी	: श्री सन्तोष केवट
उम्र	: 39 साल
निवासी	: अलहदादपुर
थाना	: दोस्तपुर
जिला	: सुल्तानपुर उतरप्रदेश हाल काडी मैदा सुभाष कॉलोनी निवाई जिला टोंक।
मुकदमा नं.	: एमपीआर संख्या 20 / 2020
जिला	: टोंक
लिंग	: पुरूष
गुम होने की दिनांक	: दिनांक 14.12.2018 साथी के किराया का कमरा निवाई से बिना बताये कहीं चला गया है।

हुलिया गुमशुदा – रंग गेहुँआ, कद–5 फिट, ललाट पर तिल का निशान, टी–शर्ट पजामा पहने हुए है। आप अपने–अपने क्षेत्र में गुमशुदा की तलाश करवायें तथा मिलने पर निम्न को सूचना देने का श्रम करें।

राजस्थान संवाद

थानाधिकारी निवाई	वृत्ताधिकारी वृत्त निवाई जिला टोंक	प्रभारी ए.एच.टी.यू जिला टोंक	प्रलिस नियंत्रण कक्ष जिला टोंक	पुलिस अधीक्षक जिला टोंक
01438–222002	01438–223811	01438–243836	01438–244400	01432–243028

पत्रिका फाइनेंस
@बिजनेस & वेल्थ

यह समझौता 25% वैश्विक व्यापार वाले दो पक्षों की मजबूत साझेदारी का संकेत है। इससे रक्षा सहयोग बढ़ेगा, निवेश आएगा। इनोवेशन में सहयोग बढ़ेगा। इससे एक-तिहाई दुनिया की आबादी के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य बनेगा।
पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, भारत

भारत-ईयू फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट 3.8% औसत टैरिफ से घटकर 0.1% रह जाएगा भारतीय उत्पादों पर, देश में मंहगी यूरोपियन कारें होंगी सस्ती, शराब-प्रोसेस्ड फूड के दाम भी घटेंगे

किसानों-एमएसएमई को ₹6.40 लाख करोड़ का फायदा!

नई दिल्ली @ पत्रिका. दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने आखिरकार इतिहास रच दिया। मंगलवार को दोनों पक्षों ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की। इस समझौते के साथ भारत और ईयू के बीच व्यापार के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुल जाएंगे। ईयू का औसत टैरिफ पहले से ही 3.8% के आसपास है, जो समझौते के बाद भारत के लिए घटकर 0.1% रह जाएगा। अभी ईयू में समुद्री उत्पाद, रसायन, प्लास्टिक-रबर उत्पादों पर ज्यादा शुल्क हैं, जिन्हें ईयू भारत के लिए पूरी तरह हटाएगा। इससे देश के किसानों, एमएसएमई औक निर्यातकों को सालावा 6.40 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। लग्जरी कार-शराब सहित कई यूरोपीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।

प्रोफेशनल्स: भारतीय टैलेंट्स के लिए यूरोप में काम करना आसान

इस समझौते में एक नया मोबिलिटी फ्रेमवर्क शामिल किया गया है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना आसान हो जाएगा। इसके तहत 37 क्षेत्रों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को ईयू में काम करने की सुविधा मिलेगी। इनमें आइटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शिक्षा और प्रोफेशनल सेवाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा 17 हाई-स्किल क्षेत्रों में स्वतंत्र पेशेवरों को भी खास पहुंच दी जाएगी। इस डील के लागू होने के बाद पहली बार कंपनी के भीतर ट्रांसफर होने वाले कर्मचारी अपने परिवार के साथ यूरोप जा सकेंगे। इससे भारतीय पेशेवरों को लंबे समय तक ईयू में काम करने के बेहतर मौके मिलेंगे। समझौते में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम भी शामिल किए गए हैं। अगले पांच साल में समझौते हो सकते हैं, जो डबल टैक्सेशन की समस्या को कम करेंगे।ह्य

छात्रों को पढ़ाई के बाद मिलेगी नौकरी

ईयू के संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने वाले भारतीय छात्रों को अब डिग्री खत्म होने के बाद 9 से 12 महीने तक नौकरी खोजने का समय मिलेगा। इससे भारतीय युवाओं को यूरोप में काम का अनुभव हासिल करने और वहां के सेवा व हेल्थकेयर सेक्टर में करियर बनाने में मदद मिलेगी।

समझौते पर मुहर: आर्थिक सहयोग में मील का पत्थर

नई दिल्ली. भारत-ईयू के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर के बाद मंगलवार को दस्तावेजों का अदान-प्रदान करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ईयू प्रतिनिधि

डील: वैश्विक सप्लाई चेन में भारत मजबूत होगा
देश के इन 12 राज्यों को सबसे अधिक होगा लाभ

इस व्यापार समझौते से देश के 12 राज्यों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसका लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों, एमएसएमई इकाइयों और युवाओं तक पहुंचेगा। इस ट्रेड डील से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत मजबूत होगा।

- **राजस्थान:** जयपुर से जेम्स-ज्वैलरी का निर्यात बढ़ेगा। जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प को मजबूत बाजार मिलेगा। ***चूरू के स्पोर्ट्स गुड्स और बंधेज कपड़ों की मांग बढ़ेगी।***
- **गुजरात:** केमिकल्स पर टैरिफ खत्म होने से भरूच-वडोदरा के केमिकल्स निर्यात को लाभ होगा। ***सूरत के कपड़े-हीरे, राजकोट की इंजीनियरिंग और वेरावल से समुद्री उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी।***
- **महाराष्ट्र:** टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ शून्य हो जाने से इचलकरंजी की गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। साथ ही ***पुणे की इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रॉनिक्स, मुंबई के रत्न-आभूषण और थाणे-रायगढ़ से फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी होगी।***
- **तमिलनाडु:** चमड़ा पर टैरिफ शून्य होने से वेल्लोर-अंबूर के चमड़ा-जूते को लाभ मिलेगा। ***तिरुपुर के परिधान और चेन्नई-कोयंबटूर के इंजीनियरिंग निर्यात भी बढ़ेंगे।***
- **पश्चिम बंगाल:** दार्जिलिंग की चाय, दीघा-हल्दिया के समुद्री खाद्य पदार्थ के साथ हस्तशिल्प पर ***टैरिफ कम होने से पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा।***
- **असम:** डिब्रूगढ़-जोरहाट की चाय का निर्यात बढ़ेगा। असम के मसालों को बेहतर बाजार मिलेगा। ***बारपेटा-नलबाड़ी के बांस से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प की मांग भी बढ़ेगी।***
- **केरल:** कोच्चि-अलाप्पुझा से झींगा और टूना मछली का निर्यात बढ़ेगा। ***इडुक्की-वायनाड की काली मिर्च और इलायची के निर्यात में अच्छा इजाफा होगा।***
- **तेलंगाना:** हैदराबाद-वारंगल के कपड़े और परिधान उद्योग को फायदा होगा। ***फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस के निर्यात में भी मजबूती आएगी।***
- **कर्नाटक:** बेंगलुरु-तुमकुरु की इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा कंपनियों में तेजी से विकास हो सकता है।
- **पंजाब:** लुधियाना के गारमेंट और निटवेयर का निर्यात बढ़ेगा। जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स की यूरोप में मांग बढ़ेगी। ***मंडी गोबिंदगढ़ की इंजीनियरिंग यूनिट्स को भी फायदा होगा।***
- **आंध्र प्रदेश:** विशाखापट्टनम-काकीनाडा से झींगा और समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात काफी बढ़ेगा। ***फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का भी निर्यात मजबूत होगा।***
- **उत्तर प्रदेश:** कानपुर-आगरा के चमड़े और जूतों का निर्यात काफी तेज होगा। ***सहारनपुर के फर्नीचर और हस्तशिल्प को नए बाजार मिलेंगे। नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी।***

टेक्सटाइल: सालाना 20-25% बढ़ सकता है देश का निर्यात

इस ट्रेड डील के तहत टेक्सटाइल पर ईयू में लगने वाला औसतन 12% टैरिफ लगभग 0% हो जाएगा। इससे यूरोप में भारतीय वस्त्रों की कीमत घटेगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। यूरोपीय संघ का 22.9 लाख करोड़ रुपए (263.5 अरब डॉलर) का टेक्सटाइल बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खुल जाएगा। उद्योग अनुमान के मुताबिक एफटीए लागू होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल निर्यात में सालाना 20-25% की ग्रोथ हो सकती है। एक जनवरी 2026 से ईयू ने भारत के 87% निर्यात पर जीएसपी (जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस) लाभ निलंबित कर दिए थे, एफटीए लागू होने से बड़ी राहत मिलेगी।

कैसे होगा फायदा?

भारत के टेक्सटाइल उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम से मुकाबला करने में बड़ा फायदा होगा। अभी भारतीय कपड़ों पर ईयू में 8-12% टैरिफ लगता है जबकि बांग्लादेश को जीएसपी के तहत और वियतनाम को ड्यूटी-फ्री टैरिफ वाला लाभ मिलता है। इससे ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम की तरफ जाते रहे हैं। एफटीए से भारतीय टेक्सटाइल की कीमतें बराबर या बेहतर हो जाएंगी। तिरुपुर (तमिलनाडु) का निटवियर हब बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है व यूरोप में सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है।

सर्विस सेक्टर को बड़ा फायदा

भारत-ईयू एफटीए से सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 55% है। इस समझौते के बाद भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के 144 सेवा क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। इनमें आइटी, शिक्षा, बैंकिंग-वित्त, पर्यटन और हेल्थकेयर जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं। वहीं ईयू की कंपनियों को भारत के 102 सेवा क्षेत्रों में प्रवेश मिलेगा। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा और नई तकनीक आएगी।

इन भारतीय उत्पादों का बढ़ेगा निर्यात

सेक्टर	वर्तमान टैरिफ	एटीएफ के बाद	ईयू को निर्यात
टेक्सटाइल-कपड़े	12%	शून्य फीसदी %	7.20
लेदर-फुटवियर	17%		2.40
इलेक्ट्रॉनिक्स	14%		11.3
जेम्स-ज्वैलरी	04%		2.70
केमिकल्स	12.8%		5.1
फार्मा-डिवाइस	6.7%		5.8
सी-फूड	26%		1.01
प्लास्टिक-रबर	6.5%		2.40
इंजीनियरिंग गुड्स	5-22%	5-0%	16.6
होम डेकोर-फर्नीचर	15-25%	10.5%	1.18

(ईयू को **निर्यात अरब डॉलर में,** वर्ष 2024-25 के आंकड़े)

भारत में ये इंडस्ट्रियल उत्पाद होंगे सस्ते

उत्पाद	एटीएफ के बाद	वर्तमान औसत टैरिफ
मशीनरी/इलेक्ट्रिकल	शून्य फीसदी %	44%
विमान/अंतरिक्ष यान		11.0%
मेडिकल उपकरण*		27.5%
प्लास्टिक		16.5%
कीमती पत्थर/धातुएं**		22.5%
केमिकल्स		22.0%
लोहा-स्टील उत्पाद		22.0%
दवाइयां		11.0%

*90% उत्पादों पर, **20% उत्पादों पर, बाकी पर कम होंगे टैक्स

50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद 2031 तक भारत से ईयू को मोबाइल-आइटी हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात

खाने-पीने के उत्पादों की घटेंगी कीमतें

उत्पाद	वर्तमान टैरिफ	एफटीए के बाद
वाइन	150%	20-30%
स्पिरिट्स (शराब)	150%	40%
बीयर	110%	50%
ऑलिव ऑयल	45%	00%
कीवी-नाशपाती	33%	10%
फलों के जूस	55%	00%
प्रोसेस्ड फूड	50%	00%
सॉसेज/मांस उत्पाद	110%	50%

236.5 अरब डॉलर के ईयू टेक्सटाइल मार्केट में भारतीय कपड़े बांग्लादेश-वियतनाम जैसे देशों से पहले से कहीं बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे

100 अरब डॉलर का बाजार यूरोप लेदर-फुटवियर का, भारत के कुल लेदर-फुटवियर निर्यात में ईयू की 44.64% हिस्सेदारी

एक साल में भारत ने किए 5 ट्रेड डील

जुलाई 2025	ब्रिटेन से एफटीए
अक्टूबर 2025	ईएफटीए से ट्रेड डील
18 दिसंबर 2025	ओमान से सीईपीए
दिसंबर 2025	न्यूजीलैंड से एफटीए
जनवरी 2026	ईयू से एफटीए

97.5% केमिकल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ***औसतन 12.8% से घटकर जीरो हो जाएगा***

90% भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स जैसे मशीनरी, ***ऑटो कंपोनेंट्स, टूल्स पर टैरिफ घटकर शून्य का बहुत कम रह जाएगा,*** ईयू इसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाजार

एमएसएमइ: श्रम प्रधान उद्योगों को मिलेगी राहत

इस व्यापार समझौते से एमएसएमई और श्रम आधारित उद्योगों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर लेदर, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र (टेक्सटाइल) और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। लेदर उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क 17% से घटकर 0% हो जाएगा। वहीं, रत्न और आभूषणों पर शुल्क 4% से घटकर 0% कर दिया जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों की ईयू बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता काफी बेहतर होगी। इसके अलावा, इस मजदूरों, कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। ***चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जी के निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी।***

समझौते में एमएसएमई के लिए सहयोगी ढांचे भी शामिल किए गए हैं। इयू इसके लिए आर्थिक मदद देगा, ताकि वे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अपना सकें और ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से जुड़ी शर्तों के अनुसार खुद को ढाल सकें। इससे छोटे उद्योगों को नए पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप काम करने में मदद मिलेगी।

कृषि: किसानों के हित सुरक्षित

इस समझौते से भारत के कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात को भी बड़ा फायदा मिलेगा। चाय, कॉफी, मसाले, फल और सब्जियां जैसे कई उत्पादों को ईयू बाजार में बिना किसी आयात शुल्क (जीरो ड्यूटी) के पहुंच मिलेगी। वहीं, भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी, पोल्ट्री और अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, ताकि घरेलू किसानों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जैसे अंगूर, खीरा (घेरकिन), सूखा प्याज, स्वीट कॉर्न और घी के निर्यात को भी इस समझौते से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है।

हेल्थकेयर: फार्मा-मेडिकल डिवाइसेज बड़े विजेता

इस एफटीए से हेल्थकेयर और मेडिकल डिवाइसेज क्षेत्र बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। भारतीय हेल्थकेयर सेवा प्रदाताओं और मेडिकल प्रोफेशनल्स को ईयू के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। वहीं, ईयू के 572 अरब डॉलर के हेल्थकेयर बाजार में भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को टैरिफ में उदारीकरण का सीधा फायदा मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियां यूरोप में चीन, अमरीका और जापन को टक्कर देंगी।

राहत ईयू की ज्वैलरी पर रहेगा 22% टैक्स

भारतीय ज्वैलर्स को हांगकांग, चीन-थाईलैंड पर बढ़त मिलेगी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत-ईयू एफटी में जेम्स एंड ज्वैलरी पर टैरिफ 4% तक से घटकर शून्य होने के बाद यूरोप में भारतीय तैयार आभूषण चाहे वे स्टडेड हों, सादे हों या इमिटेशन ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। टैरिफ घटने से भारतीय निर्यातकों की लागत घटेगी और उन्हें यूरोपीय बाजार में बेहतर कीमत और मांग मिलने की उम्मीद है। भले ही 4 प्रतिशत शुल्क देखने में कम लगे, लेकिन कम मार्जिन और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले इस कारोबार में यह अंतर वैश्विक खरीदारों के सोर्सिंग फैसलों को प्रभावित करता है। हालांकि यूरोपीय संघ से भारत में आभूषण आयात पर शुल्क करीब 22% बना रहेगा। इससे भारतीय ज्वेलर्स को हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त मिलेगी, इन देशों के ईयू को होने वाले निर्यात पर 2.5 से 4% प्रतिशत शुल्क जारी रहेगा। यह एफटीए उद्योग के लिए 'विन-विन' सौदा है।

भारत का ट्रेड सरप्लस

जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली ने कहा कि यह सौदा अगले तीन वर्षों में यूरोपीय संघ के साथ जेम्स एंड ज्वैलरी का द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रत्न और आभूषण व्यापार में भारत को यूरोपीय संघ के साथ पहले से ही हल्की बढ़त हासिल है। वर्ष 2024 में भारत ने यूरोपीय संघ को 62.8 करोड़ डॉलर के आभूषणों का निर्यात किया, जो ईयू के कुल 16.63 अरब डॉलर के आभूषण आयात का 3.78% है। वहीं पॉलिश्ड हीरों सहित भारत का कुल जेम्स एंड ज्वैलरी निर्यात ईयू को 2.7 अरब डॉलर रहा, जबकि ईयू से आयात 2.5 अरब डॉलर रहा।

एमएसएमई ज्वैलर्स को राहत उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ईयू में एफटीए लागू होने के बाद शून्य शुल्क से डिजाइन-आधारित और उच्च परिशुद्धता वाली भारतीय ज्वैलरी को बढ़त मिलेगी, जहां कीमत के साथ-साथ गुणवत्ता, कारीगरी और समय पर डिलीवरी भी अहम होती है। चूंकि यह सेक्टर एमएसएमई और कारीगरों पर आधारित है, इसलिए रोजगार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर कटिंग, पॉलिशिंग, सेटिंग और फिनिशिंग जैसे कार्यों में रोजगार बढ़ेगा।

ऑटोमोबाइल देश में सस्ती होंगी यूरोपियन लग्जरी कारें

लग्जरी कारों पर घटेगा 100% तक टैरिफ

2.50 लाख यूरोपीय कारों पर हर साल लागू होंगी ये रियायतें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत-ईयू के बीच एफटीए होने से देश में यूरोपीय लग्जरी कारें आने वाले वर्षों में सस्ती हो सकती हैं। इस समझौते के तहत कोटा प्रणाली के माध्यम से यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में चरणबद्ध कटौती होगी। इससे मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फेरारी, लेम्बॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और बेंटले जैसे ब्रांड्स की आयातित कारों की कीमतें भारतीय बाजार में धीरे-धीरे कम होने का रास्ता खुल जाएगा। कोटे के भीतर ईयू में बनी कारों पर आयात शुल्क को धीरे-धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा, जो अभी 70% से 110% तक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफटीए लागू होते ही कारों पर टैरिफ 40% तक लाया जा सकता है, जिसे बाद में समय के साथ 10% तक कम किया जाएगा। ये रियायती दरें हर साल यूरोपीय संघ से आयात की जाने वाली पहली 2.50 लाख कारों पर लागू होंगी।

किन कारों को फायदा

कम आयात शुल्क का लाभ केवल उन्हीं कारों को मिलेगा जिनकी लैंडेड वैल्यू 15,000 डॉलर (13.5 लाख रुपए) से अधिक होगी। इसका उद्देश्य भारत में बजट सेगमेंट की कारों को संरक्षण देना है। ईवी के मामले में ईयू से आयातित ईवी पर मौजूदा शुल्क पहले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। ईवी पर शुल्क में कटौती 2031 के बाद।

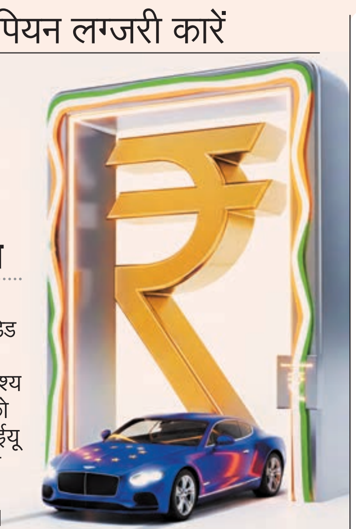

एफटीए लागू होते ही इतनी सस्ती होंगी

मॉडल	मौजूदा कीमत	40% टैरिफ होने पर	कीमतें घटेंगी
स्कोडा ऑक्टेविया	58 लाख	40.5 लाख	17.5 लाख
वोक्सवैगन गोल्फ	52 लाख	36 लाख	16 लाख
बीएमडब्ल्यू एम4	1.55 करोड़	1.08 करोड़	47 लाख
ऑडी आरस क्यू8	2.30 करोड़	1.60 करोड़	70 लाख
पोर्श 911 कैरेरा	2.10 करोड़	1.47 करोड़	63 लाख
लेम्बॉर्गिनी उरुस	4.40 करोड़	3.08 करोड़	1.32 करोड़
फेरारी रोमा	3.80 करोड़	2.66 करोड़	1.14 करोड़
फेरारी 296जीटीबी	5.40 करोड़	3.78 करोड़	1.62 करोड़
फेरारी पुरोसांगुए	10.50 करोड़	7.35 करोड़	3.15 करोड़
बेंटले बेंटायगा	5.00 करोड़	3.50 करोड़	1.50 करोड़
बेंटले फ्लाइंग स्पर	5.25 करोड़	3.67 करोड़	1.58 करोड़
रोल्स-रॉयस घोस्ट	8.95 करोड़	6.26 करोड़	2.69 करोड़
रोल्स-रॉयस कुलिनन	10.50 करोड़	7.35 करोड़	3.15 करोड़
रोल्स-रॉयस फैंटम	10.48 करोड़	7.33 करोड़	3.15 करोड़

(एक्स-शोरूम संभावित कीमतें रुपए में, वास्तविक कीमतें शुल्कढांचे के लागू होने, कार निर्माताओं की नीतियों और डीलरों की कीमत सूची के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।)

ईयू से जापान-ब्रिटेन और अमरीका को कड़ी टक्कर

नई दिल्ली @ पत्रिका. भारत-ईयू एफटीए केवल भारत-यूरोप के व्यापार को ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन को भी प्रभावित करेगा। इसके लागू होते ही भारतीय बाजार में यूरोपीय कंपनियों को प्रिफरेंशियल टैरिफ का लाभ मिलेगा, जिससे जापान, ब्रिटेन व अमरीका जैसे बड़े निर्यातक देशों को भारत में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अनुमान है 11 अरब डॉलर का भारत आयात ऐसा है, जहां ईयू की कंपनियों से जापान-ब्रिटेन-अमरीका को कड़ी टक्कर मिलेगी। इनमें औद्योगिक और हाई-वैल्यू सेक्टर जैसे मशीनरी, मेटल्स आदि शामिल हैं।

इतना निर्यात प्रभावित

	जापान	ब्रिटेन	अमरीका	रूस
ट्रेड प्रभावित	17%	20%	15%	01%
भारत को कुल निर्यात	19.90	6.53	38.98	67.15
ईयू देगा टक्कर	3.47	1.27	5.80	0.85

(राशि अरब डॉलर में)

किन चीजों पर असर?

जापान: मशीनरी, इले. इक्विपमेंट और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में ईयू से टक्कर।

ब्रिटेन: स्क्रैप मेटल, एल्युमिनियम और कार पार्ट्स ईयू के कारण दबाव में होगा।

अमरीका: मेडिकल डिवाइस, रसायन और संचार उपकरण को मिलेगी चुनौती।

सीबैम

कार्बन टैक्स पर भारत को कोई सीधी छूट नहीं

नई दिल्ली@ पत्रिका. ईयू ने स्पष्ट किया है कि भारत को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) के तहत कोई सीधी छूट नहीं दी गई है। सीबैम के तहत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। हालांकि, समझौते में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान जोड़ा गया है। ईयू ने कहा है कि अगर भविष्य में वह किसी अन्य देश को कार्बन टैक्स नियमों में कोई रियायत देता है, तो वही रियायत भारत पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि भारत को अलग से नुकसान में नहीं रखा जाएगा और उसे समान व्यवहार मिलेगा। यह प्रावधान भारत के स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और अन्य ऊर्जा-आधारित उद्योगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इन क्षेत्रों का ईयू को बड़ा निर्यात होता है। इसके अलावा, समझौते में तकनीकी सहयोग, उत्सर्जन मापन और प्रमाणन से जुड़ी मदद का भी प्रावधान है।

विरासत जीआइ टैग वाले उत्पादों की चमकेगी किस्मत

नई दिल्ली. जीआइ टैग सिर्फ एक सरकारी ठप्पा नहीं है, बल्कि देश की मिट्टी, विरासत व सदियों पुरानी कला को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक 'प्रीमियम ब्रांड' बनाने का हथियार है। जब किसी उत्पाद को जीआइ टैग के तहत सुरक्षा मिलती है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू 20% से 30% तक बढ़ जाती है। इस डील से जीआइ उत्पादों को लाभ होगा।

इन भारतीय उत्पादों को मिलेगा वीआइपी दर्जा

दार्जिलिंग और कांगड़ा चाय: इनकी खुशबू-स्वाद का यूरोप दीवाना है। अब इन्हें वहां 'शेंपेन' जैसा दर्जा मिलेगा।

बनारसी साड़ी-कांजीवरम सिल्क: भारतीय बुनकरों की कला अब पेरिस और मिलान के फैशन हाउस में अपनी असली पहचान के साथ बिकेगी।

बासमती चावल: यह एक बड़ा मुद्दा रहा है। डील के बाद भारतीय बासमती को यूरोप में वह खास सुरक्षा मिलेगी जो इसे पाकिस्तान या अन्य देशों के चावल से अलग और कीमती बनाएगी।

अल्फांसो आम (हापुस): जब भारत का हापुस यूरोप पहुंचेगा, तो वहां एक 'प्रोटेक्टेड ब्रांड' के तौर पर सजेगा।

कोल्हापुरी चप्पल-कश्मीरी पश्मीना: इन हस्तशिल्प उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान व ऊंचे दाम मिलेंगे।

ट्रेड डील औपचारिक हस्ताक्षर 2026 के मध्य तक होने की उम्मीद, 1-3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से होगा लागू

अर्थव्यवस्था-एमएसएमई पर ट्रेड डील का ऐसा होगा असर...

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत-ईयू एफटीए पर औपचारिक हस्ताक्षर 2026 के मध्य या अंत तक होने की उम्मीद है। इसके बाद 1-3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोप के प्रीमियम बाजारों तक पहुंच देगा, वहीं कड़े नियम छोटे उद्योगों के लिए नई चुनौती बनेंगे।

स्वच्छता मानक (एसपीएस)

पॉजिटिव: कृषि और फूड एक्सपोर्ट को ईयू में बेहतर पहुंच।

निगेटिव: कड़े मानकों के कारण छोटे किसान बाहर हो सकते हैं।

वस्तुओं का व्यापार

पॉजिटिव: कपड़ा, इंजीनियरिंग, केमिकल और दवा जैसे सेक्टरों में निर्यात बढ़ेगा। टैरिफ कम होने से एमएसएमई की यूरोप के हाई वैल्यू मार्केट तक पहुंच होगी।

निगेटिव: ईयू से आयात बढ़ने पर घरेलू उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है। सस्ते और बेहतर ईयू उत्पादों से घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

प्रतिस्पर्धा नीति

पॉजिटिव: एकाधिकार पर रोक।

निगेटिव: छोटे उद्यमों के लिए कानून समझना होगा कठिन।

मूल देश के नियम

पॉजिटिव: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। नियमों का पालन करने वाली एमएसएमई को प्राथमिकता मिलेगी।

निगेटिव: जटिल नियमों के कारण एफटीए का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ज्यादा दस्तावेज एमएसएमई को हतोत्साहित कर सकते हैं।

सेवाएं और निवेश

पॉजिटिव: आइटी, प्रोफेशनल सर्विसेज को बड़ा अवसर।

निगेटिव: संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

कस्टम्स और ट्रेड सुविधा

पॉजिटिव: तेज क्लियरेंस से व्यापार प्रक्रिया तेज, निर्यात आसान होगा और लेन-देन की लागत घटेगी।

निगेटिव: डिजिटल और प्रशासनिक सुधार लगातार करने होंगे। कमजोर डिजिटल क्षमता वाले एमएसएमई और कारोबारियों को दिक्कत होगी।

तकनीकी बाधाएं

पॉजिटिव: अंतरराष्ट्रीय मानकों से निर्यात गुणवत्ता सुधरेगी।

निगेटिव: सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की लागत बढ़ेगी, जिससे एमएसएमई पर बोझ बढ़ेगा।

विवाद निपटान

पॉजिटिव: स्पष्ट टैरिफ शेड्यूल, नियम-आधारित व्यवस्था।

निगेटिव: एमएसएमई सीधे केस नहीं कर सकते। जटिलता के कारण सलाह की जरूरत।

एक्सपर्ट: **आशीष दुआ,** सीए

जीवन क्षण भंगुर है। अतः हर पल महत्त्वपूर्ण है। उसे जीना है- उत्सव मानकर। व्यक्ति कितना समाज का अंग बनकर जी रहा है अथवा अकेले जी रहा है। उसने सालभर में क्या पाया-क्या खोया, समाज में कहां स्थान पाया!

अस्तित्व का बोधक है जन्मदिन

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

यह विचार आवश्यक है कि जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारित कर पा रहे हैं? हमारी सनातन परम्परा में किसी भी शुभ दिन का प्रारम्भ देवदर्शन व हवन आदि के माध्यम से किया जाता है। जन्मदिन से अधिक शुभ दिन और क्या हो सकता है?

देश हजारों वर्षों से महापुरुषों के जन्मदिन महापर्व की भांति मनाता आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयन्ती आदि भी तो जन्मदिन ही हैं। आज भी गांधी जयंती-नेहरू जयंती जैसी कई स्मृतियां सम्पूर्ण देश प्रतिवर्ष दोहराता है। क्या इनका कोई अर्थ नहीं है? दूसरी ओर आज तो हर बालक भी अपना जन्मदिन मना रहा है, केक काट रहा है, पार्टी कर रहा है/रही है। सभ्यताओं के साथ स्वरूप भले ही बदला हो, महत्त्व नहीं बदला।

जन्मदिन मनाने के दो स्वरूप हो गए- एक तो दूसरे या देशवासी मनाते हैं। दूसरा व्यक्ति स्वयं मनाता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सार्वजनिक स्तर पर भी। जब देश मनाता है, तो व्यक्ति का अवदान (देश के प्रति) अति महत्त्वपूर्ण होता है। देश के विकास-सांस्कृतिक/नैतिक जागरण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी संदर्भ में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय भी अपने-अपने गुरु पदों का जन्मदिन मनाने लगे हैं। कुछ लोकेषणा का भाव भी निहित होता है- इसमें। किन्तु अवतारों के जन्मदिवस बिना किसी लोकेषणा के, उनके दैनिक कृत्यों को- उपदेशों और संकल्पों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। यह एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रसार का, ऐतिहासिक मूल्यांकन का और इसी आधार पर देश में नवजागरण का भी माध्यम बन जाता है।

व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के अस्तित्व का बोध होता है- जन्मदिन से। कालचक्र के व्यक्तिगत इस संवत्सर से अपने जीवन का आकलन-सामाजिक मूल्यांकन, पिछले वर्ष से जीवन का समतुलन कर लेता है। अपनी वर्षभर की उपलब्धियों के आभार-प्रदर्शन का दिन तथा नए वर्ष के लिए संकल्पित कर लेने का दिन होता है।

जीवन क्षण भंगुर है। अतः हर पल महत्त्वपूर्ण है। उसे जीना है- उत्सव मानकर। व्यक्ति कितना समाज का अंग बनकर जी रहा है अथवा अकेले जी रहा है। उसने सालभर में क्या पाया-क्या खोया, समाज में कहां स्थान पाया! जन्मदिन ज्ञान-कर्म, आश्रम व्यवस्था का कालचक्र है। हम आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि उम्र का एक वर्ष कम हो गया है। आत्म-जागरण का बोध बना रहे, इस पर्व पर। अतः इसे दान और आशीर्वाद का हेतु भी माना जाता है। बड़ों से, ईश्वर से प्रार्थना करके शुभाशीष की कामना करते हैं। ताकि कुदृष्टि से भी बचा जा सके।

हम सब मिट्टी के खिलौने हैं। अपना जन्मदिन मनाकर राजी हो जाते हैं। खिलौने फूटते जाते हैं। माया की सहायता से ब्रह्म एक-एक करके खिलौने बदलता जाता है। एक ब्रह्म है, एक माया है- शेष मिट्टी- यानी पंच महाभूत। ब्रह्म अव्यय, माया-अक्षर और माटी क्षर पुरुष। गीता का विज्ञान ही इससे बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। गीता के अव्यय कृष्ण सृष्टि के आलम्बन हैं- सृष्टि का मन (श्वोवसीयस) बने बैठे हैं। इसीलिए सृष्टि को पुरुष प्रधान कहा जाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं- नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। (गीता 7.25)। कृष्ण ही 'अहं बीजप्रदः पिता' भी कह रहे हैं। विश्व की माता भी एक -माया- ही है। सभी 84 लाख शरीरों के माता-पिता एक ही हैं। चलाने वाला ईश्वर भी एक ही रूप में बैठा है- प्रत्येक हृदय में- ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। (गीता 18.61)

भारतीय जीवन दर्शन में जन्म-जन्मान्तर का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। हमारे एक के बाद एक अनेक जन्म होते रहते हैं क्योंकि जीवनचक्र 84 लाख योनियां का है। अनेक जन्मों में व्यक्ति को शरीर तो भिन्न-भिन्न ही मिलते हैं। यह सभी जन्म जिसके होते हैं वह जीव तो एक ही होता है। सभी योनियों में मानव एकमात्र कर्मयोनि है। अन्य सभी भोग योनियां हैं। मानव रूप में हमारा जन्म भी अवतरण दिवस है, भोग योनियों से निकलकर कर्म योनि में आने का। अतः जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण के अनुरूप ही होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन! ''जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब-तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं'' ताकि सज्जनों की रक्षा कर सकूं, दुष्टों का विनाश कर सकूं और धर्म की स्थापना कर सकूं, जिसके लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं।

यह विचार आवश्यक है कि जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारित कर पा रहे हैं? हमारी सनातन परम्परा में किसी भी शुभ दिन का प्रारम्भ देवदर्शन व हवन आदि के माध्यम से किया जाता है। जन्मदिन से अधिक शुभ दिन और क्या हो सकता है? किन्तु हम पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज अपनी जड़ों से छूट रहे हैं।

gulabkothari@epatrika.com

काव्यांजलि...

फैमिली डॉक्टर

डॉ. नरेंद्रपाल जैन

मैं एक डॉक्टर हूं,
कुछ परिवारों का
फैमिली डॉक्टर भी।
उन्हें भरोसा था मुझ पर
कि मेरे पास इलाज है
हर बीमारी का।
अचानक एक परिवार
ग्रसित हो गया
किसी अनजाने वायरस से।
लक्षण भी कुछ अजीब थे।
उस परिवार के लोग
बात नहीं कर पा रहे थे
आंखें मिलाकर।
घर के बुजुर्ग
आंगन में ही
बैठे रहते थे,
उदासी के साथ।
बहु के माथे पर
सलवटें ही रहती थीं
और बेटे के कानों में तो
भारी समस्या हो गई थी..
उसे सिर्फ उसकी
पत्नी की ही बातें
सुनाई देती थी,
मां-बाप की नहीं।
मैं कुछ समझ नहीं
पा रहा था,
उन सबकी बीमारियों को।
मैंने डिक्शनरी और
किताबों में भी ढूंढा,
उसका इलाज,
लेकिन कुछ नहीं मिला।
मुझे अहसास हुआ कि
शायद डॉक्टरी
अधूरी है मेरी।
मेरे पास शारीरिक और
मानसिक बीमारियों का
इलाज तो था, लेकिन
ठीक नहीं कर सका,
पारिवारिक बीमारियों को
एक 'फैमिली डॉक्टर'
होते हुए भी।

कहानी...

कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, रजनी वे जीवन को समझने के लिए होते हैं।' मैंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, मौन से पूरी होती हैं। रजनीश मेरी जिंदगी का वह अध्याय थे जो पूरा नहीं हुआ, पर अधूरा भी नहीं रहा।

एक प्रेम जो समय से आगे था

डॉ. शालिनी सिंह
कथाकार
@patrika.com

रजनीश हमारे दूर के रिश्तेदार के भाई थे। जब वे नौकरी के लिए हमारे शहर आए, तब मैं यह नहीं जानती थी कि कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे भी जीवन का सबसे गहरा अध्याय बन सकता है।

वह पहला दिन आज भी मेरी स्मृति में बिल्कुल साफ है। घर के आंगन में खड़े वे न ज्यादा बोलने वाले, न कोई दिखावा करने वाले। पर उनकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे वे दुनिया को जल्दी में नहीं देखते हों और उसी क्षण, बिना किसी समझ के मेरा मन उनके पास ठहर गया। मैं पहली नजर में ही उन्हें अपना दिल दे बैठी।

हालांकि यह बात सिर्फ मेरे भीतर ही थी। धीरे-धीरे मैं अनजाने ही उनके अनुसार ढलने लगी थी। रविवार अब सप्ताह का सबसे प्रतीक्षित दिन बन गया। उस दिन मैं बाकी दिनों से अलग जागती थी। घर के काम जल्दी निपटाने की हड़बड़ी होती, बालों को संवारने में ज्यादा समय लगता और कपड़े सोच-समझकर चुने जाते- सादे, लेकिन ऐसे, जिन पर उनकी नजर ठहर सके। हर रविवार मैं तैयार होकर उनके आने का इंतजार करती। घड़ी नहीं देखती थी, पर मन समय गिनता रहता था। जब वे आते- तो जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य हो जाता। पढ़ाई का बहाना होता, पर उन कुछ घंटों में जीवन बहुत कुछ सिखा देता था। वे मुझे पढ़ाते- कभी किताबों से, कभी उदाहरणों से और मैं उनकी बातों में शब्दों से ज्यादा भावनाएं पढ़ती थी। कभी-कभी लगता था कि मैं खुद को नहीं, बल्कि उन्हें जी रही हूं। बस एक अदृश्य डोर थी जो हमें बांधे रखती थी। शायद यही वजह थी कि यह प्रेम कभी बोझ नहीं बना। यह इंतजार था, आकांक्षा नहीं। यह चाह थी, मांग नहीं।

वे कभी मुझसे सीधे प्रेम की बात नहीं करते थे। पर उनकी हर सलाह, हर चिंता में एक अपनापन होता था। एक दिन मैंने जिद करके उनसे मेरे लिए एक कविता लिखवाई- 'आई डॉन्ट नो व्हाट यू आर बट आई नो यू आर समथिंग फॉर मी।'

यह पढ़ने के बाद मैंने जैसे अपना नाम ही बदल लिया। मैं रजनीश की रजनी बन गई। घंटों उनके बारे में सोचती रहती। उनके द्वारा मेरे लिए गाया गया गीत-'मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी' और उनकी कविताएं- जिनमें मेरा नाम नहीं होता था, पर मैं हर पंक्ति में खुद को पहचान लेती थी। दो साल ऐसे बीत गए जैसे कोई शांत नदी बहती रहती है- न शोर, न हड़बड़ी, न कोई वादा, न कोई दावा शायद हम दोनों ही जानते थे कि यह रिश्ता समाज की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठेगा।

फिर एक दिन सब बदल गया। उनकी शादी तय हो गई। खबर सामान्य थी, पर असर असामान्य और मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का आश्चर्य हुआ कि मेरा दिल रोया पर आंख से आंसू नहीं आए। शायद मैं पहले ही जानती थी कि कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं होते। कुछ समय बाद मेरी भी शादी तय हो गई। जीवन आगे बढ़ गया- नई जिम्मेदारियां, नया संसार।

पर कुछ यादें थीं, जो समय के साथ धुंधली नहीं हुईं। पच्चीस साल बाद हम फिर मिले। चेहरों पर उम्र की रेखाएं थीं, आंखों में अनुभव। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, फिर मुस्कुराए। हमने सब याद किया वो रविवार, वो पढ़ाई के घंटे, वह बेचैनी, वह चुपचाप ढल जाना- सब याद आ गया।

आज, इतने वर्षों बाद, जब मैं उन रविवारों को याद करती हूं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्योंकि वह इंतजार, वह बेचैनी, वह मौन सब मिलकर मेरे जीवन की सबसे पवित्र स्मृति बन गए हैं। इस बार ना कोई कसक थी ना कोई शिकायत थी। बस सुकून था कि जो हुआ, जैसा हुआ, ठीक हुआ अलग होते समय उन्होंने बस इतना कहा- 'कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, रजनी वे जीवन को समझने के लिए होते हैं।' मैंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, मौन से पूरी होती हैं।

रजनीश मेरी जिंदगी का वह अध्याय थे, जो पूरा नहीं हुआ, पर अधूरा भी नहीं रहा। क्योंकि कुछ प्रेम मंजिल नहीं होते- वे सिर्फ रास्ते को खूबसूरत बना देते हैं।

क्लासिक पुस्तक...

ग्रामीण जीवन की जीवंतता दर्शाता उपन्यास

हिंदी साहित्य में उपन्यास विविध शैलियों में लिखे गए, इनमें से एक शैली आंचलिक उपन्यास लेखन की है। शिवपूजन सहाय द्वारा रचित 'देहाती दुनिया' 1926 ई. में प्रकाशित पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है जो एक ग्रामीण अंचल- रामसहर को केंद्र में रख कर लिखा गया है। इसमें ग्रामीण जीवन और संस्कृत, अभावों, समस्याओं, शोषण, पीड़ा, अज्ञानता और दरिद्रता के बीच सरल जीवन का हृदयस्पर्शी चित्रण है।

प्रकाशन के 100 वर्ष पूर्ण कर चुका यह उपन्यास बाल-सुलभता और व्यवस्थाओं की विकृति को अभिव्यक्त करता है। स्मरण-शिल्प में रचित इस उपन्यास में मां के निश्छल प्रेम, पिता की चिंता और बचपन की शरारतों जैसे मानवीय भावों का अद्‌भुत चित्रण किया गया है। उपन्यास की भाषा में प्रयुक्त ठेठ हिंदी एवं स्थानीय बोलियों के शब्द इसे रोचक बनाते हैं। स्थानीय कहावतों एवं लघु गीतों का प्रयोग बिहार के लोक जीवन को जीवंत करता प्रतीत होता है। भोलानाथ (लेखक के बचपन का नाम) और उसके मित्रों का मिलकर शरारत करना और फिर उसे गीत रूप में प्रस्तुत करना बहुत अद्‌भुत है- 'ऊंच-नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी' या मक्का के खेत में दौड़-दौड़ कर चिड़ियों को उड़ाते हुए कहना - 'रामजी की चिरई, राम जी का खेत/ खा लो चिरई, भर भर पेट'- प्रकृति के सौंदर्य, उसमें व्याप्त इंद्रधनुषी रंग, बाल- मन की चंचलता और ग्राम्य संस्कृति को गहराई से अभिव्यक्त करता है। तेरह अध्यायों में निरुपित इस उपन्यास में धूल, फूल, कीचड़ और गुलाल सब मौजूद हैं। भोर का नभ, दुपहरी, ढलती सांझ, दर्दाती रात्रि, लेखक ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, उसे ज्यों का त्यों चित्रित कर दिया है। इसमें कल्पना कम और यथार्थ अधिक है।

डॉ. दीपमाला गिडवानी,
लेखक

लघुकथा...

समाधान

सुधा बहुत दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? कॉलोनी के पार्क में मॉर्निंग वॉक पर मिली रमा ने आत्मीयता से प्रश्न किया। 'सर्दी बहुत थी, अब थोड़ा मौसम खुशनुमा हुआ तो फिर से ...।' बात पूरी होती उससे पहले ही रमा ने फिर प्रश्न कर दिया - 'वह तुम्हारी कामवाली बाई ठीक से काम कर रही है?'

'बहन, क्या बताऊं? मैं तो तंग आ गई इन कामवाली बाइयों से, कभी गांव जाने की छुट्टी, कभी बच्चों की बीमारी, कभी रिश्तेदारी में जाना है तो कभी कुछ, कभी कुछ, काम पूरा हो ना हो टाइम हो गया, दूसरे घर जाना है, अरे बाप रे... कितने नखरे... इन लोगों के। सबसे बड़ी समस्या मैं शाम को ऑफिस से आती हूं उससे पहले बिटिया आ जाती है, उसे कौन संभाले, कामवाली बाई शाम को कई बार आती ही नहीं है। बिटिया बेचारी अकेली रहती है घर पर...।' सुधा के स्वर में मजबूरी झलक रही थी। सुधा के चुप होते ही रमा ने कहा - 'एक बात कहूं?' सुधा सुनने को आतुर लगी तो रमा ने कहा - 'बिटिया की तरफ से निश्चिन्त रहना चाहती हो तो अपनी सासू मां को बुला लो।'

अनिल कुमार जैन

भारत की पहली महिला स्कीयर...

दुर्गम दूरी तय कर देश का नाम किया रोशन

रीना कौशल धर्मशक्तु

एक जनवरी 2010 को अंटार्कटिका में दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं रीना कौशल धर्मशक्तु । वह आठ महिलाओं के एक अंतरराष्ट्रीय अभियान (कासपर्सकी कॉमनवेल्थ अंटार्कटिक एक्सपेडिशन) का हिस्सा थीं। उनके साथ इस यात्रा में ब्रुनेई, साइप्रस, घाना, जमैका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन की सात अन्य महिलाएं भी शामिल थीं। रीना कौशल ने अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से भारत का नाम वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। यह अभियान राष्ट्रमंडल की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। उन्होंने अंटार्कटिका के तट से दक्षिण ध्रुव तक लगभग 900 किलोमीटर की दुर्गम दूरी 38 दिनों में स्कीइंग करते हुए पूरी की। यात्रा के दौरान उन्होंने शून्य से 40 डिग्री नीचे तक के तापमान और 140 किमी/घंटा की रफ्तार वाली बर्फीली हवाओं का सामना किया। इस दौरान प्रत्येक सदस्य ने 80 किलोग्राम वजन वाला स्लेज खींचा, जिसमें उनका भोजन, ईंधन और उपकरण थे। यह साहसी टीम प्रतिदिन औसतन 8 से 10 घंटे तक स्कीइंग करती थी। इस 8 महिलाओं वाली टीम का नेतृत्व ब्रिटेन की प्रसिद्ध ध्रुवीय खोजकर्ता फेलिसिटी एस्टन ने किया था। रीना कौशल का चयन इस अभियान के लिए पूरे भारत से प्राप्त सैकड़ों आवेदनों में से किया गया था। उन्हें उनके इस अदम्य साहस के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2010 से सम्मानित भी किया गया है। यह यात्रा 13 नवंबर 2009 को शुरू हुई और टीम 31 दिसंबर 2009/1 जनवरी 2010 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची।

रीना का जन्म पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़े परिवार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश दार्जिलिंग में हुई जहां उन्होंने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लिया।

दक्षिणी ध्रुव से पहले उन्होंने माउंट नन, गंगोत्री, कैलाश, प्लूटेड और स्टॉक कांगड़ी जैसी कई चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। रीना के पति, लवराज सिंह धर्मशक्तु, भी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जिन्होंने कई बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है।

वह अमरीका स्थित नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल्स में एक फ्रीलांस प्रशिक्षक रह चुकी हैं, जो लोगों को आउटडोर कौशल सिखाती थीं।

बोधकथा...

ज्ञान का प्रकाश

आश्रम में एक ज्ञानी शिष्य रहता था, परंतु उसे अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा करना पसंद नहीं था। उसका मानना था कि उसके ज्ञान का लाभ केवल उसे ही मिलना चाहिए। एक दिन वह आश्रम के बगीचे में फल तोड़ रहा था। अचानक एक फल के तीखे कांटे उसकी जिह्वा में गहरे चुभ गए। दर्द बहुत भयानक था चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। यद्यपि उसे पता था कि इस चोट का उपचार कैसे करना है, परंतु अत्यधिक पीड़ा के कारण वह स्वयं का इलाज करने में असमर्थ था। तभी गुरुदेव वहां पहुंचे और उसकी स्थिति देखकर शांत स्वर में बोले- 'वत्स! यदि तुमने अपने ज्ञान को अपने साथियों के साथ साझा किया होता, तो आज वे तुम्हारा उपचार कर पाते। ज्ञान को संचित करके रखना व्यर्थ है। गुरुदेव ने आगे समझाया, 'तुम्हारे पास जो विद्या है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम दस शिष्यों को शिक्षित करोगे, तो वे हजारों को मार्ग दिखाएंगे और इस तरह पूरा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।' शिष्य को अपनी भूल का आभास हो गया। वह समझ गया कि ज्ञान केवल अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को रोशन करने के लिए होता है। स्वस्थ होने के बाद, उसने निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उसके ज्ञान का प्रकाश फैल गया। **तारावती सैनी 'नीरज'**

माइंड गेम...

मुहावरे

दो शब्दों के मुहावरों के अर्थ तलाशिए

1. सिर हिलाया
2. तलवे चाटना
3.धाक जमाना
4.नाक रगड़ना
5. पीठ दिखाना
6. अंगूठा दिखाना
7.पांव उखड़ना
8.हाथ मलना
9.कान भरना
10.माथा ठोकना
11.अंक भरना
12.अंगुली उठाना
13. अंगूठा छाप
14.आंखें दिखाना
15.आंखें चुराना
16.गाल बजाना
17.टांग अड़ाना
18.तारे गिनना
19.नाक कटना
20.पगड़ी उछालना

1.असहमति जताना 2.खुशामद करना 3.प्रभाव जमाना 4.गिड़गिड़ाना 5.डर कर भाग जाना 6.मदद मांगने पर मना करना 7.हिम्मत हारना 8.पछताना 9.किसी के विरुद्ध भड़काना 10.दुखी होना 11.स्नेह से लिपटा लेना 12.संदेह करना 13.अनपढ़ 14.क्रोध करना 15.नजरें बचाना 16.डींग हांकना 17.बाधा डालना 18.नींद न आना 19.इज्जत खोना 20.अपमानित करना।

कल्पमेधा

जिसे केवल अपने जीवन की पवित्रता से मतलब है, वह महत्त्वपूर्ण मानव संबंधों का विनाश कर देता है।
– कन्फ्यूशियस

हिंसा की आग

काफी मुश्किल से मणिपुर में हालात थोड़े काबू में आते दिखने लगे थे और इसी वजह से उम्मीद की जाने लगी थी कि वहां जटिल हो चुकी समस्या का अब शायद कोई समाधान निकल सके। मगर राज्य में बीते कुछ दिनों के भीतर जिस तरह हिंसा की एक नई लहर देखी जा रही है, उससे एक बार फिर स्थिति बिगड़ने की आशंका खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले के सोंगलुंग गांव में सोमवार को उग्रवादियों ने कई घरों और फार्म हाउसों में आग लगी दी। यह इलाका कुकी-जो बहुल है और पहले भी कुछ उग्रवादी संगठनों के निशाने पर रहा है। हालांकि आगजनी और हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह साफ है कि इस वारदात का मकसद जातीय तनाव की आग को भड़काना और राज्य को फिर से अराजकता की आग में झोंकना था। इसके संकेत भी सामने आए जब कांगपोकपी जिले के एक कुकी संगठन ने सरकार से चौबीस घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की और ऐसा न होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। संगठन ने यह भी कहा कि जिले के कुकी बहुल इलाकों के गांवों को जानबूझ कर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

अफसोस की बात यह है कि हिंसा की आग से उपजी व्यापक त्रासदी के बावजूद अब भी कोई ऐसा हल सामने नहीं आ सका है, जिससे विवाद और टकराव में शामिल सभी समुदाय सहमत हों और शांति की राह निकल सके। इसके उलट अब ऐसे मुद्दों पर भी हिंसक गतिविधियां सामने आती दिखने लगी हैं, जो दो समुदायों के बीच दूरी को पाटने की एक कड़ी बन सकती थी। हाल ही में एक कुकी युवती से विवाह करने वाले मैतेई युवक की संदिग्ध उग्रवादियों ने हत्या कर दी। दूसरी ओर, खबरों के मुताबिक, सोंगलुंग गांव में ताजा हमला करने वाले उग्रवादी संगठन का कहना है कि जिस इलाके में घरों और फार्महाउसों को जलाया गया, वहां अफीम की अवैध खेती होती थी। जबकि कुकी-जो संगठनों का कहना है कि सोंगलुंग गांव में कभी अफीम की खेती नहीं हुई और अस्थायी फार्महाउसों के बजाय आवासीय मकानों को जला दिया गया। सवाल है कि अगर कहीं कोई अवैध गतिविधि चल रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है या उग्रवादी संगठन की?

यह छिपा नहीं है कि मई, 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा की आग का सबसे बड़ा कारण अलग-अलग स्थानीय समुदायों के बीच कई मसलों पर सीधा टकराव रहा है। हिंसा और अराजकता में अब तक वहां ढाई सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए। मगर अफसोस की बात है कि मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर उपजे विरोध के बाद जारी हिंसा और अराजकता का हल आज तक नहीं निकल सका है, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय विवाद में शामिल जातीय संगठनों के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई। हैरानी की बात है कि देश के किसी भी इलाके में हिंसा और अराजकता जैसे हालात पर काबू पाने के मकसद से गठित सुरक्षा बलों का तंत्र भी वहां नाकाम दिखता है। दरअसल, जिन सवालों पर वहां विभिन्न समुदायों के बीच टकराव खड़ा हुआ, सबसे पहले उसका समाधान निकालने की जरूरत है। मगर इसके लिए ईमानदार इच्छाशक्ति की जरूरत है, जिसका फिलहाल राज्य और शासन से लेकर हर स्तर पर अभाव दिखता है।

अनदेखी का दंश

तेजाब से हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात भी पहुंचता है। कई बार पीड़ित महिलाओं को अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना भी करना पड़ता है, जो उनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। सवाल है कि इस तरह के हमलों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? साथ ही पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय मिल रहा है या नहीं, उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं की स्थिति क्या है और पीड़ितों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं? ये ऐसे सवाल हैं, जिनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी चिंतित है। यही वजह है कि मंगलवार को शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से तेजाब हमलों से संबंधित मामलों का वर्ष वार ब्योरा, अदालतों में उनकी स्थिति तथा पीड़ितों की मदद के लिए पुनर्वास उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से संबंधित कानून में बदलाव पर विचार करने को भी कहा है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में खुले बाजार में तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तेजाब से हमले की घटनाओं में थोड़ी कमी देखी गई, मगर पिछले कुछ वर्षों से यह आंकड़ा फिर बढ़ने लगा है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2017 में तेजाब हमलों के 244 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में ऐसे 176 मामले सामने आए। वर्ष 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 207 हो गया। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि जब खुले बाजार में तेजाब की बिक्री पर रोक है, तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की इस तक पहुंच कैसे संभव हो पा रही है। जाहिर है, कुछ लोग अवैध तरीके से तेजाब की बिक्री करते हैं और सरकारी तंत्र की अनदेखी का दंश कई महिलाओं को झेलना पड़ता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि तेजाब हमले के पीड़ितों एवं उनके परिजनों को कई बार न्याय के लिए वर्षों तक अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनके पुनर्वास की सरकारी योजनाएं भी कागजों तक ही सीमित रह जाती है।

विकास में महिला भागीदारी का सवाल

भारत में विकास का आकलन सड़कों, इमारतों, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों के आधार पर किया जाता है। मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक प्रश्न लगातार अनुत्तरित है कि क्या महिलाएं विकास की इस यात्रा में समान रूप से सहभागी हैं?

सुनिधि मिश्रा

भारत की गिनती विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। विकास की यह यात्रा सड़कों, इमारतों, डिजिटल सुविधाओं, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों के आंकड़ों से मापी जाती है। मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा प्रश्न लगातार अनुत्तरित है, जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं। यह सवाल है- क्या देश की महिलाएं इस विकास यात्रा में समान रूप से सहभागी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यह मसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति की नींव से जुड़ा है। यह सच है कि हाल के वर्षों में महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या कई स्थानों पर छात्रों से अधिक है। परीक्षा परिणामों में भी वे अव्वल रहती हैं। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, जो दशकों के प्रयासों का नतीजा है। इसके बावजूद जब शिक्षा से रोजगार की ओर बढ़ने का समय आता है, तो कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम नजर आती है। यह विरोधाभास भारतीय समाज की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग तैंतीस फीसद के आसपास है, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर पचपन फीसद से अधिक है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और अवसरों की असमानता का द्योतक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। अनेक विकासशील देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी भारत से कहीं अधिक है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, पर उसका स्वरूप चिंताजनक है। अधिकांश महिलाएं कृषि, घरेलू उत्पादन या पारिवारिक श्रम में संलग्न हैं, जहां उन्हें न तो नियमित वेतन मिलता है और न ही सामाजिक सुरक्षा। उनका श्रम आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज तो हो जाता है, मगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षित और कुशल हैं, मगर सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर रोजगार तक उनकी पहुंच सीमित है। इसके परिणामस्वरूप वे या तो अल्प वेतन पर काम करती हैं या फिर कार्यबल से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं।

महिलाओं की कार्यबल से दूरी सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव से भी गहराई से जुड़ी है। आज भी अधिकांश परिवारों में यह अपेक्षा बनी हुई है कि घर, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व मुख्यतः महिलाओं का ही है। जब काम और घर के बीच संतुलन बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले महिला को ही करिअर का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग स्वैच्छिक कम और परिस्थितिजन्य अधिक होता है। समाज में गहराई से बैठी यह धारणा कि महिलाओं की प्राथमिकता घर है और कार्य केवल एक विकल्प, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा है। एक अन्य गंभीर समस्या है 'वेतन असमानता'। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन बीस-पच्चीस फीसद कम वेतन प्राप्त होता है। यह अंतर महिलाओं के आत्मविश्वास, कार्य-संतोष और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महिलाओं की क्रय

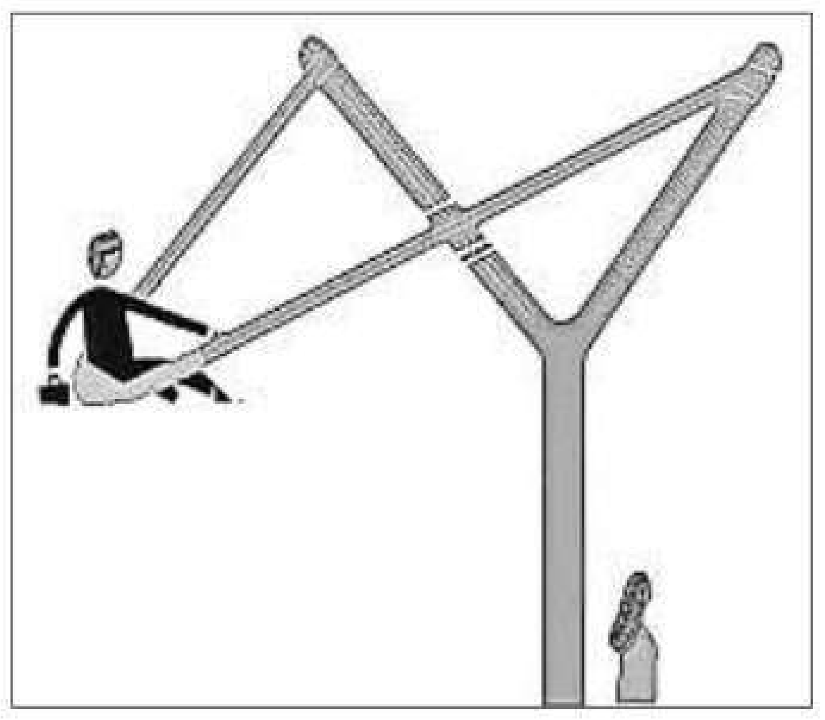

शक्ति और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।

सरकार की ओर से महिला केंद्रित अनेक कानून और योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व लाभ, समान वेतन का अधिकार और महिला-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल है।

> **सरकार की ओर से महिला केंद्रित अनेक कानून और योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व लाभ, समान वेतन का अधिकार और महिला-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल है। मगर समस्या कानूनों की अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। अनेक महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, और जो जागरूक हैं, वे सामाजिक दबाव या नौकरी छूटने के भय से आवाज उठाने से परहेज करती हैं। कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र या तो मौजूद नहीं होते या फिर इतने कमजोर होते हैं कि महिलाएं उन पर भरोसा नहीं कर पातीं।**

मगर समस्या कानूनों की अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। अनेक महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, और जो जागरूक हैं, वे सामाजिक दबाव या नौकरी छूटने के भय से आवाज उठाने से परहेज करती हैं। कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र या तो मौजूद नहीं होते या फिर इतने कमजोर होते हैं कि महिलाएं उन पर भरोसा नहीं कर पातीं। पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में कार्यरत महिलाओं का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां न तो कार्य समय निश्चित है और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव या पारिवारिक कारणों से कार्य से विराम लेती हैं। पुनः कार्यबल में लौटना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि नियोक्ता अनुभव में आए इस अंतर को नकारात्मक रूप से देखते हैं।

हालांकि कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्ष 2025 में तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लाखों महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है। केरल और महाराष्ट्र में भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि यदि नीति, इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग एक साथ आएं, तो परिवर्तन संभव है। हालांकि इन प्रयासों का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा, जब तक समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी केवल महिला सशक्तीकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बराबर की हिस्सेदारी से जुड़ा मसला भी है। विभिन्न अध्ययनों में यह बात उभर कर सामने आई है कि यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान स्तर तक पहुंच जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत अपनी जीडीपी में बीस-तीस फीसद तक की वृद्धि दर्ज कर सकता है, यदि लैंगिक अंतर को समाप्त कर दिया जाए।

आज के दौर में यह जरूरी है कि कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाया जाए, जहां लचीले कार्य समय, सुरक्षित परिवहन, बाल देखभाल सुविधाएं और समान वेतन सुनिश्चित हों। साथ ही परिवार और समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि महिला का कार्य करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। पुरुषों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में समान भागीदारी निभानी होगी। जब तक यह समझ विकसित नहीं होगी, तब तक कानून कागजों में और अवसर आंकड़ों में ही सिमटे रहेंगे। कंपनियों को केवल विविधता के आंकड़े प्रस्तुत करने से आगे बढ़कर वास्तविक समावेशन की संस्कृति विकसित करनी होगी। महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण और करिअर पुनः प्रवेश कार्यक्रम आवश्यक हैं। साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियां और उनका पालन अनिवार्य है।

सवाल यही है कि क्या हम महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी मानते रहेंगे, या उन्हें विकास का सक्रिय सहभागी बनाएंगे? जब तक महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ सुनिश्चित नहीं होती, तब तक यह कहना कठिन है कि भारत का विकास वास्तव में समावेशी है। कानून मौजूद हैं, वादे और घोषणाएं भी हैं, पर अब समय की मांग है कि अवसर भी उतने ही स्पष्ट, सुलभ और समान हों। यह परिवर्तन केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव से ही संभव है।

दुनिया मेरे आगे

स्वयं से संवाद

जयप्रकाश पांडेय 'पहाड़ी'

मिलने-जुलने का संदर्भ आमतौर पर इस तरह देखा जाता है कि हम अपने घर-परिवार से लेकर मित्रों-परिचितों और अन्य लोगों से भेंट-मुलाकात, बातचीत और विचार-विमर्श करते हैं और उससे समाज का एक ऐसा दायरा बनाते हैं, जो हमारे अपने लिए भी जीवन-तत्त्व का वाहक बनता है। मगर हमारे भीतर क्या कोई ऐसा कमरा है, जहां हम अपने आपसे मिलते हैं? आज के समय में यह प्रश्न थोड़ा अनुपयुक्त-सा लगता है, क्योंकि हमारे चारों ओर इतने लोग हैं- दोस्त, परिवार, दफ्तर, भीड़, समुदाय और अब तो मोबाइल की स्क्रीन पर हर समय कोई-न-कोई किसी रूप में उपस्थित रहता है। मगर इस सारी उपस्थिति के बीच क्या हमने कभी यह देखा है कि हम अपने भीतर कहां रहते हैं? किस जगह लौटते हैं, जब शब्द थक जाते हैं, जब शोर भारी हो जाता है, जब हम किसी को कुछ समझा नहीं पाते और किसी से कुछ सुन नहीं पाते? उस जगह का नाम ही शायद हमारे भीतर का अकेला कमरा है।

ऐसा लगता है कि हम सबके भीतर एक ऐसा स्थान होता है, जहां कोई भूमिका नहीं होती। न बेटा, न पिता, न मित्र, न नेता, न अधिकारी, न लेखक, न उच्च, न निम्न। बस केवल हम होते हैं, मानो धरती के नीचे बहती शांत, गहरी और सच्ची जलधारा। वहां कोई शोर नहीं होता, जिससे हम ध्यान भटका सकें। वहां कोई प्रशंसा नहीं होती, जो हमारी थकान पर फूल रख दे। कोई रोशनी नहीं होती, जो रास्ता दिखा दे। वहां हम ही होते हैं, अपने सबसे सच्चे रूप में। शायद इसी कारण हम उस कमरे को लंबे समय से टालते आ रहे हैं। यह कमरा हममें से बहुतों के जीवन में धीरे-धीरे बंद होता जा रहा है। या फिर इस तरह भर गया है कि भीतर प्रवेश की जगह ही नहीं बची। हमने अपने जीवन को इतनी भागदौड़, इतने संकेतों, उत्तरदायित्वों और इतनी अपेक्षाओं में बांध लिया है कि हम अपने भीतर की शांति से दूर होते चले गए हैं।

> **हमारे भीतर का कमरा वह जगह है, जहां दुख भी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखता है। वहां दुख न बड़ा होता है, न छोटा। दुख बस दुख होता है। और जब कोई मनुष्य दुख को दुख की तरह देख लेता है, बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए, बिना भागे हुए, तो दुख धीरे-धीरे ऐसा शांत जल बन जाता है, जिससे मन फिर से जगा हुआ महसूस करता है।**

आज हममें से बहुत लोग दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। कभी-कभी सुबह की चाय के साथ या रात को सोने से पहले एक क्षण आता है जब मन हल्का-सा ठहरता है, लेकिन उसी क्षण हम फोन उठा लेते हैं, खुद से बचने के लिए, क्योंकि अपने भीतर लौटना कठिन है। दरअसल, हमारे भीतर का अकेला कमरा डर का स्थान नहीं, पुनर्मिलन का स्थान है। वहीं हम सीखते हैं कि जीवन केवल लक्ष्य नहीं, अंतरयात्रा भी है। वहीं समझ में आता है कि दुख कोई कमी नहीं, मन का तापमान है और खुशी कोई उपलब्धि नहीं, मन की खुली खिड़की है। वहीं यह भी ज्ञात होता है कि हम दुनिया में चाहे जैसा दिखें, हम भीतर से बहुत साधारण, बहुत मानवीय, बहुत नाजुक हैं। इस नाजुक होने को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। समाज हमें लगातार कहता है कि दिखाओ, बनो, साबित करो, आगे बढ़ो, बोलो, लेकिन हमारे भीतर का कमरा धीरे से कहता है- रुको, सुनो, समझो, स्वीकार करो। यह स्वीकार करो कि हम पूर्ण नहीं हैं, हम थकते हैं, हम टूटते हैं, हम खो जाते हैं, हम गलत होते हैं। और यही वह क्षण है जहां मन पर पड़ी धूल हटती है और हम अपने आप से मिलते हैं। भले हमारी दुनिया तेज हो जाए, रफ्तार बढ़ जाए, उपलब्धियां मिल जाएं, नाम और प्रशंसा बढ़ जाए, लेकिन हम अपने भीतर नहीं लौटते, तो जीवन कहीं न कहीं अधूरा रह ही जाता है, क्योंकि पूर्णता उपलब्धि से नहीं, अपने भीतर के संबंध से पूरी होती है।

यह कमरा कोई पहाड़ की गुफा नहीं, न किसी तीर्थ का स्थान, न कोई दार्शनिक प्रयोगशाला। यह बस एक क्षण है, एक श्वास, एक मौन। जो हम खुद को देते हैं। इस मौन में हम फिर से अपने भीतर रहने वाले मनुष्य को देखते हैं। वही मनुष्य, जो प्रेम कर सकता है, दुख को समझ सकता है, माफ कर सकता है, लौट सकता है। यही लौटना किसी भी विकास, प्रगति, सफलता से कहीं बड़ा, कहीं सच्चा होता है। आज योजनाबद्ध होते जीवन के प्रत्येक चरण में मन को समझने की कोई योजना नहीं होती। हम मन को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, बिना उसे सुने। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। तब मन खुद ही इस कमरे का दरवाजा खोल देता है। मौन में रखा हुआ मन हमसे पूछता नहीं, बस याद दिलाता है कि 'तुम्हें इतना भी अकेला नहीं होना चाहिए कि तुम खुद से दूर हो जाओ।'

हमारे भीतर का कमरा वह जगह है, जहां दुख भी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देता है। वहां दुख न बड़ा होता है, न छोटा। दुख बस दुख होता है। और जब कोई मनुष्य दुख को दुख की तरह देख लेता है, बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए, बिना भागे हुए, तो दुख धीरे-धीरे ऐसा शांत जल बन जाता है, जिससे मन फिर से जगा हुआ महसूस करता है। अपने जीवन में समय हमें यह सिखा देता है कि रिश्तों का स्थायित्व हमारे पास नहीं होता, लेकिन अपने भीतर लौटना हमेशा हमारे पास होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के कमरे को पहचान लेता है, वह अकेला रहकर भी अकेला नहीं होता। यह अकेलापन नहीं, अंतर की संगति है। इसी संगति में मन, अपने ही भीतर, आखिरकार घर पा लेता है।

बजट से उम्मीद

भारत की कुल आबादी का 75 फीसद से अधिक हिस्सा गरीब और निम्न-मध्य आय वर्ग से संबंधित है। इस वर्ग के अधिकांश लोग केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आज स्थिति यह हो गई है कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की थाली में दाल, चावल, सब्जी और रोटी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आज दैनिक मजदूरी करने वाले और निम्न-मध्य वर्ग के लोग खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। आवश्यक खाद्यान्न, खाद्य तेल और मसालों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आगामी बजट में ऐसी ठोस व्यवस्था की जाए, जिससे गरीबों की थाली तक आसानी से दाल-रोटी पहुंच सके। आवश्यक खाद्य सामग्रियों को कर-मुक्त किया जाए या उन पर लगने वाले करों में कमी की जाए। विलासिता की वस्तुओं और सिगरेट-शराब पर कर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गरीब और निम्न-मध्यम को महंगाई से राहत देना बहुत जरूरी है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है, तो देश का आम गरीब नागरिक भी भरपेट भोजन कर सकेगा।

– अरविंद रावल, झाबुआ

अंतिम जन

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ा कर 7.3 फीसद कर दिया है। वैश्विक अस्थिरता, आर्थिक तनाव, शुल्क संकट और कई देशों के मध्य जारी खींचतान के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्था बनना एक चुनौती है। वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मजबूत घरेलू खपत, सार्वजनिक निवेश और निजी पूंजीगत खर्च से चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि की रफ्तार भी संतोषजनक दिख रही है। हालांकि वित्तीय अनुशासन और महंगाई को काबू में रखना सत्ताधारियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अनिवार्य है, वहीं बजट की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि मूल्य वृद्धि की मार और बेरोजगारी से जूझ रहे आम जन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम जन तक पहुंचे।

– आशुतोष तिवारी, जम्मू

उपेक्षित गांव

शहरी इलाकों में दूषित पेयजल के मामले सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मामले तो उजागर भी नहीं हो पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पेयजल जैसी बातें न तो सामने आ पाती हैं, न ही यह चुनावी मुद्दा बन पाता है। अक्सर नाले की सफाई नहीं की जाती है। भूजल पर पड़ रहे असर की भी अनदेखी की जाती है। दूषित जल पीकर बीमार होने की खबर इस बात के लिए काफी है कि विकसित भारत बनने की राह में कई रोड़े हैं। मूलभूत सुविधा जब नागरिकों को मिल ही नहीं पा रही है, तो बाकी सुविधा के लिए क्या कहा जाए? यह दुर्भाग्य की बात है कि नीति आयोग भी मान रहा है कि सत्तर फीसद जल स्रोत दूषित है और लोग इसीलिए दूषित पेयजल पीने के लिए विवश है, क्योंकि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। शहरीकरण का असर यहां भी पड़ा है, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है।

– मिथिलेश कुमार, भागलपुर

खतरे में दिल

आए दिन युवाओं में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं सामने आती हैं। यहां तक कि बच्चों में भी यह समस्या दिख रही है। यह समझ से परे लगता है कि अब मौत का उम्र से कोई संबंध नहीं रह गया है। यह चिकित्सकों के लिए भी चुनौती तो है ही, वहीं शोध का भी विषय है। एक समय था जब आम लोगों में धारणा थीं कि अधिक उम्र के लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं। मगर अब युवा और बच्चे तक इससे प्रभावित दिख रहे हैं। हृदय रोग से बचने के लिए संतुलित भोजन, योग और सादा जीवन अपनाना चाहिए। जितना संभव हो तनाव से दूर रहना चाहिए। कोई समस्या हो, तो परिवार के सदस्यों से बात करनी चाहिए। दुख-सुख साझा करें। आम दिनचर्या में सकारात्मक होकर जीवनयापन करना चाहिए। जितना हम जागरूक और संयमित जीवन जिएंगे, उतना ही निरोगी जीवन जी पाएंगे।

– योगेश जोशी, कंवर कालोनी, बड़वाह

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यहां करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक 'एनसीसी पीएम रैली' को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रैली का विषय 'राष्ट्र प्रथम – कर्तव्य निष्ठा युवा' है, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है। यह रैली महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के भव्य समापन का प्रतीक होगी, जिसमें देश भर से 2,406 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया, जिनमें 898 महिला कैडेट शामिल थीं। इस रैली में 21 विदेशी देशों के 207 युवा और अधिकारी भी भाग लेंगे। इस अवसर पर, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट, राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और चरित्र विकास में उनकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा।

विवादों में घिरे हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

बीरबल शर्मा

कुछ लोगों को मेरी बेटी की शादी से परेशानी है। अरे मुकेश अग्निहोत्री की बेटी को शादी नहीं करनी थी क्या? नफरत की एक सीमा होती है। कुछ लोगों को इसी बात से परेशानी है कि मेरी बेटी का घरवाला आइएएस क्यों है।' हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तो आखिर एक जनसभा में यह कहने की नौबत क्यों आई? उनके इस बयान से जितने विवाद थे, उनका पिटारा खुल गया है। बेटी की शादी में खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही, विपक्ष ने एक जमीन की खरीद को भी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तमाम आरोपों को लेकर जनसत्ता के द्वारा संपर्क किए जाने पर अग्निहोत्री का कहना था, 'मैं नहीं डरता। जिसे जो जांच करानी है, करा ले। शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते।'

बेटी की शादी में खर्च और हिमुडा द्वारा जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'नफरत की एक सीमा होती है।' मैं नहीं डरता। जिसे जो जांच करानी है, करा ले। शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते।'

मुकेश अग्निहोत्री लगातार पांचवीं बार उना जिले के हरोली से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। उन्हें वीरभद्र सिंह राजनीति में लाए थे। प्रदेश के तेज तर्रार नेता के तौर पर उनका नाम लिया जाता है।

उन्होंने कहा, हरोली में खरीदी गई जमीन की तारीखें देख लें। उन्होंने हिमुडा द्वारा खरीदी गई जमीन के कुछ दस्तावेज भी पोस्ट करते हुए कहा कि यह जमीन भाजपा शासन के समय खरीदी गई थी।

आरोप

पिछले कुछ अरसे से हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री लगातार विवादों से घिर रहे हैं। बीते साल नवंबर महीने में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी से तय की, जो उस वक्त उना जिले में ही एक उपमंडल में एसडीएम के पद पर तैनात थे। शादी के समारोह लंबे चले। उना में कई दिन समारोह चले और फिर दिल्ली में भी इसका जश्न हुआ। उपमुख्यमंत्री के राजनीतिक विरोधियों ने शादी पर किए गए खर्च को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए। इनमें विपक्षी भाजपा में कम, मगर उनके ही दल कांग्रेस में ज्यादा थे। हाइकमान तक भी यह बात पहुंचाई और दूसरे माध्यमों से भी इस बात को खूब प्रचारित किया। यही नहीं इतना पैसा कहां से और कैसे खर्च हुआ, इसे लेकर उनके विरोधियों ने मुकेश को खूब घेरा। हाल में, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जमीन की खरीद के एक मामले में घेरना शुरू किया है। हरोली विधानसभा क्षेत्र में हिमुडा कालोनी बनाने के लिए खड्ड नालों वाली जमीन 28 करोड़ में खरीदी गई है। कटवाल का आरोप है कि ऐसी जमीन जिस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसे सर्कल रेट से अधिक दाम पर खरीदकर कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप है कि यह जमीन एक कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति से खरीदी गई।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं। पहली बार कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री का पद अपने इस नेता को सौंपा। मुकेश अग्निहोत्री लगातार पांचवीं बार उना जिले के हरोली से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। उन्हें वीरभद्र सिंह राजनीति में लाए थे। प्रदेश के तेज तर्रार नेता के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री का नाम लिया जाता है। कई बार, जिसमें राज्यसभा के चुनाव के दौरान आया संकट भी शामिल है, वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संकटमोचक बने। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते रहे हैं। वह सार्वजनिक मंच से खुल कर बोल चुके हैं कि उनकी राजनीति में अब कोई और इच्छा नहीं है। उन्हें जनता ने बनाया है। सरकार के तीन साल होने के समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, 'कुछ अफसर निपटाने वाले हो गए हैं। सुक्खू जी भी सुन लें, ऐसे अफसरों को हम आधी रात को ही निपटा दें।'

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने उनके इस बयान को लेकर कहा कि इस धमकी के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच बंद करा दी गई थी। ठाकुर के मुताबिक, मुख्यमंत्री के इशारे पर ही जांच की मंजूरी दी गई थी और इसके लिए प्रदेश के डीजीपी एसआइटी का गठन करने वाले थे, मगर धमकी के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तमाम मुद्दों पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हरोली में खरीदी गई जमीन की तारीखें देख लें। उन्होंने हिमुडा द्वारा खरीदी गई जमीन के कुछ दस्तावेज भी पोस्ट करते हुए कहा कि यह जमीन भाजपा शासन के समय खरीदी गई थी।

यूजीसी के नए नियम पर देश भर में हंगामा है क्यों बरपा

सुशील राघव

देश में उच्च शिक्षा की नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए नए नियम जारी किए। यूजीसी की ओर से 2012 में पहली बार जारी किए गए 'समानता' नियमों का एक नया रूप, अब विवादों में घिर गया है। आखिर क्या हैं नए नियम, जिन पर देश भर में हंगामा बरपा है।

विवाद क्यों है?

विद्यार्थियों व शिक्षकों के एक समूह का मानना है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को परेशान कर सकते हैं और जाति के आधार पर बंटवारा पैदा कर सकते हैं। नियमों का एक पहलू जिसका वे विरोध कर रहे हैं, वह यह है कि 'भेदभाव की झूठी शिकायतों' के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है और नियमों का पालन न करने पर संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया मंचों पर 'यूजीसीरोलबैक' हैशटैग के जरिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये नियम सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए गलत हैं और यह ओबीसी समुदाय के बीच राजनीतिक फायदे के लिए जाति-आधारित बंटवारा पैदा करता है।

क्यों लाया गया?

यूजीसी ने नए नियम सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जारी किए गए हैं। दरअसल, रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इन दोनों ने 2016 और 2019 में कथित जाति-आधारित भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए समानता नियमों को लागू नहीं करने पर फटकार लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्वल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तीन जनवरी, 2025 को इस बात पर जोर दिया कि नियम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होने चाहिए।

हितधारक ने क्या कहा

यूजीसी के नियम ठीक तो हैं लेकिन इसमें निर्दोषों के फंसने की भी आशंका है। इसमें गलत शिकायत करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान नहीं है। हम यूजीसी से मांग करेंगे कि नियमों में इन दोनों प्रावधानों भी डालें। – **वीरेंद्र नेगी,** डूटा के अध्यक्ष

शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद करते हुए भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। – **वीरेंद्र सिंह सोलंकी,** एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री

क्या हैं यूजीसी के नए नियम

यूजीसी ने 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026 को अधिसूचित किया। इन नियमों को लागू करने के लिए हर उच्च शिक्षा संस्थान में एक समान अवसर केंद्र, एक समता समिति और समता समूह होना जरूरी है। समान अवसर केंद्र (ईओसी) वंचित समूहों से जुड़ी नीति को लागू करने की देखरेख करेगा, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी मदद देगा। इन ईओसी में संस्थान के पांच शिक्षक होंगे, इन पांच सदस्यों के लिए किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। नियमों में कहा गया है कि अगर किसी कालेज में ईओसी बनाने के लिए कम से कम पांच शिक्षक नहीं हैं, तो उसके काम उस विश्वविद्यालय के ईओसी द्वारा किए जाएंगे, जिससे वह कालेज जुड़ा हुआ है।

समता समिति : ईओसी में दस सदस्यों वाली एक समता समिति होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख करेगा। इसके पांच सदस्य आरक्षित श्रेणी से होने चाहिए – अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं। इसे शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर बैठक करनी होगी और 15 दिनों के अंदर संस्थान के प्रमुख को रपट सौंपनी होगी। इसके बाद संस्थान के प्रमुख को सात दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी।

समान समूह : इन्हें परिसर में भेदभाव पर नजर रखने और उसे रोकने के लिए बनाया जाएगा। उन्हें सचल रहना होगा और समय-समय पर संवेदनशील जगहों पर जाना होगा। संस्थानों में भेदभाव की घटनाओं की रपट करने के लिए 24 घंटे की 'समता हेल्पलाइन' भी होगी। उन्हें समता दूत नियुक्त करने होंगे जो समता के 'मशाल वाहक' के रूप में काम करेंगे।

सामान नागरिक संहिता : महिला सशक्तीकरण का नया युग शुरू

कुलदीप सिंह राणा

उत्तराखंड में 27 जनवरी को सामान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुए एक वर्ष पूर्ण हो गया। मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी दिवस मनाया। 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में यूसीसी कानून लागू किया गया था। नए कानून के अंतर्गत बीते एक वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकरण हेतु 5 लाख आवेदन आए, जिसमें 4 लाख 74 हजार 447 दंपत्तियों को यूसीसी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 147 युवा जोड़ों ने सह-जीवन में रहने हेतु पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के एक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया है।

नए कानून के अंतर्गत बीते एक वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकरण हेतु 5 लाख आवेदन आए, जिसमें 4 लाख 74 हजार 447 दंपत्तियों को यूसीसी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 147 युवा जोड़ों ने सह-जीवन में रहने हेतु पंजीकरण करवाया है।

उपलब्धि

यह भी जानकारी आई है कि सहजीवन के 90 आवेदन को निरस्त भी किया गया है, जिसमें उनकी मंशा को अनुचित पाया गया है। 2 आवेदन सहजीवन से पृथक होने के लिए भी प्राप्त हुए। यूसीसी के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से संशोधन अध्यादेश 2026 लाया गया है, जिसमें शादी और सहजीवन संबंध से जुड़े 18 से अधिक सुधार शामिल हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी),अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

यूसीसी लागू होने से पहले राज्य में 2010 में पारित एक्ट प्रभावी था, जिसमें मात्र विवाह का पंजीकरण किया जाता था इस एक्ट के अंतर्गत बीते 15 वर्षों में राज्य में 3 लाख 30 हजार पंजीकरण हुए थे। यूसीसी के एक्ट में प्रदेश में विवाह के अतिरिक्त सहजीवन संबंध का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 27 जनवरी को संपूर्ण प्रदेश में यूसीसी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देहरादून गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम स्थल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लेकर विभिन्न स्कूल कालेजों के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। प्रदेश सरकार का मानना है कि यूसीसी, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप पूरा किया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य की जनता ने सक्रिय सहयोग दिया है तथा विवाह, तलाक, वसीयत एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बड़ी संख्या में पंजीकरण कराए गए हैं। यूसीसी को लेकर राज्य में एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर शत प्रतिशत खरा उतरी है। मंगलवार को देहरादून स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की मुसलिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। वहीं, धामी ने जोर देकर कहा कि वह राज्य के मूल अस्तित्व और देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे चाहे उन्हें 'नफरती भाषण' देने वाला ही क्यों न माना जाए।

भारत पर्व

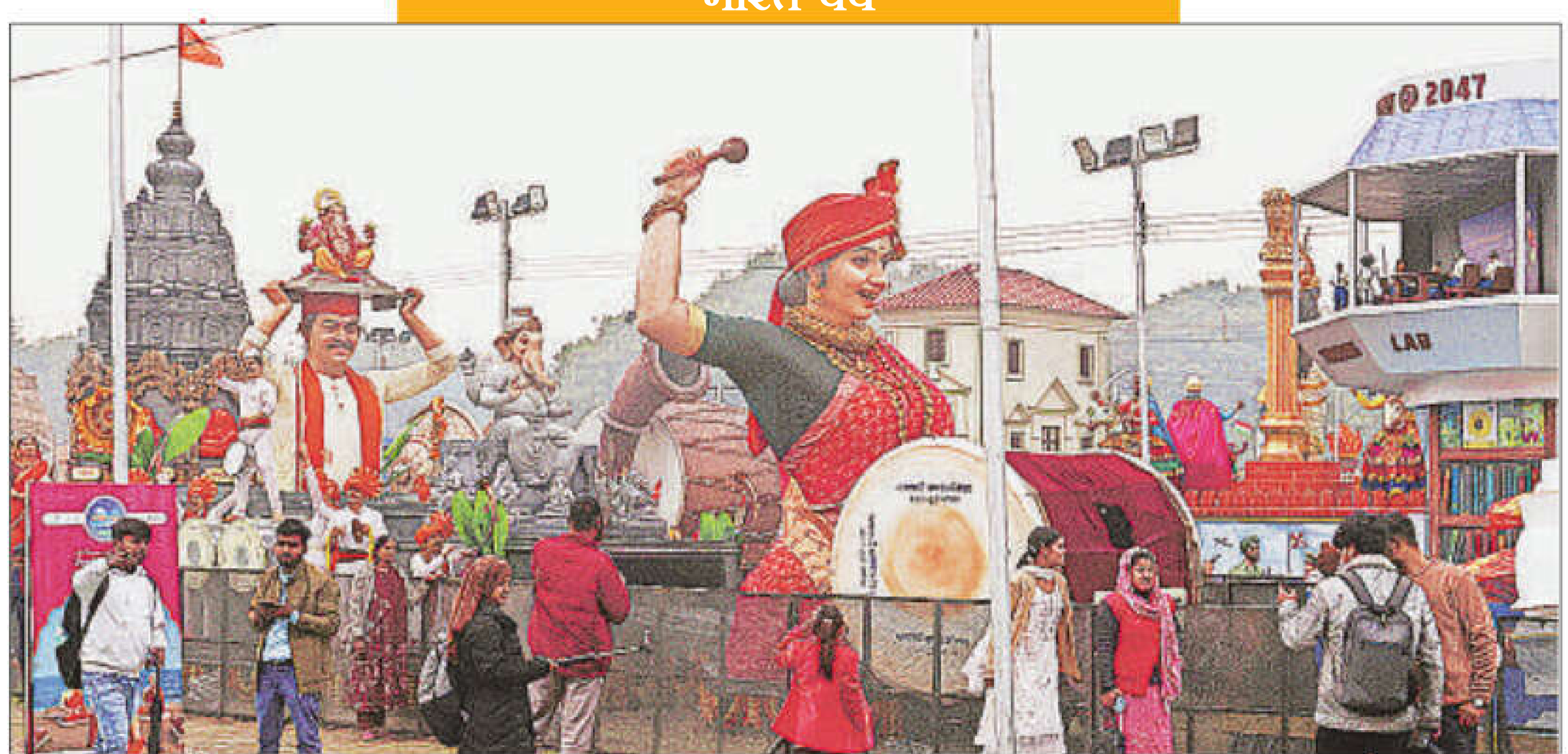

नई दिल्ली में भारत पर्व समारोह के दौरान लाल किले पर प्रदर्शित गणतंत्र दिवस की झांकी के पास जमा आगंतुक ।

कुल मनोरोगियों में 60 फीसद 35 वर्ष से कम उम्र के

राकेश शर्मा

समाज में बढ़ते एकल परिवार के साथ डिजिटल क्रांति मनोरोग की समस्या को बढ़ा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कामगार वर्ग है।

रपट

भारतीय मनोरोग सोसायटी के रपट के अनुसार भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित कुल मरीजों में से करीब 60 फीसद की आयु 35 वर्ष से कम है। विशेष रूप से 15 से 21 वर्ष की आयु के किशोर और युवा मानसिक समस्याओं के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी। भारतीय मनोरोग सोसायटी के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष डा निमेष जी देसाई ने बताया कि देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है। पहले पहले मानसिक रोगों के पीछे मुख्य रूप से अनुवांशिक और शारीरिक कारण जिम्मेदार माने जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि मनोरोग की समस्या को कम करने के लिए देशभर के मनोरोग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए सुझाव रपट को सरकार को सौंपा जाएगा। साथ ही मांग रखी जाएगी कि स्कूल, कालेज और समाज के स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए।

डा देसाई के अनुसार, वर्तमान समय में मानसिक परेशानी, सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक अपेक्षाएं और तेजी से बदलता डिजिटल वातावरण किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, कृत्रिम मेधा (एआइ) और डिजिटल प्लेटफार्म का अत्यधिक उपयोग किशोरों की दिनचर्या और व्यवहार में बड़े बदलाव ला रहा है। उन्होंने बताया कि इन कारणों से किशोरों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी देखी जा रही है। पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों में उनकी रुचि घट रही है।

क्रेडिट कार्ड : कर्ज के जाल में फंस रहे युवा, शिकायतों में बढ़ोतरी

हिमांशु अग्निहोत्री

क्रेडिट कार्ड की आसान उपलब्धता उपभोक्ताओं को कर्ज के जाल में फंसा रही है। बढ़ते उपयोग के साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। मुख्य शिकायतें ब्याज दरों में अनियमितता, अनावश्यक फीस, गलत बिलिंग और रिकवरी एजंट द्वारा प्रताड़ना से जुड़ी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की रपट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 13,34,244 शिकायतें दर्ज की गईं। प्रताड़ना से तंग आकर हर साल कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मरने वालों का आंकड़ा एक साल में पांच से छह हजार के बीच है। वर्ष 2025 में आए एनसीआरबी की रपट के मुताबित, 2023 में लगभग 6500 लोगों ने क्रेडिट कार्ड को लेकर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। शिकायतें मुख्य रूप से ईमेल, पत्र या सीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2021-22 में क्रेडिट कार्ड से जुड़ीं 32,162 शिकायतें मिलीं। 2022-23 में 24,549, 2023-24 में 33,198 और 2024-25 में 41,457 मामले मिले। ये आंकड़े साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। वहीं, लोन और एडवांस लेने पर भी उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। 2021-22 में 24,507 मामले, 2022-23 में 39,579 मामले, 2023-24 में 54,336 मामले और 2024-25 में 52,427 दर्ज किए गए। एप और बैंकिंग सेवा में भी उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ी।

चिंता

पांच हजार लोग कर चुके आत्महत्या

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रपट के अनुसार, वर्ष 2020 में लभभग पांच हजार लोगों ने क्रेडिट कार्ड भुगतान और कर्ज को लेकर प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की। 2021 में लगभग साढ़े छह हजार लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। 2022 में संख्या में वृद्धि हुई, जहां करीब 7000 मामले मिले। 2023 में लगभग 6500 लोगों ने ये कदम उठाए। आखिरी रपट 2025 में जारी की है, जो 2023 से संबंधित मामलों से है। इसमें जो ग्राहक जागरूक हैं, तो वे आरबीआइ से जुड़े पोर्टल पर शिकायत करते हैं या अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसमें उनकी परेशानी का हल किया जाता है और जो जागरूक नहीं होते तो मजबूरन कोई कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। कई मामले अदालत तक पहुंचे, जहां सुनवाई के साथ साथ कई बैंकों पर जुर्माने भी लगाए गए।

आरबीआइ की रपट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 9,34,355 शिकायतें प्राप्त हुईं। 2022-23 में कुल 7,03,544 मामले दर्ज हुए। 2021-22 में अप्रैल से नवंबर तक 2,09,196 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 90 फीसद डिजिटल मोड से थीं। जुलाई 2020 से मार्च 2021 में 2,73,204 शिकायतें दर्ज हुईं। इस दौरान कोविड महामारी के प्रभाव से यहां शिकायतों की संख्या घटी। क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क जो ग्राहकों पर लगाए जाते हैं, वे हैं ज्वाइनिंग और वार्षिक, फाइनेंस/ब्याज, विलंब भुगतान, नकद निकासी, ओवर-लिमिट, जीएसटी, विदेशी मुद्रा मार्कअप। क्रेडिट कार्ड धारक सौरभ द्विवेदी ने बताया कि मेरे पास सरकारी अंक का कार्ड है।

एजेंट ने मुझसे बोला कि ये लाइफटाइम फ्री है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन एक साल बाद उपयोग करने के बाद बैंक के बिना वजह के सर्विस चार्ज काट लिए। जब कि मैंने उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया। एक अन्य उपभोक्ता सुधांशु कुमार ने बताया कि मैं 3 से 4 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता हूं। लेकिन उसमें महीने दर महीने कई चार्ज लगा देते हैं। शिकायत भी कई बार की, लेकिन कभी सुनवाई होती है तो कभी नहीं होती। हालांकि, यह मामला उपभोक्ताओं से जुड़े सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नहीं बल्कि लोन से भी जुड़ा है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक महीने भी देरी कर देता है तो उसे बैंक द्वारा नियुक्त की गई एजंसियों के कर्मी उनके रिश्तेदारों के नंबर पर काल करके परेशान करते हैं या ग्राहक से अभद्र भाषा में बात करते हैं।

प्रेरणा

कुछ ही लोग सोच पाते हैं, लेकिन राय सभी के पास होती है। - जॉर्ज बर्कले

संपादकीय

ईयू से डील अमेरिका को एक शालीन जवाब है

ट्रम्प के टैरिफ, बलप्रयोग और रोजाना की धमकियों ने दशकों से सहज रूप से चल रही विश्व-व्यवस्था की चूलें हिला दी हैं। इसने दुनिया को विकल्प ढूंढने पर भी मजबूर किया। 27 देशों के संगठन ईयू ने भारत से 19 साल से उबड़-खाबड़ रास्तों पर डगमगाती ट्रेड डील अंततः मुकम्मल की। अब भारत अपनी कृषि और संलग्न वस्तुएं, टेक्स्टाइल और मेटलर्जी उत्पाद 22.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाले संगठन को बेच पाएगा और उसकी हाई-एंड कारें, तकनीकी, हथियार और शराब कम दरों पर हासिल कर सकेगा। भारतीय टैलेंट के लिए ईयू में नया द्वार खुलेगा। रूस से तेल न खरीदने की कोई शर्त नहीं होगी, ना ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने की गति समय-सीमा में बढ़ाने की एकमात्र शर्त। ईयू प्रमुख का मानना है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ईयू जानता है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के भारत के प्रयास दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा हैं। बहरहाल यह डील ट्रम्प को एक शालीन जवाब है कि अमेरिका के बिना भी दुनिया दौड़ सकती है। आने वाले वर्षों में ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा। इसके अलावा सामरिक क्षमता वाले जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क से व्यापार-विस्तार का भी अपना महत्व होगा। ट्रम्प को उम्मीद थी कि उनके इशारे पर ईयू भी आरोप लगाएगा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे परोक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ वित्तीय मदद दे रहा है और ऐसा कहकर वह भारत से दूरी बनाएगा। लेकिन ईयू और नाटो का अपमान उसके हमारे साथ खड़े होने का बड़ा कारण है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

लेन-देन की मुलाकात में भी आत्मीयता को बचाएं

संबंधों को इतना अच्छा बना लें कि कोई काम रुके ना। इसको जनसम्पर्क की कला कहते हैं। तुलसीदास जी अपने साहित्य में ऐसे संकेत देते रहते हैं। गरुड़ काकभुशुंडि जी के पास पहुंचे तो उनके स्वागत में काकभुशुंडि जी ने एक पंक्ति बोली- नाथ कृतारथ भयउं मैं तव दरसन खगराज, आयसु देहु सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। पक्षीराज आप जो आज्ञा दें, वहीं करूं। बताइए किस कार्य के लिए आए हैं? हम भी यह प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि आजकल हर मुलाकात लेन-देन पर टिक गई है तो आत्मीयता तो समाप्त ही हो गई। लेकिन हम कोशिश करें कि यह पंक्ति हम दिल से बोलें। सामने वाले से पूछें कि बताइए क्यों आए हैं और आपको देखकर हम बहुत खुश हुए। ये दो बातें उनके ऊपर 'हैलो इफेक्ट' करेंगी। मार्केट की भाषा में 'हैलो इफेक्ट' का अर्थ होता है किसी एक ब्रांड की वस्तु का उपयोग करें और वो पसंद आए तो उसी ब्रांड की दूसरी वस्तु का उपयोग करना। ठीक ऐसा ही होगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे इतना जुड़ जाएगा कि फिर वो आपकी हर बात सुनेगा, मानेगा।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

नए यूजीसी नियम सकारात्मक कदम

यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पृष्ठभूमि वाला छात्र कैंपस में अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। जब शिक्षा का माहौल समावेशी होगा, तभी सही मायने में योग्यता को निखरने का अवसर मिल सकेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है और हम खुले दिल से इसका समर्थन करते हैं। -जितेंद्र कुमार, देवराला, राजस्थान

बैंकों में फाइव-डे वीक क्यों नहीं?

देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों में 27 जनवरी को हड़ताल रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच मार्च 2024 में ही फाइव-डे वीक पर सहमति बन चुकी। जब सरकारी दफ्तरों और कई कंपनियों तक में फाइव-डे वीक लागू है तो बैंक कर्मचारियों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फाइव-डे बैंकिंग कोई लग्जरी नहीं, यह आर्थिक और इंसानी तौर पर एक जरूरत है। -एसके खोसला, चंडीगढ़

रील्स के लिए जीवन दांव पर क्यों?

सूने जंगलों और वीरान पहाड़ों में जाकर दुनिया को ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? खराब रास्ते और मौसम की परवाह किए बिना एक वीडियो-कंटेंट के लिए क्या अपनी जिंदगी गंवा देंगे? इसमें कौन-सी लाभ वाली बात हो गई? मौत जीवन की सच्चाई है, लेकिन ऐसी मौतें तो खुद ही बुलाई जाती हैं। रील्स के फेर में पड़कर अपने परिजनों को जीवनभर का दुःख दे देना सही नहीं है।
-शेर सिंह मेरूपा, लाहुल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश

तीर्थ स्थलों में अपनाएं तिरुपति मॉडल

क्या हम भगवान के सामने भी वीआईपी और नॉन-वीआईपी का फर्क बनाए रखना चाहते हैं? या हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां सबसे पहले कमजोर और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए? यदि तिरुपति जैसा मॉडल देशभर के तीर्थ स्थलों पर अपनाया जाए तो भीड़-भगदड़ कम होने के साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी वही है, जिसे वास्तव में सहारे की जरूरत है। -सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम, मध्य प्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

कंगारू रैट को जीवनभर पानी की जरूरत नहीं पड़ती

उत्तरी अमेरिका के सूखे रेगिस्तानों में पाया जाने वाला छोटा-सा जीव कंगारू रैट ऐसा स्तनपायी जीव है, जिसे जीवनभर पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल, कंगारू रैट अपनी पानी की जरूरत को भोजन से ही पूरा कर लेता है। यह जीव बीजों को खाता है और बीजों का वसा विखंडित होने से बना मेटाबॉलिक वॉटर ही इसकी जल की आवश्यकता पूरी कर देता है। इसकी किडनी इतनी बेहतर अनुकूलित होती है कि पानी की हरेक बूंद सोख कर यूरिन को लगभग क्रिस्टल रूप में बना देती है।

20 से अधिक प्रजातियां कंगारू रैट की अब तक पहचानी जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश आज भी अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं।

बामुलाहिज़ा • नया गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के समय की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए...

'ट्रम्प पीड़ित संघ' बनाने का यही सही समय

मिडिल पावर्स

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

2006 के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' में भारत सरकार और कॉर्पोरेट जगत ने मिलकर 'इंडिया एवरीव्हेयर' आयोजन को प्रायोजित किया था। उसके तहत कई इवेंट, पार्टियां की गईं; संगीत के कार्यक्रम हुए और खुलकर उपहार बांटे गए। तब भारतीय अर्थव्यवस्था बम-बम कर रही थी। हमारे 'टेक सेक्टर' का सितारा बुलंदी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 2026 में नजारा अलग था। भारत के नौ राज्यों ने दावोस में मंडप लगाए थे और छह मुख्यमंत्री मौजूद थे, मगर हालात 2006 के बिलकुल उलट थे। भारत के लोग अपने ही टीवी चैनलों के सिवा और कहीं खबरों में नहीं दिख रहे थे।

लेकिन जब जी-7 के पांच प्रमुख नेता भारत के साथ व्यापार समझौते की बढ़-चढ़कर बात कर रहे थे, तब अपना सीना ठोकने की कोई जरूरत थी भी नहीं। ईयू की उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे \'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा। बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब वे यूक्रेन के मामले में भारत के रुख की आलोचना कर रही थीं। लेकिन दुनिया किस कदर बदल चुकी है, इसका अंदाजा कनाडा के मार्क कार्नी के जोरदार भाषण में भारत के साथ व्यापार समझौते के जिक्र से बेहतर किसी और बात से नहीं लग सकता है। जबकि उनके पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो ने तो वार्ताओं को स्थगित ही कर दिया था।

ट्रम्प और उनके हॉवर्ड लुटनिक, स्कॉट बेसेंट और इलॉन मस्क सरीखे लोगों में ही दावोस इतना उलझा हुआ था कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इन लोगों से टक्कर लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। कार्नी, मैक्रों और मर्ज अलग-अलग पैमाने पर यही करते नजर आए। कार्नी ने तो पश्चिमी गठजोड़ के अंत की घोषणा ही कर दी। भारत के लिए सबसे मुफीद यही था कि इस झगड़े से दूर ही रहो। इसका एक फायदा यह निकला कि ट्रम्प से नाराज पारम्परिक, अमीर, विकसित अमेरिकी सहयोगी नए मित्रों की तलाश करते दिखे। हम इसे 'ट्रम्प पीड़ित' गठजोड़ कह सकते हैं! कार्नी ने अपने भाषण में 'मिडिल पावर्स' की जो परिभाषा दी और ट्रम्प की दुनिया में उनकी जो जगह बताई, वह एक युग को परिभाषित करने वाला विचार बन गया। दो सर्वशक्तिमान ध्रुवों वाली दुनिया में अमेरिका एक क्रूर और बर्बर 'दादा' वाली भूमिका में है और चीन एक बेहद चतुर दबंग की भूमिका में, जो अपनी आर्थिक तथा रणनीतिक छुरी को इतनी बारीकी से घुमाता है कि आपको दर्द भी नहीं महसूस होता। ऐसे में आपके सामने विकल्प क्या है? आप दोनों में से किसी एक महाशक्ति के याचक बन सकते हैं। या पाकिस्तान की तरह दोनों के याचक बन जाएं, जो कि दुर्लभ से भी दुर्लभ है। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आप एक ऐसे देश हैं, जो शक्तिशाली भी है और स्वाभिमानी भी, या जिसकी जनता अपनी गरिमा को इतना मूल्यवान मानती है कि घुटने टेकने वाले नेता की छुट्टी कर देती है?

दो महाशक्तियों के बाद 10 टॉप अर्थव्यवस्थाओं की गिनती शुरू करें तो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर क्रमशः जर्मनी, जापान और भारत दिखेंगे, जिन्हें 'मिडिल पावर्स' में शुमार कर सकते हैं। ब्रिटेन को फिलहाल छठे और रूस को नौवें नंबर पर रख सकते हैं। फ्रांस और इटली को 7 और 8 पर और कार्नी के कनाडा को 10वें नंबर पर रख सकते हैं। 11 से लेकर आगे की गिनती में ब्राजील, स्पेन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया आदि हैं। ये सारे देश दुनिया में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का अमेरिका सबके साथ तिरस्कार वाला व्यवहार करता है। ये देश चीनी खेमे में भी नहीं जा सकते। क्या ये किसी तरह की एकता, साझा मकसद और साथ मिलकर मोलभाव करने की थोड़ी ताकत बना सकते हैं?

क्या आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ याद है? यह एक सच्ची ताकत नहीं बन पाया, तो इसके कई कारण हैं। पहला यह कि यह सैद्धांतिक रूप से तो गुटनिरपेक्ष था, मगर इसका ज्यादा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। दूसरे, इसमें ऐसे सदस्य नहीं थे, जिन्हें उस समय 'मिडिल पावर्स' में गिना जा सकता था। भारत उसमें सबसे बड़ा देश था, लेकिन उसका नैतिक तेवर उसकी आर्थिक तथा सैन्य कमजोरियों तथा निर्भरताओं के कारण फीका पड़ जाता था। और कुछ समय बाद तो भारत सोवियत संघ का संधिबद्ध सहयोगी ही बन गया था।

दुनिया के 'मिडिल-पावर' देश क्या अब एकजुट होंगे?

अमेरिका पर दुनिया के देशों का भरोसा टूट चुका है। 'मिडिल पावर' वाला परिदृश्य कायम हो रहा है। क्या यह कारगर होगा? दावोस में मस्क ने जो कहा, यहां हमें उसे याद रखना होगा-निराशावादी और सही होने से बेहतर है आशावादी और गलत होना!

आज जब जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और यूरोप के ज्यादातर देश इस नए विश्व पर नजर डाल रहे हैं, तब क्या एक नए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समय आ गया है? बेशक यह आज के समय के साथ तालमेल करती नई विशेषताओं से लैस होगा। इसमें विचारधारा नहीं, व्यावहारिकता पर जोर होगा। अमेरिका-चीन के साथ व्यापार तो करो, लेकिन एक समूह के रूप में मोलभाव की ताकत रखो। यहां हम कार्नी के उपरोक्त भाषण को याद करें, जिसमें वे कहते हैं- 'अगर हम खाने की मेज पर नहीं होंगे, तो खाने का मेनू बन जाएंगे।' इसलिए 'मिडिल पावर' देशों को साथ आना पड़ेगा, साझा हितों की खोज करनी होगी और विरासत में मिली खेमेबंदियों से आगे देखना होगा। जी-7, जी-20, नाटो और यूएन तो आज बेदम ही हो चुके हैं। वहीं ब्रिक्स और एससीओ जैसे दूसरे कुछ समूह चीन के दबाव में हैं।

ट्रम्प को किसी समूह से निबटना नापसंद है। इसकी सबसे साफ मिसाल नाटो के प्रति उनकी नफरत है। उनके पास विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), पेरिस जलवायु समझौता, संयुक्त राष्ट्र और क्वाड तक के लिए समय नहीं है। चूंकि वे आप से संकेतों में बात नहीं करते, बल्कि आपको घूरते हुए अपने घोर स्वार्थ की बात करते हैं, इसलिए उनके दिमाग को समझना अब ज्यादा आसान है। वे किसी भी बहुपक्षीय मेल को अमेरिकी ताकत को कमजोर करने वाला मानते हैं। वे किसी समूह से नहीं, हर देश से अलग-अलग बात करेंगे। और वे चीन को छोड़ हर देश से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस तरह वे वार्ता की मेज पर \'कोर्लिओन सिद्धांत' को ले आते हैं, जो यह कहता है कि मैं तुम्हें जो पेशकश कर रहा हूं उसे तुम मना नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड इसका सबसे ताजा उदाहरण है। यूक्रेन भी उसी दिशा में है। चीन को छोड़ कोई भी देश ट्रम्प के साथ बराबरी की हैसियत से बात नहीं कर सकता। इसलिए, जो 'मिडल पावर' देश बहुपक्षीय संगठनों के मूल आधार थे, वे आज बेसहारा और ट्रम्प की मर्जी पर निर्भर महसूस कर रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • बेहतर तालमेल चाहती है भाजपा

पार्टी, सरकार और संघ के कामकाज का नया मॉडल

सियासत

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन की उम्र लगभग उतनी ही है, जितनी कि स्वयं पार्टी की। प्रधानमंत्री ने इस बात को छिपाया नहीं है कि पार्टी की मंशा युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करने और उसका समर्थन हासिल करने की है। नबीन को चुनकर भाजपा नेतृत्व ने गियर बदला है। पार्टी अब संगठन के भीतर से उभरे कार्यकर्ताओं को महत्व देने की ओर लौटती दिख रही है। एक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रदान किया जाएगा और पार्टी अमित शाह की निगरानी में काम करती रहेगी। वहीं नबीन पार्टी-सरकार-संघ के कामकाज के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें उन राज्यों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पार्टी अभी कमजोर है और जहां 2026 और 2027 में चुनाव होने हैं।

देखें तो नितिन नबीन का उदय सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, जहां भाजपा उपयुक्त समय आने पर सरकार का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रही है। उनकी जाति (कायस्थ) भी ऊंची जातियों को आश्वस्त करती है, जो ओबीसी और दलितों के पक्ष में भाजपा द्वारा अपनाई जा रही पहचान-आधारित राजनीति से असंतुष्ट हैं। नबीन की पदोन्नति केवल पार्टी कार्यकर्ता को महत्व देने तक ही सीमित नहीं है, ताकि जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया जा सके। भाजपा अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जब वह देश के पूर्व और दक्षिण दोनों हिस्सों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी को ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है, जो उसके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सके।

वर्षों से पार्टी की कमान राष्ट्रीय कद के दिग्गजों के हाथों में रही है। इसकी शुरुआत 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। वाजपेयी ने नई पार्टी के मंत्र के रूप में गांधीवादी समाजवाद को सामने रखा था, ताकि उसे मध्यपंथी दिशा में ले जाया जा सके। यह दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित पार्टी के वैचारिक आधार से अलग था। वाजपेयी और आडवाणी ने पुराने जनसंघ को पुनर्जीवित करने का विकल्प नहीं चुना, जिसने आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने वाली जनता पार्टी में अपनी पहचान विलीन कर दी थी।

1984 में लोकसभा में भाजपा के मात्र दो सीटों पर सिमट जाने के बाद वाजपेयी ने 1986 में आडवाणी के लिए रास्ता छोड़ दिया। पार्टी में आडवाणी युग की शुरुआत हुई और वे तीन बार अध्यक्ष बने। उनके बाद मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने पार्टी की कमान संभाली। 2019 में अमित शाह अध्यक्ष बने, जिनके नेतृत्व में पार्टी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनके बाद अध्यक्ष बने जेपी नड्डा को पार्टी के लिए भाग्यशाली माना गया। हालांकि उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के आम चुनावों तक उन्हें विस्तार दिया गया। चुनावों के बाद पार्टी नेतृत्व और संघ नेतृत्व के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए। कई नामों पर चर्चा हुई। लेकिन बताया जाता है कि दिसंबर 2025 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अमित शाह और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद नबीन के नाम पर अंतिम मुहर लगी।

नबीन को चुनकर पार्टी अब संगठन के भीतर से उभरे कार्यकर्ताओं को महत्व देने की ओर लौटती दिख रही है। एक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। नबीन पार्टी-सरकार-संघ के कामकाज के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

संघ हमेशा से संगठन को प्राथमिकता देने का पक्षधर रहा है और उससे गहराई से जुड़े नबीन पुराने ढर्रे के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने चार विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिससे उन्हें जन-राजनीति की गतिशीलता की समझ है। साथ ही वे संगठन के 'नट-बोल्ट' संभालने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। हालांकि, नीतीश सरकार में मंत्री रहने के बावजूद वे ऐसा चेहरा नहीं थे, जो बिहार से बाहर व्यापक रूप से पहचाना जाता हो।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

नजरिया • 'रेल बजट' की जगह 'बजट में रेलवे'

विकास पटरी पर रहे, इसका दारोमदार रेल के पहियों पर

रेलवे

मोहम्मद जमशेद
चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो

रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिलाकर पेश करने का यह दसवां वर्ष होगा। इस कालखंड में देश में हुए विकास ने न सिर्फ जीडीपी में बढ़ोतरी की, बल्कि तमाम आर्थिक गतिविधियों में इसका असर दिखा। उद्योग, व्यापार और कृषि की जरूरतों को पूरी करने के लिए रेलवे को भी तेज गति से बढ़ना होगा।

2016 तक हर वर्ष रेल बजट के बाद अखबारों में 'सौगातों' को लेकर विशेष परिशिष्ट छपते थे। रेल बजट में रेल मंत्रालय की मौजूदा वर्ष की कार्य योजनाओं, प्रतिबद्धताओं और उसके प्रदर्शन का लेखा-जोखा होता था। 25 फरवरी 2016 को रेल मंत्री द्वारा अंतिम स्वतंत्र रेल बजट पेश किया गया था। इसके अगले वर्ष पहले संयुक्त बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 'हमने 1924 से चली आ रही औपनिवेशिक परंपरा समाप्त कर दी है। यह निर्णय रेलवे को सरकार की वित्तीय नीति के केंद्र में लाता है।' अब 'रेल बजट' की जगह 'बजट में रेलवे' ने ले ली थी।

रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक माना जा सकता है। इसने रेलवे के वित्त और बुनियादी ढांचा प्रबंधन का तरीका बदला। लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय रेल बजट बुनियादी ढांचा विकास, वित्त प्रबंधन और समन्वित व्यवसाय के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ा।

2014-2024 के दशक में कई अन्य सुधारों के साथ ही वर्षों से उपेक्षित रेलवे बुनियादी ढांचे में सरकारी खजाने से बहुतायत में पैसा दिया गया। 2004-2014 के दशक से 2014-2024 के दशक की तुलना करें तो कोविड के बावजूद रेलवे का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। 2014-24 तक कुल माल ढुलाई लगभग 12600 मिलियन टन रही, जबकि इससे पहले के दशक में यह 8400 मिलियन टन थी। सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची, जबकि पहले 1.56 लाख करोड़ रुपए थी। रेलवे का राजस्व 18.5 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो पहले 8.6 लाख करोड़ रुपए था।

पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी से नई लाइनों, विद्युतीकरण, नए रोलिंग स्टॉक शामिल करने और सुरक्षा कार्यों में उपलब्धियां हासिल हुईं। 2024-25 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आवंटित 11.11 लाख करोड़ रुपए में से रेलवे को 2.52 लाख करोड़ मिले। 2025-26 के बजट में भी इतनी ही राशि मिली। अब भविष्य के आवंटन महज सेक्टर की जरूरतों ही नहीं, आवंटित राशि के उपयोग पर भी निर्भर करेंगे।

यात्री सेवाओं से रेलवे को अपने राजस्व की महज एक-तिहाई आय ही होती है। दो-तिहाई राजस्व माल ढुलाई से आता है। कम दरों पर यात्री सेवा देने से रेलवे को सालाना 60 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान होता है। इसकी भरपाई माल ढुलाई से की जाती है, जिसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। 2024-25 में यात्री सेवाओं से आय के 80 हजार करोड़ रुपए के बजटीय अनुमानों की तुलना में वास्तविक आय 75 हजार करोड़ रुपए ही हुई। माल ढुलाई से भी 1.80 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपए ही मिले।

भारतीय रेलवे आज भी देश की जीवनरेखा है। यह देश को एक करती है। समय आ गया है कि इसे न केवल विश्वस्तरीय रेलवे, बल्कि सुरक्षित, किफायती और दक्षतापूर्ण परिवहन प्रणाली में बदला जाना चाहिए।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यात्री सेवाओं से आय का लक्ष्य 92800 करोड़ रुपए रखा गया है। नवंबर के अंत तक लगभग 52 हजार करोड़ रुपए कमाई हो चुकी। लक्ष्य पाने के लिए रेलवे को दो बार किराया भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन रुझान बताते हैं कि अब भी शायद इतनी कमाई न हो पाए। इसे पाने के लिए पिछले वर्ष की वास्तविक आय से करीब 17 हजार करोड़ रुपए अधिक चाहिए। रेल बजट के मर्जर के बाद आ रहे इस दसवें बजट में रेलवे के भविष्य की स्पष्ट दिशा तय होनी चाहिए। किराए-भाड़े के ढांचे को तर्कसंगत बनाने और वेतन-पेंशन की देनदारियों से निपटने के लिए रेल टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापित करना जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • यह बात समझ लें कि प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें प्रकृति की आवश्यकता है...

धरती को बचाने की नहीं, जीने के तरीके बदलने की जरूरत है

क्लाइमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर
chetanss@gmail.com

पिछले कुछ वर्षों से मैं देशभर में यात्रा करते हुए हजारों लोगों से मिला हूं। पर्यावरण विषय पर लगभग हर शहर, कॉलेज और कार्यक्रम में मुझे एक ही वाक्य दीवारों पर, पोस्टरों पर और भाषणों में दिखाई देता है- पृथ्वी बचाओ या धरती बचाओ। पर जितनी बार मैं यह वाक्य सुनता हूं, उतना ही मुझे लगता है इसमें गहरी भूल है।

यह मान लेना कि मनुष्य धरती को बचा सकता है, हमारे अहंकार का प्रतीक है। चार-साढ़े चार अरब वर्ष पुरानी यह पृथ्वी आग, बर्फ, उल्कापात और कई प्रजातियों की विलुप्ति झेल चुकी है। मनुष्य तो उसके इतिहास में एक बहुत छोटा-सा अध्याय है। हम इस धरती पर एक अणु तक नहीं बना सकते, रेत का कण भी खुद से पैदा नहीं कर सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि हम धरती को बचा सकते हैं। हमें धरती या प्रकृति को नहीं, खुद को बचाने की जरूरत है। प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें प्रकृति की आवश्यकता है। यदि मनुष्य कल समाप्त हो जाएं, तो जंगल लौट आएंगे, नदियां साफ हो जाएंगी, समुद्र अपने आप ठीक हो जाएंगे और जीव-जंतु फिर से फैल जाएंगे। प्रकृति चलती रहेगी। पर यदि धरती पर जलवायु पूरी तरह से बदल जाए, पानी, मिट्टी और हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए, तो मनुष्य प्रजाति नहीं बच सकेगी।

भारतीय दर्शन में यह बात बहुत पहले से कही गई है। पंचतत्व के अनुसार हमारा शरीर भी उसी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है, जिससे प्रकृति बनी है। बाहर की हवा वही है, जो हमारे फेफड़ों में जाती है। बाहर का पानी वही है, जो हमारे शरीर में रक्त और द्रव बनता है। मिट्टी ही भोजन के रूप में हमारे भीतर आती है। हम और प्रकृति अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। जो प्रकृति में है, वही मनुष्य के शरीर में भी है।

लेकिन आधुनिक जीवन में हर काम और हर उपभोग से- चाहे वह वॉट्सएप पर मैसेज भेजना हो, गाड़ी चलाना हो, बिजली का उपयोग हो या कोई सामान खरीदना हो- हम हवा, पानी और मिट्टी को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रदूषित करते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में हम खुद को ही, अपने ही शरीर को दूषित करते हैं। कभी-कभी तो मुझे आधुनिक मनुष्य की समझ पर बड़ा शक होने लगता है। हम उसी हवा को कैसे खराब कर सकते हैं, जिसमें खुद ही श्वास लेना है? उसी पानी को कैसे गंदा कर सकते है, जिसे खुद ही पीना है। क्या मनुष्य सच में ही ईश्वर की बनाई गई सबसे उत्कृष्ट और बुद्धिमान कृति है?

इतिहास हमें जलवायु परिवर्तन के परिणाम का उदाहरण दे चुका है। कभी इस धरती पर डायनोसौर राज करते थे। वे शक्तिशाली थे, हर जगह थे। किंतु जलवायु बदली तो वे विलुप्त हो गए। धरती बची रही। जीवन बचा रहा। केवल वह प्रजाति समाप्त हुई। परंतु उस समय जलवायु परिवर्तन के लिए डायनोसौर स्वयं जिम्मेदार नहीं थे। पर आज का जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक नहीं है। यह मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और वातावरण में कार्बन डाल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम अस्थिर हो रहा है और आपदाएं बढ़ रही हैं। यह इस बात का संकेत नहीं है कि धरती मर रही है। यह इसका संकेत है कि मानव सभ्यता स्वयं को नष्ट कर रही है।

इसलिए अगली बार जब आप धरती बचाओ कहें, तो रुककर सोचिए। धरती को बचाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीने के तरीके को बदलकर खुद को बचाने की जरूरत है। आधुनिक दुनिया एक खतरनाक भ्रम पर टिकी है कि सीमित धरती पर असीमित उपभोग संभव है। जब हमारी आय सीमित होती है तो हमारे खर्चे भी सीमित हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी धरती सीमित है तो हम अपनी जरूरतों को सीमित क्यों नहीं करते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मदर ऑफ ऑल डील्स • लग्जरी कारों से लेकर वाइन तक के लिए भारत ने ईयू के लिए खोला बाजार

भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स-जूलरी के लिए बड़े मौके, चीन, बांग्लादेश को कड़ी चुनौती मिलेगी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारत-ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर मुहर लगा दी है। लग्जरी कारों, वाइन और मशीनरी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है, जिससे भारत में विदेशी लग्जरी कारें और प्रीमियम उत्पाद सस्ते होने वाले हैं। जीटीआरआई के मुताबिक मुख्य रूप उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां टैरिफ ऊंचे थे। सबसे बड़े लाभार्थी रेडीमेड कपड़े (12% टैरिफ), फुटवियर (8-15%), समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, रसायन और मशीनरी होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह समझौता 2030 तक भारत के 9 लाख करोड़ रुपए के कपड़ा निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में गेम-चेंजर साबित होगा। हालांकि इस सौदे को अभी ईयू पार्लियामेंट की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में इस डील को जमीन में उतरने में एक साल या उससे अधिक समय लग सकता है। एक यूरोपीय ऑटो लग्जरी कंपनी के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं, आधिकारिक मंजूरी और व्यापक अमल में लगने वाले समय के कारण, इस एफटीए के 2028 के मध्य तक ही प्रभावी होने की संभावना है। यूरो की तुलना में रुपए में गिरावट डील के असर को कम कर सकती है।

2030 तक 9 लाख करोड़ के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य हासिल हो सकता है

टेक्सटाइल: यूरोपीय बाजार में चीन, बांग्लादेश का शेयर 50%+, अब भारत इन्हें चुनौती दे सकेगा

8.71 लाख करोड़ रुपए के यूरोपीय बाजार में भारतीय निर्यातकों को 'जीरो-ड्यूटी' एंट्री मिलेगी। जिसमें भारत का शेयर महज 6% यानी 50,424 करोड़ रु. है।

अभी बांग्लादेश, वियतनाम को शुल्क-मुक्त पहुंच का लाभ मिलता था। यह डील भारतीय निर्यातकों को उनके बराबर खड़ा कर देगा।

भारतीय निर्माता 8-12% के टैरिफ घाटे से मुक्त होंगे। इससे चीन, बांग्लादेश की 50% हिस्सेदारी वाले बाजार में भारत के लिए विस्तार की बड़ी गुंजाइश है।

अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक संकट में थे। अकेले तिरुपुर के निटवेअर हब को 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

लाखों नौकरियों पर मंडरा रहा संकट इस डील से काफी हद तक कम हो सकता है। 5 वर्षों में ईयू को निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है।

जेम्स एंड जूलरी: 27 देशों के 1.56 लाख करोड़ के बाजार में पहुंच, यूएस टैरिफ की भरपाई संभव

जारी टैरिफ से भारत को 1.56 लाख करोड़ रुपए के यूरोपीय जेम्स एंड जूलरी बाजार में मौका मिलेगा, जहां फिलहाल चीन, थाईलैंड और हॉन्गकॉन्ग का दबदबा है।

इस डील का उद्देश्य 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 91.6 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचना है।

अमेरिकी बाजार में ऊंचे टैक्स के कारण भारत के निर्यात में 44% की भारी गिरावट आई थी; यह डील उस नुकसान की भरपाई करेगी।

सूरत, जयपुर, मुंबई और कोलकाता जैसे जूलरी हब में मैन्युफैक्चरिंग और शिपमेंट में तेजी आएगी। नए रोजगार पैदा होंगे।

यूरोपीय संघ से आने वाले मोतियों और कीमती पत्थरों पर भारत 22.5% तक टैरिफ खत्म करेगा, जिससे ज्वेलरी बनाना सस्ता होगा।

सस्ती होंगी कारें... 15 लाख की आयातित कार 31.5 लाख की जगह 25 लाख की पड़ेगी

- इस डील से भारतीय बाजार में बीएमडब्ल्यू, लैंबर्गिनी, पोर्श और ऑडी जैसी प्रीमियम लग्जरी यूरोपीय कारें सस्ती होने वाली हैं। अगले साल से लागू होने वाले इस समझौते के तहत भारत कोटा-आधारित आयात शुल्क में रियायतें देगा।
- यूरोपीय संघ भारतीय ऑटोमोबाइल के लिए चरणबद्ध तरीके से शुल्क समाप्त करेगा, जबकि भारत कारों की एक कोटा के लिए आयात शुल्क घटाकर 10% करेगा। लैंबर्गिनी जैसी कंपनियों को लाभ होगा, जो कारें आयात करती हैं।
- समझौते के तहत यूरोपीय संघ 25 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों का निर्यात भारत को नहीं करेगा। वे इन्हें भारत में बना सकते हैं, लेकिन निर्यात नहीं कर पाएंगे।
- भारत में आयातित लग्जरी कारों पर 70% से 110% तक सीमा शुल्क लगता है। इस समझौते के तहत 15 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारें ही इस रियायती कोटे में आएंगी। पोर्ट पर पहुंचने के बाद कीमत 25 लाख या अधिक होगी। अब तक 31.5 लाख की पड़ती है।

भास्कर एक्सपर्ट

अजय श्रीवास्तव
फाउंडर, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव, जीटीआरआई

यूरोपीय 'कार्बन टैक्स' पर से अनिश्चितता हटना जरूरी

भारत और यूरोप के बीच यह समझौता व्यापार के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि इससे दुनिया के सबसे अमीर देशों के बाजार हमारे लिए खुल जाएंगे। भारत 97% आयात पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसे 7-10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वाइन पर शुल्क 150% से घटकर 20-30%, स्पिरिट पर 40%, बीयर पर 110% से 50% और कारों पर 100-125% से घटकर 10% रह जाएगा। भारत भेड़ के मांस, फलों के रस, चॉकलेट और पेट फूड जैसे कई कृषि-खाद्य उत्पादों पर भी 'जीरो टैरिफ' की ओर बढ़ेगा। हालांकि, समझौते का प्रभाव इस बात से सीमित है कि इसमें क्या अनसुलझा रह गया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का सौदे से बाहर रहना असंतुलन पैदा करता है, जो टैरिफ से मिलने वाले लाभों को धीरे-धीरे खत्म कर सकता है। इस को टैरिफ कटौती के एक मजबूत समझौते के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में विनियामक और जलवायु मुद्दों को कितनी सार्थकता से सुलझाया जाता है।

वाहनों पर टैक्स में कटौती और स्पेयर पार्ट्स का उदारीकरण ऑटो उद्योग के लिए गेमचेंजर साबित होगा। लेटेस्ट मॉडल जल्द मिलेंगे। मर्सिडीज-बेंज भारत में निर्माण जारी रखेगी।
- संतोष अय्यर, इंडिया हेड, मर्सिडीज-बेंज

ऑटो सेक्टर में नवाचार, सप्लाई चेन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कीमतों और बाजार पर असर का सटीक अंदाजा अंतिम शर्तें स्पष्ट होने के बाद लगाया जा सकेगा।
-बलबीर सिंह ढिल्लन, ब्रांड डायरेक्टर, ऑडी इंडिया

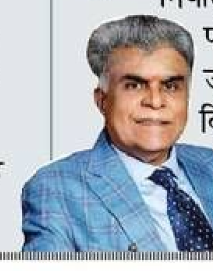

एफटीए लागू होने के बाद भारतीय परिधान निर्यात में साल-दर-साल 20-25 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जबकि वर्तमान में ईयू बाजार में यह विकास दर मात्र 3 फीसदी है।
-ए. शक्तिवेल, चेयरमैन, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

व्यापार और निवेश के अवसर खुलेंगे। डील टेक्सटाइल, ऑटो जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच, सुरक्षा कवच का काम करेगी।
-रजनी सिन्हा, चीफ इकोनॉमिस्ट, केयरएज रेटिंग्स

शेयर बाजार • एफटीए पर सकारात्मक प्रतिक्रिया

टेक्सटाइल शेयर 12% तक उछले, ऑटो में 4% गिरावट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मंगलवार को शेयर बाजार ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे घरेलू उद्योगों को इस समझौते से प्रमुख रूप से फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने थोड़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। शेयर बाजार दिन की शुरुआत में दबाव में थे, लेकिन आखिरी घंटे में आई मजबूत खरीदारी ने उन्हें दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा दिया। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 319.77 अंकों की बढ़त के साथ 81,857.48 पर बंद हुआ। निफ्टी 126.75 अंक चढ़कर 25,175.40 पर बंद हुआ। ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। लाभ वाले शेयरों में अदाणी एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदाणी पोर्ट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज शामिल थे। एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, नुकसान वाले शेयरों में शामिल थे।

इन शेयरों में दिखी भारी उछाल

ईयू से डील के बाद केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग, नितिन स्पिनर्स, बॉम्बे डाइंग जैसे टेक्सटाइल शेयरों में भारी उछाल आया। क्योंकि इस डील से निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। कारोबार के दौरान कई शेयर 12% तक उछले, 7% तक ऊपर बंद हुए।

शेयर	प्राइस	उछाल
केपीआर मिल्स	908.00	6.92%
नितिन स्पिनर्स	334.85	5.45%
वेलस्पन लिविंग	125.85	4.22%
बॉम्बे डाइंग	116.45	4.58%
ग्रासिम इंडस्ट्रीज	2,856.65	3.49%

फेड के फैसले और बजट पर नजर

मासिक एक्सपायरी के दिन घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। टैरिफ को लेकर नई चिंताओं का असर बाजार पर था, लेकिन भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की उम्मीद ने बाजार को सहारा दिया। अब घरेलू निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी फैसले और भारत के केंद्रीय बजट पर टिकी है।
- विनोद नायर, रिसर्च हेड, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स

फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल, आभूषण जैसे सेक्टर को लाभ की उम्मीद

क्षेत्र	प्रमुख कंपनियां	लाभ का कारण
कपड़ा और परिधान	किटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल्स, गो फैशन, इंडो काउंट, वेलस्पन,	यूरोपीय बाजार में 12% टैरिफ खत्म होने से वियतनाम और बांग्लादेश के साथ सीधा मुकाबला कर सकेंगी।
फार्मास्यूटिकल्स	डॉ. रेड्डीज, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला	रेगुलेटरी बाधाएं कम होने और यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच से जेनेरिक दवाओं का निर्यात बढ़ेगा।
केमिकल	एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोरीन, आरती इंडस्ट्रीज	यूरोप के साथ सप्लाई चेन का एकीकरण और कम आयात-निर्यात शुल्क।
समुद्री उत्पाद	अपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स	झींगा और अन्य समुद्री उत्पादों पर लगने वाला 26% तक का भारी शुल्क खत्म होगा।
रत्न और आभूषण	टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट्स	7 लाख करोड़ रु. के यूरोपीय प्रीमियम मार्केट में 100% शुल्क-मुक्त पहुंच।

तिमाही नतीजे

पीसी ज्वेलर का मुनाफा 28% बढ़कर 190 करोड़

मुंबई | प्रमुख ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 28% बढ़कर 190.10 करोड़ रु. हो गया। कंपनी की कुल आय भी 683.44 करोड़ रु. से 31.8% बढ़कर 900.51 करोड़ रु. पर पहुंच गई। कंपनी के एमडी बलराम गर्ग के मुताबिक मुनाफा बढ़ने की वजह दिवाली और शादी सीजन में जबरदस्त खरीदारी रही।

एशियन पेंट्स: मुनाफा 1074 करोड़, 4.8% घटा

मुंबई | एशियन पेंट्स का अक्टूबर-दिसंबर 2025 में मुनाफा 4.8% घटकर 1,073.9 करोड़ रुपए रह गया। यह एक साल पहले समान तिमाही में 1128.4 करोड़ रुपए था। कंपनी ने मुनाफा घटने के लिए नए लेबर कोड के तहत ग्रैच्युटी देनदारी बढ़ने और व्हाइट टीक के अधिग्रहण में हुए नुकसान को बड़ी वजह बताया है।

टाटा कंज्यूमर का लाभ 384 करोड़ रुपए हुआ

मुंबई | टाटा ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 36.4% बढ़कर 384.52 करोड़ रु. पर पहुंच गया। एक साल पहले यह 282 करोड़ था। मुनाफे में वृद्धि की मुख्य वजह घरेलू बाजार में बिक्री (वॉल्यूम) 15% बढ़ना है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 15% बढ़कर 5,112 करोड़ रुपए पर पहुंच गई।

क्विक कॉमर्स • पहली बार एमसीपी तकनीक

स्विगी ने एआई से जोड़ा प्लेटफॉर्म; अब बिना एप खोले ही होगा ऑर्डर

उदिशा श्रीवास्तव | नई दिल्ली

फूड और ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म स्विगी के ग्राहक चैटजीपीटी, क्लॉड और गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स के जरिये सीधे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (एमसीपी) इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। इंस्टामार्ट वैश्विक स्तर पर एमसीपी अपनाने वाला पहला क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, जो उपयोगकर्ताओं को सरल, स्वाभाविक भाषा संकेतों का उपयोग करके 40,000 से अधिक एसकेयू के वर्गीकरण से ब्राउज और खरीदारी की अनुमति देता है।

कैसे करें इस्तेमाल: आप चेटजीपीटी या जैमिनी जैसे टूल पर जाकर बस अपनी जरूरत लिखें। जैसे कल की क्रिकेट मैच पार्टी के लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दो। एआई स्विगी की लिस्ट चेक करेगा और आपके लिए बेस्ट कॉम्बो चुनकर ऑर्डर फाइनल कर देगा।

क्या होगी सहूलियत: एआई खुद ही कूपन कोड लगाकर आपको सबसे सस्ता विकल्प बताएगा और डिलीवरी ट्रैक करने में मदद करेगा।

टेक्नोलॉजी: यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह काम

स्विगी ने जिस एमसीपी तकनीक का इस्तेमाल किया है, वह यूएसबी-सी पोर्ट की तरह काम करती है। यह अलग-अलग एआई टूल्स को स्विगी के सॉफ्टवेयर से सीधे जोड़ देती है। इससे एआई एजेंट यूजर की बात समझकर तुरंत टास्क पूरा करते हैं।

ईवी • यूरोप में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की कुल हिस्सेदारी अब 67%

यूरोप: पहली बार पेट्रोल से ज्यादा बिकीं ई-कारें, पर टेस्ला की बिक्री 20% घटी

एजेंसी | लंदन

यूरोपियन यूनियन में पहली बार इलेक्ट्रिक कारों ने पेट्रोल कारों को पछाड़ दिया है। दिसंबर 2025 में 2.17 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जबकि पेट्रोल कारों का आंकड़ा 2.16 लाख पर सिमट गया। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की कुल हिस्सेदारी अब 67% पहुंच गई है, जो साल भर पहले 57.8% थी। यह बदलाव तब आया है जब सरकारें उत्सर्जन नियमों में ढील देने की तैयारी में हैं। बाजार में अब टेस्ला पिछड़ रही है। चीन की बीवाईडी और यूरोप की फॉक्सवैगन तेजी से कब्जा जमा रही हैं। जानकारों का दावा है कि नियमों में ढील के बावजूद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज कम होने के आसार नहीं हैं।

चीनी कंपनी का दबदबा... बीवाईडी की 229% बढ़ी

यूरोपीय बाजारों में दिसंबर 2025 में टेस्ला का रजिस्ट्रेशन 20.2% घट गया। इसके उलट चीन की बीवाईडी की बिक्री 229.7% बढ़ी। फॉक्सवैगन ने 10.2% और स्टेलेंटिस ने 4.5% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि रेनॉ की बिक्री में 2.2% की गिरावट आई। अब बाजार में चीनी और यूरोपीय कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

5 साल का रिकॉर्ड: 2025 में 1.33 करोड़ कारें बिकीं

यूरोप में कारों की बिक्री पटरी पर लौट रही है। लगातार छठे महीने कारों की बिक्री बढ़ी है। साल 2025 में कुल 1.33 करोड़ कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है, हालांकि यह कोविड से पहले के स्तर से अब भी कम है।

भारत: 2025 में ई-कार की बिक्री 77% बढ़ गई

ऑटो डीलरों के संगठन फाडा के मुताबिक, 2025 में देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 77.04% बढ़कर 1,76,817 हो गई। दिसंबर 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 3.94% पर पहुंच गई जो दिसंबर 2024 में 3.09% थी।

बिजनेस डील • कोर बिजनेस पर फोकस बढ़ेगा

पीवीआर आइनॉक्स ने 227 करोड़ में मैरिको को बेचा स्नैकिंग ब्रांड

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर पीवीआर आइनॉक्स ने प्रीमियम स्नैकिंग ब्रांड 4700 बीसी (गॉरमे पॉपकॉर्न) की निर्माता कंपनी जिया मेज प्रा.लि. में अपनी पूरी हिस्सेदारी मैरिको को करीब 227 करोड़ रुपए में बेच दी है। हालांकि पीवीआर आइनॉक्स के सभी सिनेमाघरों में 4700बीसी उत्पादों की बिक्री जारी रहेगी। इस पॉपकॉर्न ब्रांड ने बीते वित्त वर्ष करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की। ये ब्रांड सालाना 31-35% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मुनाफे में नहीं आ पाया है।

भास्कर नॉलेज

पीवीआर ने ब्रांड क्यों बेचा?

एलारा कैपिटल के एक्जीक्यूटिव वीसी करण तौरानी के मुताबिक पीवीआर आइनॉक्स ने 4700 बीसी को नॉन-कोर एसेट मानते हुए बेचा है, ताकि फोकस कोर सिनेमा बिजनेस पर रहे और बैलेंस शीट मजबूत हो। इसका पीवीआर आइनॉक्स की कुल आय में केवल 2% योगदान था। इस डील से पीवीआर को करीब 600 करोड़ का कर्ज घटाने और शून्य कर्ज का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

ट्रेंड • जीएसटी छूट से त्योहारों के दौरान बढ़ा खर्च

अप्रैल-दिसंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च 13.6% बढ़कर 17.65 लाख करोड़

आतिरा वारियर | मुंबई

भारतीयों की खर्च करने की आदतों में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब लोग खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च 13.57% बढ़कर 17.65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 15.54 लाख करोड़ रुपए था। अकेले दिसंबर 2025 में ही लोगों ने 2.05 लाख करोड़ रुपए स्वाइप किए। यह साल 2025 में चौथा ऐसा मौका था जब मासिक खर्च 2 लाख करोड़ के पार गया।

वृद्धि: 2025 में जुड़े 77 लाख नए क्रेडिट कार्ड

देश में क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या 7.13% बढ़कर 11.57 करोड़ के पार पहुंच गई। दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 10.80 करोड़ था। यानी 2025 में कुल 77 लाख नए कार्ड सिस्टम में जुड़े। एचडीएफसी बैंक 2.57 करोड़ कार्ड्स के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है।

वेदांता, हिंदुस्तान जिंक में 1.59% हिस्सेदारी बेचेगी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

वेदांता ने मंगलवार को एक ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक (एचजेडएल) के 6.7 करोड़ इक्विटी शेयरों तक की बिक्री को मंजूरी दे दी। ओएफएस में 0.79% की आधार हिस्सेदारी शामिल है। ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, तो अतिरिक्त 0.79% हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिससे कुल बिक्री 1.59% हो जाएगी। फ्लोर प्राइस 685 रु. प्रति शेयर तय किया गया है। ये मंगलवार को बीएसई पर बंद भाव 726.6 रुपए से 5.8% डिस्काउंट है।

ब्याज दरों में 0.25% कटौती और हो सकती है: रिपोर्ट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आरबीआई 6 फरवरी को रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। विकास संबंधी अनिश्चितताओं और कम महंगाई के बीच ब्याज दर में कटौती के प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस कदम के साथ पर्याप्त लिक्विडिटी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, 'ग्रोथ आउटलुक में अनिश्चितता है और आरबीआई रेपो रेट को 5.25% तक लाने के लिए नीतिगत गुंजाइश का उपयोग कर सकता है।'

वोडा-आइडिया का घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रुपए

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया का दिसंबर तिमाही में घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रु. रहा। घाटे में कमी ग्राहकों द्वारा सर्विस अपग्रेड करने, महंगे पैक चुनने से आई। प्रति यूजर कमाई 173 से 7.5% बढ़ाकर 186 रुपए हो गई। आय मामूली बढ़त के साथ 11,323 करोड़ रुपए रही। कंपनी का कुल यूजर बेस 3.4% घटकर 19.29 करोड़ रह गया। पोस्टपेड ग्राहक 14% बढ़कर 2.9 करोड़ हो गए। प्रति यूजर डेटा खपत 15 जीबी से 19.2 जीबी प्रति माह हो गई।

ऑस्ट्रिया की कंपनी कॉफीशॉप भारत में 100 स्टोर खोलेगी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

ऑस्ट्रिया की प्रीमियम कैफे चेन कॉफीशॉप कंपनी भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने 2029 तक देश में 100 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल स्टोर्स की संख्या के लिहाज से रूस इसका सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन कंपनी का मानना है कि भारत जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगा। भारत में प्रति व्यक्ति कॉफी खपत अभी कम है, लेकिन इसमें तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। शहरी युवाओं के बीच कैफे जाना अब आदत बनता जा रहा है।

बिजनेस एंकर चीन में ऑफिस में बढ़ते हुए वर्कलोड का प्रतीक बन रहा है उदास घोड़ा

गलती से बना रोते हुए घोड़े का खिलौना अब बेस्टसेलर; इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहे लोग, कई देशों से आ रही मांग

एजेंसी | बीजिंग

चीन के सबसे बड़े थोक बाजार, यिवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में, चंद्र नव वर्ष से पहले ग्राहक एक छोटी सी दुकान में उमड़ रहे हैं। इन ग्राहकों को एक लाल रंग के सॉफ्ट टॉय घोड़े (क्राइंग हॉर्स) की तलाश है। ऐसा घोड़ा जिसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ हो, यानी हंसने के बजाय रोता हुआ दिखता हो, गले में सोने की घंटी हो और आंखें देखने वाले की निगाहों से शरमाती हुई प्रतीत हों। चीनी राशि चक्र में घोड़े का वर्ष 17 फरवरी, 2026 से 5 फरवरी, 2027 तक चलेगा। इस नव वर्ष से पहले बाजार में घोड़े की मूर्तियां और खिलौने जमकर बिक रहे हैं। इस बीच उदास भाव वाला ये घोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे खरीदने उमड़ पड़े। लगभग 25 चीनी युआन (करीब 330 रुपए) की किफायती कीमत ने इसकी बिक्री बढ़ाने में मदद की। लेकिन ये उदास भाव वाला घोड़ा जानबूझकर नहीं, बल्कि गलती से बन गया था। यिवू स्थित हैप्पी सिस्टर नामक दुकान की मालिक झांग हुओकिंग के मुताबिक एक कर्मचारी ने घोड़े पर मुस्कान को उल्टा सिल दिया था। गलती पता चलने पर उन्होंने ग्राहक को पैसे लौटाने की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने खिलौना वापस नहीं किया। बाद में उन्हें पता चला कि खिलौने की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। अब झांग के पास चीन के अलावा अन्य देशों से भी उदास घोड़े की डिमांड आ रही है। घोड़े के उदास भाव चीन के युवा श्रमिकों को काफी अपनापन महसूस करा रहे हैं। रोता हुआ घोड़ा अपनी कमजोरियां स्वीकार करने का प्रतीक बन गया। तुआन मामी नामक एक खरीदार ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह छोटा घोड़ा इतना उदास और दयनीय लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे काम पर महसूस होता है।' एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा कौन है जिसके जीवन में ऐसे पल नहीं आए हों जब रोने का मन करता हो लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ता हो?'

क्राइंग हॉर्स, लाबूबू जैसे अगली क्यूट खिलौनों का चलन बढ़ रहा

मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक नए तरह का चलन है। लाबूबू, जेलीकैट्स, और क्रायबेबी के बाद क्राइंग हॉर्स का वायरल होना नई पीढ़ी के बीच बढ़ती 'अगली-क्यूट' (बदसूरत मगर प्यारे) पसंद की वजह से है। इसके अलावा ये सॉफ्ट टॉयज अपनी अनोखी-अजीब शक्ल और भावनात्मक जुड़ाव के कारण जेन जी और मिलेनियल्स के बीच फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं।

फायदा • आम लोगों के लिए हवाई सफर आसान और सस्ता होगा

अदाणी डिफेंस और ब्राजील की कंपनी भारत में विमान असेंबली यूनिट लगाएंगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और ब्राजील की कंपनी एंब्रायर मिलकर भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम तैयार करेंगे। मंगलवार को दोनों कंपनियों के बीच इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी के तहत दोनों कम्पनियां विमान निर्माण, सप्लाई चेन, आफ्टरमार्केट सेवाओं और पायलट प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगी। इसके तहत देश के रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (आरटीए) प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। देश में एंब्रायर के क्षेत्रीय विमानों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) भी स्थापित की जाएगी। हालांकि अभी निवेश की रकम और प्लांट की जगह का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन अगले कुछ महीनों में इस पर फैसला होने की उम्मीद है। इस साझेदारी से देश के टियर टू और टियर थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। इससे आम लोगों के लिए हवाई सफर आसान और सस्ता होगा। प्रस्तावित इकोसिस्टम से इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सर्विसेस में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

देश में रीजनल एविएशन इकोसिस्टम जरूरी

रीजनल एविएशन देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। उड़ान जैसी योजनाओं ने टियर-2 और 3 शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी मजबूत की है। ऐसे में देश में एक स्वदेशी रीजनल एविएशन इकोसिस्टम की जरूरत बढ़ गई है। **– जीत अदाणी,** डायरेक्टर अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस

Last Day To Join Private Channel.
Closing entry for new members Now

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times

And more Newspapers

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International

[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + International Editorials]

Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees 📍

Trust me... this will be your best purchase of 2025